पंचायत (अनुसुचित क्षेत्रावर विस्तारीत) कायदा 1996

सदरची माहीती PESA (PANCHAYAT EXTENTION TO SCHEDULED AREA- ACT- 1996) संबंधी जनतेमध्ये जाणिव जागृती निर्माण व्हावी या उद्देशाने या संकेतस्थळावर अपलोड केलेली आहे. सदरची माहिती ही पेसा कामकाजासंबंधीत असून शासनाच्या संबंधित विभागांकडून त्यामध्ये वेळोवेळी शासन निर्णयात बदल होत असतात. यास्तव अद्ययावत शासन निर्णयासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या Maharashtra.gov.in या संकेतस्थळाचा वापर करावा.

रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 521] नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 2, 1985/अग्रहायण 11, 1907
No. 521] NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 2, 1985/AGRAHAYANA 11, 1907

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 दिसम्बर, 1985

*सा.का.नि. 876(अ) :—राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है ।

"सं. आ. 123"

अनुसूचित क्षेत्र (महाराष्ट्र), आदेश 1985

राष्ट्रपति, भारत के संविधान की पांचवीं अनुसूची के पैरा 6 के उपपैरा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अनुसूचित क्षेत्र (भाग क राज्य) आदेश, 1950 और अनुसूचित क्षेत्र (भाग ख राज्य) आदेश, 1950 को, जहां तक वे महाराष्ट्र राज्य में अब समाविष्ट क्षेत्रों से संबंधित हैं, विखंडित करते हैं और उस राज्य के राज्यपाल से परामर्श करके, निम्नलिखित आदेश करते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम अनुसूचित क्षेत्र (महाराष्ट्र) आदेश, 1985 है ।

(2) यह तुरंत प्रवृत्त होगा ।

2. नीचे विनिर्दिष्ट क्षेत्र महाराष्ट्र राज्य के भीतर अनुसूचित क्षेत्र के रूप में पुनः परिनिश्चित किए जाते हैं :—

1. थाना जिला में निम्नलिखित :—(क) दहानू, तलासे, मोखाडा, जौहर, वाडा और शाहपुर तहसील;

(ख) (i) पालघर तहसील के नीचे उल्लिखित एक सौ चौंवालीस गांव :—

पालघर तहसील :—(1) तारापुर, (2) कुडन, (3) दहीसर-तर्फ-तारापुर, (4) घिवाली, (5) दाबे, (6) अक्करपट्टी, (7) कुरगांव, (8) परनाली, (9) वेंगनी, (10) पाथरवाली, (11) नेवले, (12) शिगांव, (13) गरगांव, (14) चिचारे, (15) अकेगौहन, (16) नानीवाली, (17) अम्बेडे, (18) बरहानपुर, (19) सलगांव, (20) कुडन, (21) [illegible], (22) नवटे, (23) आकोली, (24) अशेरी, (25) सोमाटे, (26) पश्याल, (27) बोइसार, (28) बोमेटी, (29) महागांव, (30) किराते (31) वाडे, (32) खडकवाने, (33) मेंढवान, (34) चिल्हेर (35) कोंडगांव (36) करसूद, (37) बेटेगांव, (38) वारंगडे (39) नालोंडे (40) घनेडे, (41) कम्बलगांव, (42) मान (43) हानेघर (44) वेदे, (45) चारी बुदरूक, (46) बिरवाडी (47) कल्लाले (48) पड़घे, (49) पोले, (50) नन्दोरे (51) गिरनाली (52) बोरांडे, (53) देवखोपे

(54) मगावे, (55) कोसवाड, (56) कोकानेर, (57) नगजारी, (58) चारी खुर्द, (59) वेलगांव, (60) खुटल, (61) चिल्हर, (62) मोपोली (63) नीहे, (64) दामखंड, (65) कोंधान, (66) अवधान (67) बंगरचोले, (68) शील, (69) लौवारे, (70) वंधन (71) नंदगांव अर्क मनोर, (72) शीलशेट, (73) कटाले, (74) अंमन, (75) वासारोली, (76) खरसेट, (77) मनोर, (78) टकवा-हल, (79) सावरखंड, (80) नालशेट, (81) केव, (82) वकाडी (83) मंसवान, (84) वंडीवाली, (85) नेटाली, (86) साये, (87) नेन, (88) करलगांव (89) गौवाडे, (90) तमसाई (91) दुखेस, (92) दुखतान, (93) पोचाडे, (94) हालोली, (95) खामलोली, (96) बहाडोली, (97) बोट, (98) एम्बुर इराम्बी (99) दानिसार टर्फ मनोर, (100) कुडे, (101) गुंडांवे (102) सतीवाली, (103) वेहालोली, (104) सवारे, (105) वराई, (106) जन्माई, (107) खेरे, (108) ढेकाले, (109) गंजे, (110) जयसेट, (111) शेलवाडे, (112) वियुर, (113) अम्बाडी, (114) नवाली, (115) मोरावरी, (116) वरकुंठी, (117) कमारे, (118) टोकराले, (119) बंडाते, (120) जंजारोली (121) चहाडे. (112) वसारे, (123) खाडकोली, (124) सखारे, (125) रोठे, (126) लालथाने, (127) नवांजे, (128) तंडुलवाडी, (129) गिराले, (130) परगांव, (131) नगावे टर्फ मनोर, (132) उम्बरपाडानंडाडे, (133) उछावली, (134) सफाले (135) सोनावे, (136) मकाने कप्से, (137) करवाले, (138) वाधिव सरावाली, (139) पेनांड, (140) कंडरवान, (141) दहीवाडे, (142) दरशेट, (143) नवघर (घतीम), (144) उम्बर पडा टर्फ मनोर;

(ii) वसई (वस्सई) तहसील के नीचे उल्लिखित पैंतालीस गांव :—

वसाई (वस्साई) तहसील :—(1) दहीसर, (2) कोशिम्बे, (3) तुलींज, (4) मकवार, (5) त्रिमाने, (6) हेडावाडे (7) कशीदकोपर, (8) खानीवाडे, (9) भालीवाली, (10) कवहेर, (11) शिरसाड, (12) मांडवी, (13) चांदीप (14) भटाने, (15) शिवनसाई, (16) उसगांव, (17) मेडे (18) वाढघर, (19) मीनार, (20) अम्बोडे (21) कलभोन, (22) अडने, (23) सायावान, (24) परोल, (25) शिरवाली, (26) मजीवाली, (27) करतजोन, (28) तिलहर, (29) धानिव, (30) पेलहार (31) आचोले, (32) वालिव, (33) (33) सतीवाली (34) राजावाली, (35) कोल्ही, (36) चिचोटी, (37) जुचन्द्र, (38) वापने, (39) देवदल, (40) कमान, (41) सरजामोरी, (42) पोमन, (43) शिलोट्टार, (44) ससुनवघर (45) नागले;

(iii) भिवंडी तहसील के नीचे उल्लिखित बहत्तर गांव :—

(iii) भिवंडी तहसील : (1) भीवाली, (2) गणेशपुरी, (3) बडावाली वज्रेश्वरी, (4) अकलोली, (5) सवरोली, (6) खातीवाली, (7) उस गांव, (8) घोटगांव, (9) वेडे, (10) वरेठ, (11) चाने, (12) असनोलीन्ताफ डुगड, (13) डुगड, (14) मनीवाली, (15) वडवाली-तार्फ डुगड, (16) मालबोडी, (17) मोहीली, (18) नन्दी-थाने, (19) देपोली, (20) सखरोली, (21) सुपेगांव, (22) पिलांजे खुर्द, (23) पिलांजे बुदरुक, (24) अलखीवाली, (25) विधीवाले (26) देवचोले, (27) मागांव, (28) इकमाल, (29) चिनावली-तार्फ-कुंडे, (30) [illegible] वापे, (32) घाढाने, (33) कुंडे, (34) घोटावाडे (35) मैंडे (36) करमाले (37) कंडाली बुदरुक, (38) केल्हे, (39) काडली खुर्दे (40) दिखाशी, (41) नेवाडे, (42) अम्बाडी, (43) दलोंडे (44) अम्भीवाली-टर्फ-खम्बाले, (45) उम्बरखंड, (46) आखिवली (47) जिदके, (48) खड़ीवाली, (49) बसे, (50) गीडाडे, (51) पहारे, (52) शेडगांव, (53) पच्छपुर, (54) गोंद्रावली, (55) जम्मीवाली-टर्फ-कुंडे (56) असनोली-टर्फ-कुंडे, (57) शिरोले, (58) दभड़ (81). (59) मोहोन्डुल, (60) शिरगांव, (61) पिपल शेठ मुशेठ, (62) खडकी खुर्द (63) खडकी बुदरुक, (64) चिबीपाडे (65) कुहे, (66) धामने, (67) लखी वाली, (68) पलीवाली, (69) पाये, (70) गाने, (71) दहयाले, (72) फिरंग-पाडा ।

(iv) मुर्बाद तहसील के नीचे उल्लिखित सतहत्तर गांव :—

मुर्बाद तहसील :—(1) कसगांव, (2) किसाल, (3) वाडावाली, (4) सखारे, (5) खुटलबोरगांव, (6) अम्बेले खुर्द, (7) सयाले, (8) इंडे, (9) खेडाले (10) तलवालीं-तर्फ-घोरट, (11) इकलहरे, (12) चाफे-तार्फ-खेडुल, (13) पिपलघर (14) दहीगांव (73), (15) परट्टे, (16) कंडाली, (17) धसाई, (18) अलयानी, (19) पालू, (20) देवधर, (21) मड़ (22) सोनावाले, (23) वेलुक, (24) अलावे, (25) बरसुगे, (26) मन्दूस, (27) खेड़, (28) वनोटे, (29) शाई, (30) शेलगांव, (31) शिरोशी, (32) तेलेगांव, (33) फंगाकोशी, (34) मेरडी, (35) वल्हीवाडे, (36) माल, (37) जदाई, (38) अम्श्रीवाली, (39) दिघेफाल, (40) दिवानपाडा (41) खोचर खुर्द, (42) खोचर बुदरुक (43) चोसोले, (44) खुटल बंगला, (45) नाहाडी, (46) मोरोशी, (47) फंगुलगोहन (48) सवरेन, (49) पिटावी-टर्फ-खरे, (50) खुदशेट, (51) फंगाने, (52) खापरी, (53) ढेडावली, (54) करचोंडे, (55) जडघर, (56) उडल दोहा (57) महोरांन्डे, (58) टोकावाडे, (59) बलेगांव, (60) तालावाली (वड़ागांव), (61) वाईशाखारे, (62) मानीवाली-टर्फ-खेडुल, (63) पेनारी, (64) उमरोली बुडरुक, (65) ओजीवाले, (66) मंडवाट, (67) महाज, (68) पाडले, (69) कोलोशी, (70) जयगांव, (71) कलामवाड (भोंडीवले), (72) खेवारे (73) दूधनोली, (74) अमरोली खुर्द, (75) खोपीवली, (76) मिलेट्ट, (77) गोरा-खगड ।

2. नाशिक जिले में निम्नलिखित:—

(क) पेण्ट, सुरगांना और कलवान की तहसीलें;

(ख) (1) डिन्डोरी तहसील के नीचे उल्लिखित एक सौ छह गांव;

डिनडोरी तहसील:—(1) मोखानल, (2) भानवाड़ (3) डेहारे, (4) करणजाली, (5) मनडोले, (6) पलासविहिर, (7) वारे, (8) वनजोले, (9) अमवाड़, (10) वनारे, (11) टिटवे, (12) देवथान (13) नानाशी, (14) चारोज, (15) देवघर (16) काउडासर, (17) वाणी खुर्द, (18) पिम्पलगांव धूम, (19) जोरन, (20) माहाजे, (21) सदराले, (22) नालवाड़ी, (23) ओजे (24) गोलशी, (25) जलखेड़ (26) नीलडोल, (27) कोकनगांव बुडरुक, (28) उमबड़ाले खुर्द, (29) अमबिगन, (30) वाचादगांव, (31) वाघाड़, (32) पोफल वाड़े, (33) धाउर, (34) उमबाले बुडरुक, (35) जाम्बुटके, (36) पिम्पराज, (37) नाले गांव, (38) विलबांड़ी, (39) रासेगांव, (40) कोछरगांव, (41) तिलहोली, (42) रावलगांव, (43) डेहरवाड़ी, (44) ठागुर, (45) देवसाने (46) सारसले, (47) करणजखड़, (48) पिंगलवाड़ी, (49) एकलाहारे, (50) चाउसाले, (51) पिम्परी आंचला, (52) अहीवातवाड़ी, (53) गोल्डारी, (54) हस्ते, (55) कोल्हर, (56) जीरवाड़े, (57) चामडारी, (58) माले दुमाला, (59) मन्डने, (60) कोशीम्बे, (61) पुणेगांव, (62) पान्डन, (63) अम्बनेर, (64) चंडिकापुर (65), भाटोडे, (66) दाहीवी, (67) मुलाने, (68) कोकणगांव खुर्द, (69) माले गांव (70) पिम्पारखेड़, (71), फोपासी, (72) वाणी कामवे, (73) संगममरे, (74) खेडले, (75) मावाडवे (76) करणजवान, (77) डाहेगांव, (78) वागलुड, (79) कृष्णगांव (80) वारखेड़ (81) काड़वाम्हालुंगी, (82) गोंडेगांव, (83) हटनोरे (84) नीलवांड़ी (85) पिम्पलगांव केतकी, (86) राजापुर, (87) डिजडोरी (88) जोपुल, (89) मड़की जाम्ब, (90) पालखेड़, (91) इन्दौर (92) कोग्हाटे, (93) चीन्चखेड़ (94) वेलगांव डिन्डोरी (95) अकराले, (96) भोहाड़ी, (98) पिम्पमालानारे, (98) खाटवाड़ (99) गमसेज, (100) अम्बे डिन्डोरी, (101) दावकाम्बे,

(1[illegible]) जनोरी, (103) मनोरी, (104) शिवनाई, (105) वारबांड़ी (106) जानुल्के डिन्डोरी ;

(ii) इगतपुरी तहसील के नीचे उल्लिखित निरानवे गांव और एक कस्बा इगतपुरी:—

इगतपुरी तहसील :—(1) दाधोशी, (2) भीलमाल, (3) पाहीने, (4) जरवाड खुर्द (5) हेकहर्पा (6) असवाली हर्पा, '(7) सामुन्डी (8) खारोली, (9) कोजीली, (10) एवहाटे, (11) खुशेगांव, (12) मेटचन्द्रीयाची, (13) एलवाड, (14) दापुरे (15) मेट हुमवाची, (16) जरवाड़ बुडरूक, (17) महामुरली, (18) शीवेगडांग, (19) वानजोले, (20) देवगांव (21) अहुरली, (22) ननडाडगांव (23) वाबी हर्पा, (24) नागोसाली, (25) धारगांव, (26) ओन्डली, (27) सेटउरलो, (28) अवलीडुमाला, (29) करहाले (30) रेअम्वे, (31) टेकदेवगांव, (32) मेटाइलाइची (33) बीटउरली (34) वालविहिर, (35) भारवाली बुदरुक, (36) पिम्पलगांव भटाटा (37) कांपरगांव, (38) कुरनोली (39) धारनोली, (40) वाकी, (41) चिन्चाले (खेरे), (42) त्रिगलवाड़ी (43) अडवान, (44) अवालखेड़े, (45) पारडेरी, (46) बालोडुरी, (47) खामबाला, (48) टेक घोटी (49) घोटी बुडरुक, (50) तेलगांव, (1), (51) गिरनारे, (52) टीटोली, (53) बोरटेमभे, (54) तालोशी, (55) नन्दगांव साड़े, (56) पिम्परी साडारोउडीन, (57) तेलघा, (58) कंचनगांव, (59) शेनवाड़ बुडरुक, (60) फेनंगुलगावन, (61) बोरली, (62) मानवं.ड़ेह (63) भावाली खुर्द, (64) कालुमटे, (65) जामुण्डे (66) गाहुन्डे (67) भेरवाज, (68) कुरंगवाड़ी, (69) निरपान, (70) मंजरगांव, (71) अम्बेवाड़ी, (72) खाड़केड, (73) इन्दौर, (74) उमवारकोन, (75) सोमाज घाडगा, (76) उभाड़े (वन जुलवाड़ी) (77) मेगारे, (78) बेलगांव तारहाले, (79) धमनगांव, (80) देयोल, (81), खेरगांव, (82) पिम्पल गांव मोर, (83) धामनी (84) अदासारे खुर्द, (85) अदासारे बुडरुक (86) अधरवाड़, (87) टकड़े खुर्द, (88) टकड़ बुडरूक, (89) खेड़, (90) वारसीगने (91) सोनोशी, (92) माइडारा धानोशी, (93) वासाली;

(iii) नाशिक तहसील के नीचे उल्लिखित सत्तर गांव और एक कस्बा त्रिबंक:—

नाशिक तहसील :—(1) सापटे, (2) कोने, (3) खरवाल, (4) वारा सविहिर, (5) वाघेरा, (6) रोहीले, (7) नन्दगांव (8) गोरथान, (9) हीरडी (10) माले गांव, (11) वेलुन्डो, (12) गणेशगांव वाघेरा, (13) पिम्परी त्रिबंक, (14) मेट कावारा, (15) बहमनवाडे भिबक (16) तोरखांगन, (17) घुमोडी, (18) वीणे, (19) चाकोरे, (20) अमबोली, (21) अमथाई, (22) सीरसगांव, (23) तालवाड़े त्रिबंक, (24) पिम्पलाड त्रिबंक, (25) खामवाले, (26) सापगांव, (27) काचुरली (28) आंजनेरी, (29) ताले गांव, त्रिबंक, (30) पेगलवाड़ी त्रिबंक, (31) वधोली, (32) उभरान्डे, (33) कालमुश्टे, (34) त्रिबंक (ग्रामीण), (35) हर्षवाडी, (36) मेटघरा किल्ला, त्रिबंक (37) मुले गांव (38) लाडची, (39) नाइकवाड़ी, (40) वेले, (41) मदगांव (42) वडगांव, (43) मनोली, (44) घोनगांव (45) दारी (46) गिरनाट, (47) डूगांव, (48) डेओरगांव, (49) नागलवाडी, (50) ओजारखेडा, (51) चांदासी, (52) गांगमहलुंगी (53) जलालपुर, (54) सावरगांव, (55) गोवरधन, (56) शिवानगांव, (57) पिम्पलगांव गरूडेश्वर, (58) राजेवाड़ी, (59) गंगावरहे, (60) गणेशगांव त्रिबंक, (61) गणेशगांव नाशिक, (62) वासाली (63) डूडगांव, (64) महीरावनी, (65) तेलगांव अंजनेरी, (66) जाटेगांव (67) सरुले (68) पिम्पलाड नाशिक, (69) राजुर बहुला, (70) दहीगांव ;

(iv) बागलान तहसील के नीचे उल्लिखित सत्तावन गांव:—

बागलन तहसील :— (1) बोरहाटे, (2) मोहालंगी (3) जैतापुर, (4) गोलवाड, (5) हटनूर, (6) मालीवाडे, (7) अम्बापुर, (8) जाड, (9) विसापुर, (10) शीवारे, (11) खराद, (12) वादे डिगार (13) देवथान (14) कोन्धराबाड़, (15) अन्तापुर, (16) रावर, (17) जामोती (18) अलियाबाड, (19) अजान्डे (20) मुलहर, (21) बावुलने, (22) मोरने डिगार, (23) वोरदाईवात, (24) भीमखेत (25) वाघम्बे, (26) मनूर, (27) सालहर, (28) कटारवेल, (29) भीवलाड़ (30) तुन्गन, (31), दासवेल, (32), जाखाड़ (33) मुन्गासे (34) भावाड़े, (35) डासाने, (36) मालगांव खुर्द (37) सालावान, (38) विसोरे, (39) केरासाने, (40) वाथोड, (41) पाथावेदीगार, (42) तालवाडे डिगार (43) भोरकुरे (44) कीकवारी खुर्द (45) केलजार, (46) टाटनी, (47) भीलडार, (48) की कवारी बुडरुक, (49) जोशन (50) साकोड, (51) करनजखाड (52) डांग सोनडाने, (53) निकवतन, (54) बधांते (55) दाहीं घूले, (56) मारवार, (57) वाडीचौलहेर।

3. धुले जिले में निम्नलिखित:—

(क) नवापुर, तालोडा, अक्कलखुवा और अकरानी की तहसीलें।

(ख) (i) कोरी तहसील के नीचे उल्लिखित अस्सी गांव :—(1) चोपाले, (2) रोथोड, (3) जामखेल, (4) खुरूरवाडे, (5) सुतारे, (6) धनेर, (7) आमले, (8) माचमाल, (9) खांडवारे, (10) रायकोट, (11) वुरूदखे, (12) पानगांव, (13) लागाडवाल, (14) रायतेल, (15) ब्रामनवेल, (16) आम वरवेल (17) जामवोरे, (18) बाटसूल, (19) जामकी, (20) रनमाली, (21) वासखंदी, (22) दामकानी, (23) मालटेक, (24) डाहीवेल, (25) भोनगांव, (26) वाडगांव, (27) मेनडाने, (28) दापुर, (29) रोहन, (30) जेवपुर, (31) आमोड, (32) कीरवाडे, (33) घोडाडे, (34) सुरपान, (35) कोरडे, (36) वालवहे, (37) वीटावे, (38) कासवे छादवेल, (39) वासार, (40) ईशारडे, (41) पेटाले, (42) पिम्पलगांव, (43) मोहने, (44) टेमभी, परगाने वर्षा, (45) शिरसोले, (46) उमारपटा (47) मालगांव परगाने वर्षा, (48) खारगांव, (49) कालाम्बे, (50) चोरवाड, (51) लाखेले, (52) वाटसे, (53) शेनवाड, (54) कुडासी, (55) मन्जारी, (56) मापालगांव, (57) डांगसिटवाडे, (58) बोपखेल (59) शिव, (60) खटयाण, (61) बारखेली, (62) काकसाह, (63) पंखेडे, (64) सामोडे, (65) महाशाडी, परगने पिम्पलनेर, (66) पिम्पलनेर, (67) चीकासे, (68) जीरापुर, (69) कोकनगांव, (70) शीवागे, (71) धामनघर, (72) वीरखेल, (73) पारगांव, (74) मनडाने, (75) बालहाने, (76) देशशिखाडे, (77) काडयाले, (78) टोन गद्दीगार, (79) शेलबाड़ी, (80) देगांव,

(ii) नन्दूरबार तहसील के नीचे उल्लिखित ब्यासी गांव और नन्दूरबार कस्बा

नन्दूरबार तहसील :—(1) भानगाडे, (2) मंगलूर, (3) वासालाई, (4) अर्दीतार, (5) धनोरा, (5) पावाले, (7) कोथाडे, (8) उमाज, (9) कोथाली, खुर्द, (10) वज्जकान, (11) नीमवोमे बुडरूक, (16) जालखे, (13) शिरवाडे, (14) रानाले खेर्द, (15) नाटवाड, (15) करणजवे, (17) शेजवे, (18) पिम्पलोड-टार्फ-धनोरे, (19) लोभा, (20) वेलावाड, (21) वयाहूट, (22) धुलावाड (23) गूलर भवाली, (24) गुंजर जामनोली, (25) करणखेदे, (26) फूलसारे, (27) उमाराडे बुडरूक, (28) नारायणपुर, (29) वीरासगांव, (30) टेकवाड, (31) बिलाढो, (32) खेरआले, (33) खामगांव, (34) नागासार, (35) वीरचाक, (36) टोकरताले, (37) वाघोले, (38) ओंजराडे, (39) आशेटे, (40) थाणेपाडा, (41) अमारावे, (42) पाथारार, (43) थामडाई, (44) वरूल, (45) अदाछी, (46) लोंखेडे, (47) काराजकूपे, (48) नालवे खुर्द, (49) मुदारवे, (50) नालवे बुडरुक, (51) डुथाले, (52) नन्दारखे, (53) भाने, (54) वासाडारे, (55) वावाड, (56) चाकले, (57) दहनीडुले, बुडरूक, (58) दहनीडुले खुर्द, (59) काथोट डिगार, (60) उमारडे खुर्द, (61) चाउपाले, (63) कराले, (63) वाडवारे, (64) आखाटवाडे, (65) हट्टी उर्फ इन्डी, (66) पालाशी, (67) धुली, (68) रकासवाडे, (69) वागहोडे, (70) पाटोनडे, (71) होल-टार्फ-हवेली, (72) खांडोसगांव, (73) शहाडे, (74) शिन्डे,

(75) कोल्डे, (76) भागसारी, (77) धामडोड, (78) मावालडे, (79) कोरीत, (80) सुवातपुर, (81) तीशी, (82) धनधने;

(iii) शाहादा तहसील के नीचे उल्लिखित एक सौ इकतालीस गांव :—

शाहादा तहसील:—(1) आकाशपुर, (2) नवागांव, (वन ग्राम) (3) वीरपुर, (4) दारा, (5) भुटे, (6) कन्साई (वन ग्राम), (7) नन्दया कुमुमवाढे, (वनग्राम), रामपुर, (8) चीराढे, (9) नागजीर (10) कुसुमवाडे, (11) नन्दया, (वन ग्राम), (12) पिम्परानी, (13) रानीपुर, (वन ग्राम), (14) फाटेपुर, (15) लक्काडकोट (वन ग्राम), (16) कोटबनधानी, (वन ग्राम), (17) पिम्पलोड, (18) कुड्डावाड, (19) लाछौर, (20) कनाडी टार्फ हवेली, (21) शिरुडेशर्फ-हवेली, (22) आमोडे, (23) अलखेड, (24) पाडालडे बुडरुक, (25) बुडीगावन, (26) जमाराती, (27) पिम्परी, (28) महशावाड, (29) अनकवाडे, (30) सुलवाडे, (31) तावलाई, (32) मुबारकपुर, (33) वेलावाड, (34) कालामाडी-टार्फ बोम्राडों, (35) वाडी, (36) सोनावाज-टार्फ-बोम्रार्डी, (37) थेलचे, (38) जावडे-टार्फ-बोम्रार्डी, (39) टारहाडी-टार्फ-बोम्रार्डी, (40) वारखे, (41) पारी, (42) कोथाली टार्फ-हवेली, (43) ओरंगपुर, (44) ची-खाली बुडरुक (45) करन खेडे, (46) नन्दार्डी (47) वेजाली, (48) वाघाडे, (49) प्रकाशे, (50) घामलाड, (51) काथारडे वुडरुक, (52) काथारडे खुर्द, (53) कालशाडी, (54) घुरखेडे, (55) भाडे, (56) पिंगने, (57) गनोर, (58) अडगांव, (59) खारागांव, (60) कोच-रारे, (61) बिलाडी-टर्फ-हवेली, (62) बहिरपुर, (63) ब्राह्मणपुरी, (64) सुल्तानपुर, (65) राईखेड, (66) खड डिगर, (67) नवलपुर, (68) चांदसेली, (69) गोदीपुर, (70) पाडालडे खुर्द, (71) भागपुर, (72) जावखेडे, (73) सोनवाल-टर्फ-हवेली, (74) कावालिय, (75) टुकी, (76) मावखेडे, (77) कारजोत, (78) लोहारे, (79) गोगापुर, (80) मुरांगी, (81) टिडारे, (82) दमालडे (83) कलामाद-टर्फ-हवेली, (84) चिखाली खुर्द, (85) भोरटेक, (86) श्रीखेडे, (87) ओजार्टे, (88) उखलशांम, (89) वधार्डे, (90) जाम, (91) जावडे-टर्फ-हवेलीं, (92) टिटारी, (93) हौल-मुबारकपुर, (वन-गांव), (94) वाडगांव (95) पिपार्ड़े, (96) आमा-लोड, (97) मन्डाने, (98) अवागे, (99) टिखोरे, (100) अंटा-वाड, (101) होल, (102) मोहिडे-टर्फ-हवेली, (103) जुनवाने, (104) लोनखेडे, (105) टेंभाली, (106) होलगुजरारी, (107) आमुस, (108) बुपकारी, (109) मालोनी, (110) डोंगरगांव, (111) कोटल-टर्फ-शाहादा, (112) मटकुट, (113) बोराले, (114) कामरावाड, (115) काहाडुल, (116) वाडचिल, (117) लोनखारे, (118) उधालोड, (119) निभोरे, (120) डांडरे, वुदरुक, (121) चिरखान (वन-गांव) (122) असालोड, (नया) (वन-गांव), (123) जयनगर, (124) ढांडरेखुर्द, (वन-गांव), (125) मानमोद्य, (वन-गांव), (126) दुतखेडे (वन-गांव), (127) भोंगारा (वन गांव), (128) वाडाली, (129) कोंढवाल, (130) भुलाने, (वन-गांव), (131) चांदसेली, (वन-गांव), (132) उभाउगढ़, (वन-गांव), (133) काकर्डे खुर्द, (134) खापर खेड, (वन-गांव), (135) मालगांव, (वन-गांव), (136) लंगड़ी भवानी (वन-गांव), (137) शबाना (वन-गांव), (138) काकर्डे वुदरुक, (139) अमोनपुर बुदरुक, (140) काठघर, (141) निबार्डी, (वन-गांव)।

(iv) शिरपुर तहसील के नीचे उल्लिखित बासठ गांव :--

शिरपुर तहसील :—(1) बीरपाली (वनगांव), (2) मल्कात (वन-गांव), (3) फत्तेपुर (वन-गांव), (4) गम्राइ देव (वन-गांव), (5) कोडिड (वन-गांव), (6) गुरहदपानी (वन-गाव), (7) भुटाकी (वन-गांव), (8) वाधपाडे (वन-गांव), (9) सेगरवाडा (वन-गांव) (10) मंजरी बुर्डी (वन-गांव), (11) चोंडी (वन-गांव), (12) भुदाकी (वन-गांव), (13) चांद सुर्य वन-गांव, (14) बोराडीं (नया), (वन-गांव), (15) ककाडमल (वन-गांव), (16) वाकवाड (वन-गांव), (17) उमार्डी, (वन-गांव), (18) दुर्वाद्य (वन-गांव), (19) मोहिडे (वन गांव) (20) डांडवाडा (वन-गांव), (21) टेंभा (वन-गांव), (22) खरीखान (वन-गांव), (23) बोराडी, (24) वसार्डी (25) नंडार्डे, (26) चांदसे, (27) वाडी वुदरुक, (28) वाडी-खुर्द, (29) जालूद, (30) अमानपुर खुर्द, (31) तरहाड, (32) उखलवाढी, (33) मुखेड, (34) नीमजागरी वास्जडी, (36) वाघवाडे, (37) ममरयापाडा, (38) लौंकी, (39) सालेम, (61), (40) फत्तेपुर, (41) हेडाखेड, (42) अरुणापुरी, वांध वनरोधी, (43) संगवी, (44) हटेड, (45) जैड्या अंजर, (46) पलासनेर, (47) खांबले, (48) पानखेड, (वन-गांव), (49) खैरखुटी, (वन-गांव), (50) जोयाडा (वन-गांव), (51) चिलैरे (वन-गांव), (52) लाकड्या हनुमान (वन-गांव), (53) महादेव डांडवाडे (वन-गांव), (54) भालापुर (वन-गांव), (55) रोहिणी, (56) भोइटी, (57) आम्बे (58) खामखेडे परगने आम्बे, (59) हिलारखेड (वन-गांव), (60) हिगांव, (61) वाडेल खुर्द, (62) कालापानी, (वन-गांव)-।

4. जलगांव जिले में निम्नलिखित हैं:--

(क) (1) चोपडा तहसील के नीचे उल्लिखित पच्चीस गांव :—
चोपड़ा तहसील :— (1) मराठा (वन-गांव), (2) मोरहिडा (वन-गांव), (3) उभारती (वन-गांव), (4) सवसेन (वन-गांव), (5) कृष्णपुर (वन-गांव), (6) अंगुर्ने, (7) खार्या पाइव (वन-गांव), (18) वैजापुर (राजस्व) (52), (9) मुलयोतर (वन-गांव), (10) वैजापुर (वन-गांव) (54), (11) बोराजंती (वन-गांव), (12) माला पुर (वन-गांव), (13) बोरमाली (वन-गांव), (14) करजने, (वन-गांव), (15) मेलाने (वन-गांव), (16) विशनपुर (वन-गांव), (17) देवहारी (वन-गांव), (18) देवजीरी (वन-गांव), (19) कुंडणमानी (वन-गांव), (20) इचापुर परगने अडवाड़ (21) वाढावानी, (22) बध्राई, (23) काडने, (24) मोहाराड, (25) असलवाडी (वन-गांव)।

(ii) यावल तहसील के नीचे उल्लिखित तेरह गांव:--

यावल तहसील:—(1) मानापुरी, (2) तोलाने, (3) खालकोट, (4) इचारखेडे (5) मलोद, (6) हरीपुरा (वन-गांव), (7) वाघजीरा (वन-गांव)., (8) पारसड़े बुदरुक, (9) बोरखेडे खुर्द, (10) लांगडा अम्बा, (11) जामन्य, (वन-गांव), (12) गडर्या (वन-गांव), (13) उसमाली (वन-गांव);

(iii) रावेर तहसील के नीचे उल्लिखित इक्कीस गांव:--

रावेर तहसील :—(1) महुमंडली (वन-गांव) , (2) पिपरकुंड (वन-गांव), (3) अंधरमाली (वन-गांव), (4) टिडया (वन-गांव), (5) नीमड्य (6) गार्बार्डी (वन-गांव), (7) जनोरी, (8) चिचाटी, (9) पालु, (10) मारवाल, (11) जिनसी, (12) सहसरालिंग (वन-गांव), (13) लालमती (वन-गांव), (14) अभोंडे बुदरुक, (15) लोहारे, (16) कुसुमबे वुदरुक, (17) कुसुम्बे खुर्द, (18) पिपरी, (19) मोहगन वुदरुक, (20) पाडाले बुदरुक, (21) महुमंडली (पुराना) (परित्यकत्त)

5. अहमद नगर जिले में निम्नलिखित :—

(क) अकोला तहसील के नीचे उल्लिखित चौरानवे गांव :--

अकोला तहसील : (1) तिरढ़े, (2) पदोशी, (3) महालूंगी, (4) एकडारे, (5) संगावी, (6) केली रुम्हनवाडी, (7) विटाका, (8) खीरखोरे, (9), खाम्भालने (10) तहकारी, (11) समशेरपुर, (12) मावरगांव पाट, (13) मुटलाने (14) बारी, (15) वारंघुशी, (16) लाडागांव, (17) शेनिट, (18) पमुलवंडी, (19) बमूलवंडी, (20) अम्बेवंगन, (21) देवगांव, (22) पेंडशेट, (23) मन्हेरे, (24) शेलविहिरे, (25) पंजारे, (26) चिनचोंडी, (27) वाकी, (28) टिटावी,

(29) पिपरकाने, (30) उडाडावाने, (31) कोंडानी, (32) घाटघर, (33) शिगनवाडी राजुर (34) मुरशेट, (35) शेंडी, (36) सामराड, (37) भंडरडारा, (38) रानाड बुदरुक, (39) रानाड खुर्द, (40) मालेगांव, (41) काहोंडी, (42) दिगाम्बर, (43) गुहिरे, (44) कटलपुर, (45) रतनवाडी, (46) मुटखेल, (47) तेरुंगन, (48) राजुर, (49) विले, (50) कोल्टेभे, (51) केलुंगन, (52) जामगांव, (53) शिरपूंजे बुदरुक, (54) सावरकुटे, (55) कुमशेट, (56) शिरपुंजे खुर्द, (57) धमनवान, (58) अम्बिट, (59) बाल्थन, (60) मानिक ओजार, (61) पुरुचवाडी, (62) मवेशी, (63) शियवाड, (64) वांजुलशेट, (65) गोंडांशी, (66) खाडकी, (67) सकिरवाडी, (68) पचनई, (69) चिचावाने, (70) पाडालने, (71) शिलाड, (72) पिंपरी, (73) घोटी, (74) पैठान, (75) लावली, कोटुल, (76) वाघडारी, (77) शिलवंडी, (78) कोहोने, (79) लावली ओटुर, (80) टाले, (81) कोठाले, (82) सोमलवाडी, (83) विहिर, (84) शिंडा, (85) अंबिट खूंद (86) पालसूंडे, (87) पिसेवाडी, (88) फोपसंडी, (89) साटेवाडी, (90) केली ओटुर (91) केली कोटूल, (92) खेटेवाडी, (93) इसरठाव, (94) करंडी।

6. पुणे जिले में निम्नलिखित हैं:—

(क) (i) अम्बेगांव तहसील के नीचे उल्लिखित छप्पन गांव:—

अम्बेगांव तहसील :—(1) डोन, (2) पिंपरगाने, (3) अघाने, (4) आहुपे, (5) तिरपड, (6) न्हावेड, (7) असाने, (8) गाग्विन, (9) नानावाडे, (10) अमाडे, (11) वारसावाने, (12) कोंढारे, (13) अडिवारे, (14) वोरघर, (15) पाटन, (16) कुशिरे खुर्द, (17) पांचाले बुदरुक, (18) कुशिरे बुदरुक, (19) दिगाद, (20) पांचाले खुर्द, (21) महालुंगे-टर्फ-अम्बेगांव, (22) सावराली (23) मेघोली, (24) वाचपे, (25) साकेरी, (26) पिंपरी, (27) अम्बेगांव, (28) जाम भोरी, (29) कलम वाई, (30) कोंढावाल, (31) फुलावाडे, (32) फालोडे, (33) कोल्टावाडे, (34) तेरुनगांव, (35) डिफे बुदरुक, (36) महालुंगे-टर्फ घोडा, (37) राजपुर, (38) चिखाली, (39) राजेवाडी, (40) सुपेघर, (41) तालेघर, (42) मापोली, (43) डिफे खुर्द, (44) पोखरी, (45) गोहे बुदरुक, (46) निगाडाले, (47) गोहे खुर्द, (48) अपाटी, (49) गंगापुर खुर्द, (50) आमोंडी, (51) कानासे, (52) गंगापुर बुदरुक, (53) शिनोली, (54) पिपल गांव-टर्फ-घोडा, (55) साल, (56) ढाकले;

(ii) जुन्नर तहसील के नीचे उल्लिखित पैंसठ गांव :—

जुन्नर तहसील : (1) चिल्हेवाडी, (2) अम्बेगवहन, (3) जाम्बुलसी, (4) खिरेश्वर, (5) मुथालने, (6) कोल्हेवाडी, (7) कोपारे, (8) मंडावे, (9) संगानोरे, (10) आलू, (11) खुबी, (12) पिपलगांव जोगा, (13) करनजाले, (14) माध, (15) पंगरी-टर्फ-माध, (16) कोलवाडी, (17) पारगांव-टर्फ-माध, (18) तालेरन, (19) सीतेवाडी, (20) वटखाले, (21) निमंगीर, (22) अंजनवाले, (23) हडसार, (24) देवाले, (25) खैरे, (26) घाटघर, (27) जलवंडी, (28) हिरडी, (29) उंडेखडाक, (30) राजुर, (31) खाटकाले, (32) मानिकडोह, (33) खाडकुम्बे, (34) उस्रन, (35) वेवाडी, (36) तेजुर, (37) फांगुलघावन (38) चावंड, (39) पुर, (40) खानगांव, (41) मांकेश्वर, (42) सुराले, (43) अम्बेली, (44) शिरोजी-टर्फ-कुकडनेर, (45) बानेवाडी, (46) आपटाले, (47) केली, (48) शिवाली, (49) उटचिल, (50) बोटार्डे, (51) थालेवाडी-टर्फ-मिनेहर, (52) भिवाडे बुदरुक, (53) इंगालून, (54) भिवाडे खुर्द, (55) घंगलडारे, (56) सोनावाले, (57) ताम्बे, (58) हिवारे-टर्फ-मिनहेर, (59) हाटब्रिज, (60) आम्वे, (61) पिंपरवाडी, (62) गुकालनव, (63) गोडरे, (64) खामगांव, (65) सोमतवाडी।

7. नांदेड़ जिले में निम्नलिखित हैं:—

(क) किनवाट तहसील के नीचे उल्लिखित एक सौ बावन गांव और कस्बा किनवाट हैं:—

किनवाट तहसील : (1) टाकली, (2) पाडसा, (3) सेयपाल, (4) मुर्ली, (5) वाडसा, (6) कोली, (7) आप्टा, (8) गोंडेगांव, (9) मदनापुर (महोरे), (10) बोंडगवन, (11) उमरा, (12) मचंदरा पार्डी, (13) करलगांव, (14) मावरखेड, (15) डिगडी कुटेमार, (16) वाम, (17) हरदाय, (18) नाइकवाडी, (19) हिंगान। (20) वाजरा, (21) तुलशी, (22) गोंडवाडसा, (23) अंजनखेड, (24) भोराड, (25) चोराड, (26) धनोड़ा, (सिडखेड), (27) रामपुर, (28) पठरी, (29) खंवाला, (30) पारडी, (31) सिडखेड (32) मिचखेड, (33) हटोला, (34) वेफानी, (35) दुंडरा, (36) गोड़ी, (37) बोठ, (38) मैलू, (39) करंली, (सिडखेड) (40) भगवती (41) वाजरा बुडरुक, (42) उमरी, (43) ऊनकदेव, (44) चेस, (45) पिपलसेंडा, (46) सरखाड़ी, (47) देहली, (48) निराला, (49) नूरगांव, (50) टिटवी, (51) लिंगी, (52) नागपुर, (53) जुनुनी, (54) डीगाडवाजरा, (55) हारसंगमी (सिडखेड) (56) सिंगोडा (57) सीरपुर, (58) टेम्भी, (59) पटोडा बुडरुक, (60) मांडवी (61) जावरला, (62) पल्सी, (63) बेलगांव, (64) कांगी, (65) कोठारी (सिडखेड) (66) पिपलगांव (सिनखेड), (67) डंगरगांव (सिखेड) (68) जारुर, (69) मिकी, (70) पांचुंडा, (71) बनोला (72) साकूर, (73) मेंडकी, (74) डिग्डी (मोहापुर), (75) दांगोरा (डिग्डी), (76) मोहापुर, (77) मुगशी, (78) सिडगी (किन्वात), (79) मालबोड़गांव, (80) नीपुर, (81) राजगाड, (82) वाडोली (83) अंजी, (84) कनकवाडी, (85) लोनी, (86) धामनधारी, (87) पंढारा, (88) वेलोरी, (किन्वात), (89) मारेगांव, (90) कामथाला, (91) अंबाडी, (92) खेरडा, (93) मलकापुर, (94) छोटी, (95) सिरमेटी, (96) भीमपुर, (97) पीपलगांव, (किन्वात), (98) घोगरवाडी, (99) गोकुंडा, (100) मंडवा, (101) डिग्डी (मंगाबोडी), (102) नागजारी, (103) कोठारी (चिखली) (104) प्रधान मांगवी, (105) वेंडी, (106) अमाडी, (107) मदनापुर, (चिखली) (108) शनीवार पेठ, (109) डभाडी, (110) चिखली, (111) हूडी, (चिखली), (112) ऐंढा, (113) भूलजा, (114) दरसंगवी, (चिखली), (115) मलकसाडी, (116) पडा, (117) पारडी खुर्द, (118) करला, (119) डेगांव, (120) लिंगधारी, (121) पार्डी बुद्रुक, (122) बोधाडी खुर्द, (123) बोढाडी बुडरुक, (124) सिडगी, (चिखली), (125) अंडबोड़ी, (चोखली), (126) कोपारा, (127) पिपरफोडी, (128) पटोडा (चिखली), (129) पिपरी, (130) धनोरा (चिखली), (131) सवारी, (132) थारा, (133) पोथरैड्डी, (134) सिगरावाडी, (135) अनजेगांव, (136) भंडारवाडी, (137) जलधारा, (चन्द्रपुर), (138) बेलेरी, (चिखली). (139) माल्कोलरी, (140) डिगराम, (141) डेगरागांव, (चिखली), (142) शिवोनी (चिखली), (143) परोटी, (144) सवारगांव, (145) जलधारा (इस्लापुर), (146) कोठारी, (147) हुडी (इस्लापुर), (148) करांजी, (इस्लापुर), (149) कुप्टी खुर्द, (150) कुप्टी बुडरुक, (151) वागधारी, (152) तलारी।

8. अमरावती जिले में निम्नलिखित :—

(क) चिखलडरा और धारणी की तहसीलें।

9. यवतमाल जिले में निम्नलिखित :—

(क) (i) मारेगांव तहसील के नीचे उल्लिखित एक-सौ-तीस गांव:—

मांडेगांव तहसील :—(1) घोगुलडारा, (2) शिवनाला, (3) बुरांदा (24) (4) पहापल, (5) कन्हल गांव, (26), (6) खेफाडवई, (7) घोडाधारा, (8) नरगना, (9) धामनी, (10) मदनपुर, (11) बोरी खुर्द, (12) पिसगांव, (13) वडगांव (40), (14) फिस्की (वन

ग्राम) (15) भालेबाडी, (16) पठारी, (51), (17) चिचाला, (18) पंढार का वडा (53), (19) खारडा (वन ग्राम) (54), (20) पिपराड, (वन ग्राम), (21) फेपरवाडा, (22) सालिभट्टी (वनगांव), (23) डालडोंगार गांव, (24) मचिन्द्रा, (25) पंडविहीर, (26) जलका, (27) पंढार देवी (वनग्राम), (28) अम्बोरा (वन ग्राम), (29) चिचोनी बोटोनी, (30) अवालगांव (वन ग्राम), (31) कन्हल गांव (85), (32) खैरगांव, (86), (33) सराती, (34) बुरांदा (88), (35) दुरगाडा, (36) वागधारा, (37) मैनधादी, (38) धान पुर, (39) हतवांजी, (40) खापरी, (41) उन्दार-देवी (वन ग्राम), (42) मारेगाव (वन ग्राम), (43) खडानी, (44) म्हाइरडोडका, (45) पालगांव (46) बोटोनी, (47) गिरिजापुर (वन ग्राम), (48) पचपोहर, (49) अम्बेजारी, (50) रोहवत, (51) रायपुर, (52) सागनापुर, (53) हिवारा वारसा, (54) रामपुर, (55) कटली बोरगांव, (56) पार्डी (116), (57) शिवला, (58) चिलाई (वन ग्राम), (59) बोरगांव (वन ग्राम), (60) पेनधारी, (61) अर्जुनी, (62) केगांव, (63) रजनी, (64) मजारा, (65) गंगापुर (वन ग्राम), (66) भोइकुंड (वन ग्राम), (67) वधोना, (68) सुसारी, (69) सुरला, (131), (70) गोंडानी, (71) निमानी, (72) डराग, (73) आसन, (74) जागलोन, (75) जामकोला (76) ईसापुर, (77) भिलोना, (78) उमरघाट, (79) वललासा, (80) जुनोनी (वनग्राम), (81) लैनधोरी, (82) चिचघाट, कारेगांव खुर्द, (83) अम्बेजरी खुर्द, (84) अम्बेजरी बुदरूक, (85) कारेगांव खुर्द, (86) निवादेवी, (87) तेम्भी, (88) कुंडी, (89) मांडवी, (90) जुनोनी, (91) परम्भा, (92) पोवर्नी (वनग्राम), (93) पीवरडोल, (94) भोराड (वनग्राम) (95) चीखलडोह, (96) मुलगावान, (97) भीमनाला, (98) चाटवां, (99) अराईकवाडा, (100) म्वारा, (101) मथार्जुन, (102) महाडापुर, (103) पंढारखनी, (104) डेमाड देवी, (105) मंडवा, (106) डुगरगांव, (वन ग्राम), (107) डभाडी, (108) अमरी, (192), (109) मुघाटी, (110) परसोडी, (111) कोडपाखेंडी, (112) मंगरूल खुर्द, (113) मांगरूल बुद्रुक (114) गोपालपुर, (115) रामपैठ, (116) चलवार्डी, (117) जामनी, (118) शिरोला, (119) अडकोली, (120) खडकडोह, (121) विरसापेठ (122) मुची, (123) मरकी बुद्रुक (124) मरकी खुर्द, (125) गणेशपुर, (216), (126) पवनार (वन ग्राम), (127) कृष्णपुर (वन ग्राम), (128) खेकडी (वन ग्राम), (129) शेकपुर, (130) इयोती ;

(ii) रालेगांव तहसील के नीचे उल्लिखित तैतालीस गांव :—

रालेगांव तहसील :—(1) लोहारा, (2) इकलैरा, (3) सोनेर्डी, (4) वाहखेड, (5) जलका, (6) बरला, (7) पिंपरी दुर्गा, (8) मंडवा (9) कोलवां, (10) सोइत, (11) वरूड, (12) बुकाई, (13) जारगाड, (14) खडकी सुकली, (15) डोंगरगांव, (16) तोजनी, (17) अंजी, (18) लोनी, (19) बोरटी (वनग्राम), (20) सरटी, (21) खैरगांव, कासर, (22) वर्धा, (23), भूलगाड, (24) पिपलशेंडा, (75), (25) अरमुर्डी, (26) सावरखेड, (27) चोंधी, (28) वंढोडा, (29) खेमकुंड, (30) पार्डी (वनग्राम), (31) उमरविहीर, (32) आडनी (33) खटारा, (34) मुंजाला, (35) पलसकुंड, (36) विहीरगांव, (37) खैरगांव, (38) देवधारी (39) सिगलदीप, (40) सेनुर्ली, (41) शिडोलां, (42) जोतिगडारा, (43) सखी खुर्द ;

(iii) केलापुर तहसील के नीचे उल्लिखित एक सौ तीन गांव और कस्बा पंढरकावडा :—

केलापुर तहसील :—(1) मोहदारी, (2) जोगिन खोला, (3) मीरा, (4) जीरा (5) घोडदारा (वन ग्राम), (6) सखी बुद्रुक (7) वधोना खुर्द, (8) जोलापुर (वन ग्राम), (9) करंजी, (10) वधोना बुद्रुक (11) तिवसाला (वन ग्राम), (12) कोठाडा, (13) मुरदेवो (14) नन्दाय, (15) असोली, (16) मोहदा, (17) कारेगांव (163), (18) चिखालदारा, (19) कृष्णापुर (20) डभा, (21) मोर्वा, (22) खैरगांव, (199), (23) वधोली (24) कुसाल, (25) चापन, (26) मलकापुर (वनग्राम (27) केगांव, (28) वाढनेर, (29) गुली, (30) भाडउमगारी, (31) पटोडा, (32) पहपल, (33) नागेजरी खुर्द, (34) वहट्टार, (35) मुसारी, (36) माइंकसुकली (वनग्राम), (37) पेधारी, (38) पिडपली, (39) डांगरगांव, (308), (40) बोठ, (41) मालेगांव, (वन ग्राम), (42) हिवारडारी (वनग्राम), (43) मालेगांव बुद्रुक (वनग्राम), (44) दर्यापुर (45) पिलवाहेरी, (46) अर्ली, (47) हिवारी, (48) पिपलशेंडा, (333), (49) (कारेगांव, (334), (50) वडवात, (51) खेरी (336), (52) घुबाडी, (53) कोंधारा, (54) सखारा बुद्रुक (55) धारना (56) मांगी (343), (57) ढोकी, (344), (58) वाई, (59) पिपलपुर, (60) गणेशपुर (347), (61) खैरगांव (348), (62) पाढे, (63) नीलजय, (64) मारेगांव (352), (65) अंभोरा, (66) डोंगरगांव, (358) (67) पिपरी, (353), (68), खैरगांव, (360), (69) मुबी, (70) मंगुरडा, (71) पंढारवाणी बुद्रुक (वन ग्राम), (72) कोंधी, (73) बेडाड, (74) वाग्गी, (75) घनमोडे, (76) नंदगांव, (77) गणेशपुर, (370) (78) टाटापुर, (79) जंजापुर, (80) गोंडवाकाडी, (81) चालवरडी, (82) थेलूरी, (83) टाडूमारी (84) बोड़गांव (377), (85) अकोली बुद्रुक, (86) महनडोली, (87) सखारा, (88) मराठवाकाडी (89) ढोकी, (382), (90) वेल्लारपुर, (91) टोकवंजारी, (92) वंजारी, (382), (93) खैरगांव बुद्रुक, (94) तेम्भी, (95) राधापुर (वन ग्राम), (96) गिलखाना, (वन ग्राम), (97) वसारी (98) अंधारवाडी, (99) येदलपुर (वन ग्राम), (100) चन्खा, (101) नीमथेली, (102) रूढा, (103) सुकली ;

(iv) घटंजी तहसील के नीचे उल्लिखित पचपन गांव :—

घटंजी तहसील :—(1) माखेनी, (2) राजुड़वाडो, (3) लिंगी, (4) कोलीखुर्द, (5) कोली बुद्रुक, (6) रामपुर रुंधार्नी, (7) कापशी, (8) डाटीडी (9) गूढ़ा, (10) वरूड़, (240), (11) जापरवाडी, (12) उमरी (242) (13) पलोडी, (14) कोपरी (244), (15) घोटी (16) वोडाडी, (17) मुढ़ाटी, (वन ग्राम), (18), जालन्द्री (19) मनुषधारी, (20) अयाटे, (21) काप, (22) कवाठा बुद्रुक, (23) बिलायत, (24) खड़की, (250), (25) चिमटा, (26) कोपरी-खुर्द, (27) चिंचोली, (269), (28) किडो (वन ग्राम) (269), (29) गवांड़ा (वन ग्राम), (30) टिटवी, (31) मुराद गहून (32) पिपलखूंटी (वन ग्राम), (33) खरोनी (वन ग्राम), (34) वढोनी, (35) डोर्ली, (36) रुहटी, (37) रासा (वन ग्राम), (38) जटाला, (39) चीखलवर्धा, (40) टाड-सावांगी, (41) सैकाल, (42). नागेजारी बुद्रुक, (43) कवाठा, (वन ग्राम), (44) पार्वा, (45) मेझाडा (46) पर्डी, (47) जम्ब, (48) कालेश्वर, (49) शेराड, (50) ढंकी (वन ग्राम), (51) मथानी (वन ग्राम), (52) राजेगांव (वन ग्राम) (53) खापड़ी (वन ग्राम), (54) होनेगांव, (55) गनेड़ी ।

(10) गडचिरोली जिले में निम्नलिखित :—

(क) ऐटापल्ली, सिरोंचा, अहेरी, धनोरा, कुरखेडा की तहसीलें ।

(ख) (i) गडचिरोली तहसील के नीचे उल्लिखित बासठ गांव :—

गडचिरोली तहसील :—(1) नवेगांव (636), (2) चाक चुरोचूरा, (3) कुरहाडी, (4) चमक मोसी, (6) मुरमाडी, (6) बोठेडा, (7) पलंडुर, (8) गिलगांव (658), (9) चाकखारपुडी, (10) जेपरा, (11) चाक डिमाना, (12) मरूमबोडी (13) कुरखेडा (14) खुरसा (15) बोसापुर, (16) सोनपुर, (17) मेंढा (680), (18) सावरगांव, (683) (19) कनेरी, (20) पुलखल, (21) मुडजा बुद्रुक (22) मुडजा दुकुम, (23), कुपला, (24) मसेली, (25) रणभूमि, (26) चंढाला, (27) रणमूल, (28) कुंभी पैच, (29) कुंभी मोकसा, (30) मडे मूल (31) मड़ोढा, (32) कोसमघाट, (33) रायपुर, (718) (34) रावणजोरा, (35) पेकिनकासा, (36) रावेला, (37)

(37) सुइमारा (38) मखेरा (39) करकजरा (40) कन्हलगांव (725), (41) केलोगट्टा (42) तहगांव (43) गजनगुडा (44) वेनोली (45) सूर्यडूंगरी (36) सलाईटोला, (47) बीतनटोला (48) पोतेगांव (733) (49) राजोली (734) (50) मराडा (51) जल्लेर, (52) देवपुर (53) रामगाड (738), (54) गावलहेटी (55) देवडा (56) खडदगुडा, (57) तलगुडा (58) जमगांव, (59) कडसी (60) कार-कुटी (61) नागवेली (62) जालेगांव ;

(ii) ग्ररमोड़ी तहसील के नीचे उल्लिखित चौहत्तर ग्राम :—

ग्ररमोड़ी तहसील :—(1) कारेगांव (6), (2) कलमगांव, (3) कुगन (4) सेल्डा कुकुम (5) सेल्डा लम्बे (6) कसारी तुकुम (7) कसारी गांव (8) शिवराजपुर (29) (9) पोटेगांव (30) (10) विहिरगांव (33) (11) पिपलगांव, (12) ग्ररात-टोंडी (13) डोंगरगांव (हल्बी) (14) पलासगांव (43) (15) नावरगांव, (26) पथरगोटा, (49) (17) मंगेवाडा (18) ग्ररमोड़ी, (19) सलमारा, (20) थांणेगांव (21) पतनवाडा, (22) पुरावेरगाड, (23) देवलगांव, (69) (24) सुकला (25) मोहजारी बनाम साखरबोडी (26) चक केरनाडा (27) लोहरा (78), (28) चकसोनपुर, (29) होरापुर (80), (30) डूंगरतम्सी, (31) शिग्रानी खुर्द (32) चवहेला, (33) मोहतला चक कुकोड़ी, (34) मेंढा (89) (35) डूंगरतम्सी पंच (36) नागर-वाडी (37) चक नरोटी (38) चक कुरांडी (39) बड़ेगांव (40) छोटेबोदी, (41) देलनवाडी, (42) मानापुर (43) कोसारी (44) मानगोडा, (45) तुलतुली, (46) चकनगरवाही, (47) विहिरगांव, (48) कुरांदी, (49) उमरी, (50) येनगड़ा, (51) पिसेवाडाढा, (52) पारसवाडी (113), (53), डावंडी, (54) खादकी (115), (55) भाकरांडी, (56) नरोती मालगुजार, (57) कोरेगांव, (119) (58) वाखेडा, (59) खारदी, (60) भंसी, (61) डोरली, (62) वानरचुवा, (63) जांभली (127), (64) भेंढा (128), (65) नरचूली, (66) खैरी, (67) मारेगांवपाच, (68) मारेगांव (140), (69) चाकमारेगांव, (70) चाकचोली, (71) मोसी खाम्ब, (72) बेलगांव, (144); (73) चिचोली (145). (74) वांखेड़ा,

(iii) चमौर्शी तहसील के नीचे उल्लिखित एक सौ बत्तीस गांव :—

चमौर्शी तहसील :—(1) सगनपुर (758), (2) बंधोना (764), (3) गिलगांव (765), (4) भेंडी कनहल (771), (5) थाटारी, (6) चोते कनहर, (7) कलमगांव, (8) कुरूड, (9) मलेर, (10) कुलेगांव, (11) नाचनगांव (12) भड़भी (788), (13) वलसारा, (14) चाकवीसापुर, (15) जोगना (16) मुरमुरी, (17) रावनपल्ली, (18) सोनापुर, (19) दरली, (20) रेखागांव, (21) येडानुर (22) पेलमन पेठ, (23) पंढरी भाटल, (24) राजनगट्टा, (25) चाक ग्रांमगांव सं० 1 (809), (26) मुटनूर, (27) अंबापुर, (28) मुरंडा पाई, (29) लेनगुडा, (30) ग्रदयल, (31) करकापल्ली, (32) चाक करकापल्ली, (33) जंगमकुरूल, (34) फूमर, (35) धेकानी, (35) चाक मुढीली सं० 2 (37) लक्ष्मणपुर, (38) सगनपुर (829), (39) ग्रम्बोली (40) गहूबोडी, (41) चाक नारायणपुर सं० 1, (42) चाक नारायण-पुर सं० 1 (43) राजुर बुटुक, (44) भडबिड (835), (45) मनगर, (46) चिचपल्ली, (47) वानरचुग्रा, (48) जयरामपुर, (49) वैगांव (50) नारायणपुर, (51) राजुर खुर्द, (52) हलदवाही, (53) मुढोली (54) कोटारी (845) (55) बमहनी देव, (56) सोमनपल्ली, (57) कनहलगांव (848), (58) मिनगेला, (59) वेलगट्टा, (60) पैठताला, (61) चाकपेठटाला सं० 1 (62) परडी देव, (63) यादव पल्ली, (64) राजपुर (856), (65) जमभाली रीठ, (66) मेटीगुड़ा, (67) चाक बेलगट्टा, (68) मंजीगांव, (69) मछलीघाट, (70) चाक माकेपल्ली सं० 4, (71) दर्पणगुडा, (72) चाक माकेपल्ली सं० 2, (73) चाक माकेपल्ली सं० 3 (74) गरंजी, (75) चाकमाड़े ग्रामगांव, (76) चाकमाड़े ग्रामगांव सं० 1, (77) चाकमाड़े ग्रामगांव सं० 2, (78) तुम्डी (79) रिगाडी, (80) माकेपल्ली मालगुजारी, (81) बोरघाट, (82) ग्रस्सी नोकेवाडा, (83) बामनपेठ, (84) वेन्गनुर, (85) नोकेवाडा, (86) ग्रलापल्ली, (87) रेंग्नेवाही, (88) कोलपाली, (89) ग्रम्बेला (वनगांव), (90) गाटा (वनगांव), (91) ग्रडान्गेपाली, (92) सुरगांव (वनगांव), (93) येललूर, (94) थाकारी, (95) घराजगट्टा (908), (96) लोहारा (97) मुकारीटोला, (98) भोलखंडी (वनगांव), (99) हेटालकासा, (100) भोलेपाली, (101) पुलीगुडाम, (102) कुनघडा, (103) कोलमापुर (104) गंगापुर, (105) चन्दनखेडी, (106) मालेरा, (107) वासरवाडा, (108), चापराला, (109) चैंदमपट्टी, (110) मुकाडी (वनगांव), (111) फुमकी, (112) सिन्गामपल्ली, (113) घान्नूर, (114) कोठारी (930) (115) ग्रम्बाटपाली, (116) गांमानी, (117) लग्महेटी, (118) दामपुर, (119) बंडुकापाली, (120) कोडीगांव, (121) चिचेला (122) नागुलवाही, (123) चितूगुनहा, (124) टुमरगुण्डा, (125) मचांली गट्टा, (126), येल्ला, (127) टिकेपाली, (128) पारपल्ली (129) जामगांव, (130) कुलया, (131) रामपुर, (132) लागाम चाक।

(11) चन्द्रपुर जिले में निम्नलिखित राजुरा तहसील के नीचे उल्लिखित एक सौ ब्यासी गांव : —

राजुरा तहसील :— (1) परसांडा, (2) रायपुर, (3) कोठोदा खुर्द, (4) गोविन्दपुर, (5) कठोदा बुद्रुक, (6) महेंडी, (6) पारडी, (8) जैवरा (8), (9) चनई खुर्द, (10) ग्रकोला, (11) कोरपाना, (12) दुर्गाडी, (13) रूपापेठ, (14) चनई बुद्रुक, (15) मंडवा, (16) कनेरगांव बुद्रुक, (17) कटलाबोडी, (18) शिवापुर, (19) चोपन, (20) केरमबोडी, (21) कुकुलबोडी, (22) टिप्पा, (23) मंगुलवीरा, (24) खड़की, (27) (25) जमुलधारा, (28) (26) बोरगांव, बुद्रुक, (27) बोरगांव खुर्द, (28) ग्राशापुर, (29) तंगाला, (30) खैरगांव (33) (31) हटलोनी, (32) यरगांव, (33) उमरजारा, (34) येल्लापुर, (35) सिंगार पठार, (35) लमबोरी (37) शेडबई (38) नरपायर, (39) कोडापुर, (40) घरपना, (41) नोकेवडा, (42) गुडशेला (43) वानी, (44) केकाजारी, (45) मोहडा, (46) पुडीयाल मोहडा, (47) कमलापुर, (48) चिचखोड, (49) वनसाडी, (50) परम्बा, (51) देवघाट, (52) कुसल, (53) देहेगांव, (54) सोनुरली (70), (55) करगांव खुर्द, (71), (56) धनोली, (57) पीपरदा, (58) चिनचोली, (59) करगांव बुद्रुक, (60) मरकागोडी (76), (61) वेलगांव व, (62) जुलबरडी, (63) सावलहीरा, (64) खैरगांव (80), (65) पंटारवानी (81), (66) जमबुलधारा, (67) धानक देवी, (68) चरमी ईसापुर, (69) सारंगपुर, (70) जिवटी, (71) नागापुर, (72) मसकलमेट्टा (73) धोंडा ग्ररजुनी (74) धोंडा मंडवा, (75) टेका ग्ररजुनी, (76) टेका मंडवा, (77) रहपल्ली बुद्रुक, (78) चिखली, (94) (79) पाटन (95), (80) हीरापुर (96), (81) ईसापुर, (82) ग्रासन खुर्द, (83) ग्रासन बुद्रुक, (84) पीपलगांव, (85) पालेजारी, (86) बोरीनवेगांव, (87) नंदा, (88) वीची, (89) धुनकी, (90) धामनगांव, (91) लखमपुर, (92) वाडगांव, (92) इंजापुर, (94) चन्दूर, (95) कुकड़नत, (96) खिरदी, (97) धुतरा, (98) वेहलामपुर, (99) मानोली खुर्द, (100) जामोनी, (101) नोकारी बुद्रुक, (102) सोनापुर, (103) उपरवाई, (104) भुरकुंडा खुर्द, (105) खडकी (150), (106) नौकारी खुर्द, (107) नगराला (108) पालेजारी, (109) काकवन, (110) डोंगार-गांव (155), (111) चिखाली (156), (112), भुरकुन्डा बुद्रुक, (113) पचगांव, (114) सेनगांव (159), (115) टाटाखोहाडी, (116) भेडवी, (117) मुकडपल्ली, (118) मरकागोंडी, (119) टिटवी, (120) नाडपा, (121) यरगावन, (122) खावाडगोन्डी, (123) सोराकासा, (124) कुसम्बी, (125) जनकापुर, (126) पुनागुड्डा (नावेगांव), (127) डिजवाडा, (128) खडकी रायपुर, (129) गोविन्दपुर, (130) मरईपाटन (131) उमरजारा (176) (132) रहपल्ली खुर्द, (133) धर्मारम, (134) भोकसापुर, (135) वामबेजारी, (136) भारी, (137) पंढारवानी (182) (138) मिनढोला, (139) सोनडो, (140) वेलगांव (185) (141) ककड़घाट, (142) गनेरी, (143) खिरदी, (144) शेडवाही, (145) बाबापुर, (146) हीरापुर, (200), (147)

सखरी, (148) मनोली बुद्रुक, (149) गायेगांव, (150) हरडोना खुर्द, (151) हरडोना, बुद्रुक, (152) विमिरगांव (224) (153) मांगी, (154) वान्नगी, (155) पन्ढरपौनी (227), (156) ग्रहेरी, (157) कोवी, (158) गोराज, (197) वाम्हर, (160) रानीवेली, (161) भेडोडा, (162) टमभुरवाही (163) चिन्डु, (164) चिचगोडा, (165) कावथाला (119) (166) सोनुरली, (167) सिरसी, (168) बरडा (169) धेनथाला, (170) खेलजारी, (171) नेवगांव (265) (172) चिचाला, (173) विरूर, (174) सिद्धेश्वर, (175) घोटा, (176) डांमारगांव (269), (177) सुबई, (178) कोसटाला, (179) लाकड-कोट, (180) अंत्रेजारी, (181) अंतरगांव (277), (182) ग्रनूर।

3. पूर्वगामी पैरा 2 मे किसी प्रादेशिक खण्ड के प्रति किसी निर्देश का चाहे वह किसी भी नाम से उपदर्शित हो, यह अर्थ लगाया जायगा कि वह इस आदेश के प्रारम्भ पर यथाविद्यमान उस नाम के प्रादेशिक खण्ड के प्रतिनिर्देश है ।

जैल सिंह,
राष्ट्रपति

[सं० फा० 19(2)/85-वि.—1]
इ० वें० सूर्य परिशास्त्री,
सचिव

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd December, 1985

G.S.R. 876 (E).—The following Order made by the President is published for general information:—

"C.O. 123

THE SCHEDULED AREAS (MAHARASHTRA) ORDER, 1985

In exercise of the powers conferred by sub-paragraph (2) of paragraph 6 of the Fifth Schedule to the Constitution of India, the President hereby rescinds the Scheduled Areas (Part A States) Order, 1950, and the Scheduled Areas (Part B States) Order, 1950, in so far as they relate to the areas now comprised in the state of Maharashtra, and in consultation with the Governor of that state, is pleased to make the following Order, namely:—

1. (*1*) This Order may be called the Scheduled Areas (Maharashtra) Order, 1985.

(*2*) It shall come into force at once.

2. The areas specified below are hereby redefined to be the Scheduled Areas within the State of Maharashtra:—

1. The following in Thane District:—

(*a*) Tahsils of Dahanu, Talasari, Mokhanda, Jawhar, Wada and Shahapur;

(*b*) (*i*) The one hundred forty-four village of Palghar tahsil as mentioned below:—

Palghar tahsil :—

(1) Tarapur, (2) Kudan, (3) Dahisar-tarf- Tarapur, (4) Ghiwali, (5) Wawe, (6) Akkarpatti, (7) Kurgaon (8) Parnali, (9) Vengani, (10) Patharwali, (11) Nowale, (12) Shigaon, (13) Gargaon, (14) Chinchare, (15) Akegawhan, (16) Naniwali, (17) Ambedhe, (18) Barhanpur, (19) Salgaon, (20) Khutad, (21) Khaniwade, (22) Rawate, (23) Akoli, (24) Asheri, (25) Somate, (26) Pasthal, (27) Boisar, (28) Borsheti, (29) Mahagaon, (30) Kirat, (31) Wade, (32) Khadkawane, (33) Mendhwan, (34) Vilshet, (35) Kondgaon, (36) Karsood, (37) Betegaon, (38) Warangade, (39) Lalonde, (40) Ghanede, (41) Kambalgaon, (42) Man, (43) Ghaneghar, (44) Wedhe, (45) Chari Budruk, (46) Birwadi, (47) Kallale, (48) Padghe, (49) Pole, (50) Nandore, (51) Girnoli, (52) Borande, (53) Devkhope, (54) Sagawe, (55) Kosbad, (56) Kokaner, (57) Nagzari, (58) Chari Khurd, (59) Velgaon, (60) Khutal, (61) Chilhar, (62) Bhopoli, (63) Nihe, (64) Damkhand, (65) Kondhan, (66) Awandhan, (67) Bangarchole, (68) Shil, (69) Loware, (70) Bandhan, (71) Nand-gaon-tarf-Manor, (72) Shilshet, (73) Katale, (74) Ambhan, (75) Wasaroli, (76) Kharshet, (77) Manor, (78) Takwahal, (79) Sawarkhand, (80) Nalshet, (81) Kev, (82) Wakadi, (83) Maswan, (84) Wandiwali, (85) Netali, (86) Saye, (87) Ten, (88) Karalgaon, (89) Gowade, (90) Tamsai, (91) Durves, (92) Dhuktan, (93) Pochade, (94) Haloli, (95) Khamloli, (96) Bahadoli, (97) Bot, (98) Embur Irambi, (99) Danisari-tarf-Manor, (100) Kude, (101) Gundave, (102) Satiwali, (103) Vehaloli, (104) Saware, (105) Warai, (106) Jansai, (107) Khaire, (108) Dhekale, (109) Ganje, (110) Jayshet, (111) Shelwade, (112) Veur, (113) Ambadi, (114) Nawali, (115) Morawali, (116) Varkhunti, (117) Kamare, (118) Tokrale, (119) Bandate, (120) Zanjaroli, (121) Chahade, (122) Wasare, (123) Khadkoli, (124) Sakhare, (125) Rotho, (126) Lalthane, (127) Navaze, (128) Tandulwadi, (129) Girale, (130) Pargaon, (131) Nagawe-tarf-Manor, (132) Umbarpada Nandade, (133) Uchavali, (134) Safale, (135) Sonawe, (136) Makane Kapse, (137) Karwale, (138) Wadhiv Sarawali, (139) Penand, (140) Kandarwan, (141) Dahiwale, (142) Darshet, (143) Navghar (Ghatim), (144) Umbarpada-tarf-Manor.

(ii) The forty-five villages of Vasai (Bassein) tahsil as mentioned below:—

Vasai (Bassein) tahsil:—

(1) Dahisar, (2) Koshimbe, (3) Tulinj, (4) Sakawar, (5) Chimane, (6) Hedavade, (7) Kashidkopar, (8) Khaniwade, (9) Bhaliwali, (10) Kavher, (11) Shirsad, (12) Mandvi, (13) Chandip, (14) Bhatane, (15) Shivansai, (16) Usgaon, (17) Medhe, (18) Vadghar, (19) Bhinar, (20) Ambode, (21) Kalbhon, (22) Adne, (23) Sayawan, (24) Parol, (25) Shirvali, (26) Majivali, (27) Karanjon, (28) Tilher, (29) Dhaviv, (30) Pelhar, (31) Achole, (32) Valiv, (33) Sativali, (34) Rajavali, (35) Kolhi, (36) Chinchoti, (37) Juchandra, (38) Bapane, (39) Deodal, (40) Kamam, (41) Sarjamori, (42) Poman, (43) Shilottar, (44) Sasunavghar, (45) Nagle,

(*iii*) The seventy-two villages of Bhiwandi tahsil as mentioned below:—

Bhiwandi tahsil:—

(1) Bhivali, (2) Ganeshpuri, (3) Vadavali Vajreshwari, (4) Akloli, (5) Savaroli, (6) Khativali, (7) Usgaon, (8) Ghotgaon, (9) Vadhe, (10) Vareth, (11) Chane, (12) Asnoli-tarf-Dugad, (13) Dugad, (14) Manivali, (15) Vadwali-tarf-Dugad, (16) Malbidi, (17) Mohili, (18) Nandithane, (19) Depoli, (20) Sakharoli, (21) Supegaon, (22) Pilanze Khurd, (23) Pilanze Budruk, (24)

Alkhivali, (25) Vaghivale, (26) Devchole, (27) Sagoan, (28) Eksal, (29) Chinchavali-tarf-Kunde, (30) Dudhani, (31) Vape, (32) Ghadane, (33) Kunde, (34) Ghotavade, (35) Mainde, (36) Karmale, (37) Kandali Budruk, (38) Kelhe, (39) Kandali Khurd, (40) Dighashi, (41) Newade, (42) Ambadi, (43) Dalonde, (44) Jambhivali-tarf-Khambale, (45) Umbarkhand, (46) Ashivali, (47) Zidake, (48) Kharivali, (49) Base, (50) Gondade, (51) Pahare, (52) Shedgaon, (53) Pachhapur, (54) Gondravali, (55) Jambhivali-tarf-Kunde, (56) Asnoli-tarf- Kunde, (57) Shirole, (58) Dabhad, (81) (59) Mohandul, (60) Shirgaon, (61) Pimpal Sheth Bhusheth, (62) Khadki Khurd, (63) Khadki Budruk, (64) Chimbipade, (65) Kuhe, (66) Dhamne, (67) Lakhiwali, (68) Palivali, (69) Paye, (70) Gane, (71) Dahyale, (72) Firangpada,

(*iv*) The seventy-seven villages of Murbad tahsil as mentioned below:—

Murbad tahsil:—

(1) Kasgaon, (2) Kisal, (3) Wadawali, (4) Sakhare, (5) Khutalborgaon, (6) Ambele Khurd, (7) Sayale, (8) Inde, (9) Khedale, (10) Talawali-tarf-Ghorat. (11) Eklahare, (12) Chafe-tarf-Khedul, (13) Pimpalghar, (14) Dahigaon, (73) (15) Parhe, (16) Kandali, (17) Dhasai, (18) Alyani, (19) Palu, (20) Deoghar, (21) Madh, (22) Sonawale, (23) Veluk, (24) Alawe, (25) Bursunge, (26) Mandus, (27) Khed, (28) Wanote, (29) Shai, (30) Shelgaon, (31) Shiroshi, (32) Talegaon, (33) Fangalkoshi, (34) Merdi, (35) Walhivare, (36) Mal, (37) Jadai, (38) Ambiwali, (39) Dighephal, (40) Diwanpada, (41) Kochare Khurd, (42) KochareBudruk, (43) Chosale, (44) Khutal Bangla, (45) Nayahadi, (46) Moroshi, (47) Fangulgawhan, (48) Sawarne, (49) Thitabi-tarf-Vaishakahre, (50) Kudshet, (51) Fangane, (52) Khapari, (53) Hedawali, (54) Karchonde, (55) Zadghar, (56) Udaldoha, (57) Mhorande, (58) Tokawade, (59) Balegaon, (60) Talawali (Baragaon), (61) Waishakhare, (62) Maniwali-tarf-Khedul, (63) Pendhari, (64) Umaroli Budruk, (65) Ojiwale, (66) Mandwat, (67) Mahaj, (68) Padale, (69) Koloshi, (70) Jaigaon, (71) Kalambad (Bhondivale), (72) Kheware, (73) Dudhanoli, (74) Umaroli Khurd, (75) Khopiwali, (76) Milhe, (77) Gorakhagad.

2. The following in Nasik District:—

(*a*) The tahsils of Peint, Surgana and Kalwan;

(*b*) (*i*) The one hundred six villages of Dindori tahsil as mentioned below:—

Dindori tahsil :—

(1) Mokhanal, (2) Bhanwad, (3) Dehare, (4) Karanjali, (5) Gandole, (6) Palasvihir, (7) Vare, (8) Vanjole, (9) Ambad, (10) Vanare, (11) Titve, (12) Deothan, (13) Nanashi, (14) Charose, (15) Deoghar,(16) Kaudasar, (17) Vani Khurd, (18) Pimpalgaon Dhum, (19) Joran, (20) Mahaje, (21) Sadrale, (22) Nalwadi, (23) Oje, (24) Golshi, (25) Jalkhed, (26) Nigdol,(27) Kokangaon Budruk, (28) Umbrale Khurd, (29) Ambegan, (30) Chachadgaon, (31) Vaghad, (32) Pophal Wade, (33) Dhaur, (34) Umbale Budruk, (35) Jambutke, (36) Pimpraj, (37) Nalegaon, (38) Vilwandi, (39) Rasegaon, (40) Kochargaon, (41) Tilholi, (42) Ravalgaon, (43) Deher Wadi, (44) Dhagur, (45) Deosane, (46) Sarsale, (47) Karanjkhed, (48) Pingalwadi, (49) Eklahare, (50) Chausale, (51) Pimpri Anchla, (52) Ahiwantwadi, (53) Goldari, (54) Haste, (55) Kolher, (56) Jirwade, (57) Chamdari, (58) Maledumala, (59) Mandane, (60) Koshimbe, (61) Punegaon, (62) Pandane, (63) Ambaner, (64) Chandikapur, (65) Bhatode, (66) Dahivi, (67) Mulane, (68) Kokangaon Khurd, (69) Malegaon, (70) Pimparkhed, (71) Phopasi, (72) Vani Kasbe, (73) Sangamner, (74) Khedle, (75) Mavadi, (76) Karanjwan, (77) Dahegaon, (78) Vaglud, (79) Krishnagaon, (80) Varkhed (81) Kadvamhalungi, (82) Gaondegaon, (83) Hatnore, (84) Nilwandi, (85) Pimpalgoan Ketki, (86) Rajapur, (87) Dindori, (88) Jopul, (89) Madki Jamb, (90) Palkhed, (91) Indore, (92) Korhate, (93) Chinchkhed, (94) Talegaon Dindori, (95) Akrale, (96) Mohadi, (97) Pimpsalanare, (98) Khatwad, (99) Ramsej, (100) Ambe Dindori, (101) Dhakambe, (102) Janori, (103) Manori, (104) Shivanai, (105) Varwandi, (106) Jaulke Dindori,

(*ii*) The ninety-three villages of Igatpuri tahsil as mentioned below and one town Igatpuri:—

Igatpuri tahsil :—

(1) Dhaloshi, (2) Bhilmal, (3) Pahine, (4) Zarwad Khurd, (5) Tak harsha, (6) Aswali Harsha, (7) Samundi, (8) Kharoli, (9) Kojoli, (10) Avhate, (11) Kushegaon, (12) Metchandryachi, (13) Alwand, (14) Dapure, (15) Met Humbachi, (16) Zarwad Budruk, (17) Mhasurli, (18) Shevgedang, (19) Wanjole, (20) Deogaon, (21) Ahurli, (22) Nandagaon, (23) Vavi Harsha, (24) Nagosali, (25) Dhargaon, (26) Ondli, (27) Saturli, (28) Awalidumala, (29) Karhale, (30) Rayambe, (31) Takedeogaon, (32) Met Ilyachi, (33) Biturli, (34) Walvihir, (35) Bhavli Budruk, (36) Pimpalgaon Bhatata, (37) Kopargaon, (38) Kurnoli, (39) Dharnoli, (40) Waki, (41) Chinchal (Khaire), (42) Tringalwadi, (56) (43) Adwan, (44) Awalkhede, (45) Parderi, (46) Balayduri, (47) Khambala, (48) Take Ghoti, (49) Ghoti Budruk, (50) Talegaon ([illegible]), (51) Girnare, (52) Titoli, (53) Bortembhe, (54) Taloshi, (55) Nandgaon Sade, (56) Pimpri Sadaroddin, (57) Talegha, (58) Kanchangaon, (59) Shenwad Budruk, (60) Fangulgavan, (61) Borli, (62) Manwedhe, (63) Bhavali Khurd, (64) Kaluste, (65) Jamunde, (66) Gahunde, (67) Bharvaj, (68) Kurungwadi, (69) Nirpan, (70) Maniargaon, (71) Ambewadi, (72) Khadked, (73) Indore, (74) Umbarkon, (75) Somaj Ghadga, (76) Ubhade (Vanjulwadi), (77) Megare, (78) Belgaon Tarhale, (79) Dhamangaon, (80) Deole, (81) Khairgaon, (82) Pimpalgaon Mor, (83) Dhamni, (84) Adasare Khurd, (85) Adasare Budruk, (86) A[illegible]harwad, (87) Taked Khurd, (88) Taked Budruk,(89) Khed, (90) Barshingve, (91) Sonoshi, (92) Maidara Dhanoshi, (93) Wasali,

(*iii*) The seventy villages in Nasik tahsil as mentioned below and one town Trimbak:—

Nasik tahsil:—

(1) Sapte, (2) Kone, (3) Kharwal, (4) Varasvihir, (5) Vaghera, (6) Rohile, (7) Nandgaon, (8) Gorthan, (9) Hirdi, (10) Malegaon, (11) Welunje, (12) Ganeshgaon Waghera, (13) Pimpri Trimbak, (14) Met Kawara, (15) Brahmanwade Trimbak, (16) Toanangan, (17) Dhumodi, (18) Bese, (19) Chakore, (20) Amboli, (21) Ambai, (22) Shirasgaon, (23) Talwade Trimbak, (24) Pimpalad Trimbak, (25) Khambale, (26) Sapgaon, (27) Kachurli, (28) Anianeri, (29) Talegaon Trimbak, (30) Pegalwadi Trimbak, (31) Vacholi, (32) Ubhrande, (33) Kalmuste, (34) Trimbak (Rural), (35) Harshewadi,

(36) Mahiravani Trimbak, (37) Mulegaon, (38) Ladachi, (39) Naikwadi, (40) Vele, (41) Sadgaon, (42) Vadgaon, (43) Manoli, (44) Dhondegaon, (45) Dari, (46) Girnare, (47) Dugaon, (48) Deorgaon, (49) Nagalwadi, (50) Ozarkheda, (51) Chandashi, (52) Gangamhalungi, (53) Jalalpur, (54) Sawargaon, (55) Govardhan, (56) Shivangaon, (57) Pimpalgaon Garudeshwar, (58) Rajewadi, (59) Gangavarhe, (60) Ganeshgaon Trimbak, (61) Ganeshgaon Nashik, (62) Wasali, (63) Dudgaon, (64) Mahirawani, (65) Takegaon Anjaneri, (66) Jategaon, (67) Sarul, (68) Pimplad Nashik, (69) Rajur Bahula, (70) Dahigaon.

(*iv*) The fifty seven villages in Baglan tahsil as mentioned below: —

Baglan tahsil:

(1) Borhate, (2) Mohalangi, (3) Jaitapur, (4) Golwad, (5) Hatnoor, (6) Maliwade, (7) Ambapur, (8) Jad, (9) Visapur, (10) Shevare, (11) Kharad, (12) Vade Digar, (13) Deothan, (14) Kendharabad, (15) Antapur, (16) Raver, (17) Jamoti, (18) Aliabad, (19) Ajande, (20) Mulher, (21) Babulne, (22) Morane-Digar, (23) Bordaivat, (24) Bhimkhet, (25) Waghambe, (26) Manoor, (27) Salher, (28) Katarwel, (29) Bhilwad, (30) Tungan, (31) Daswel, (32) Jakhod, (33) Mungase, (34) Bhawade, (35) Dasane, (36) Malgaon Khurd, (37) Salawan, (38) Pisore, (39) Kerasane, (40) Vathod, (41) Pathavedigar, (42) Talwade Digar, (43) Morkure, (44) Kikwari Khurd, (45) Kelzar, (46) Tatani, (47) Bhildar, (48) Kikwari Budruk, (49) Joran, (50) Sakode, (51) Karanjkhed, (52) Dang Saundane, (53) Nikwel, (54) Bandhate, (55) Dahindule, (56) Sarwar, (57) Wadi chaulher.

3. The following in Dhule District:—

(*a*) Tahsils of Nawapur, Taloda, Akkalkuwa and Akrani;

(*b*) (*i*) The eighty villages in Sakri tahsil as mentioned below:—

Sakri tahsil:—

(1) Choupale, (2) Rothod, (3) Jamkhel, (4) Khuruswade, (5) Sutare, (6) Dhaner, (7) Amali, (8) Machmal, (9) Khandbare, (10) Raikot, (11) Burudkhe, (12) Pangaon, (13) Lagadwal, (14) Raitel, (15) Brahmanwel, (16) Amkhel, (17) Jambore, (18) Varsus, (19) Jamki, (20) Runmali, (21) Vaskhedi, (22) Damkani, (23) Saltek, (24) Dahiwel, (25) Bhongaon, (26) Badgaon, (27) Maindane, (28) Dapur, (29) Rohan, (30) Jebapur, (31) Amode, (32) Kirwade, (33) Ghodade, (34) Surpan, (35) Korde, (36) Valwhe, (37) Vitave, (38) Kasbe Chhadwell, (39) Basar, (40) Isarde, (41) Petale, (42) Pimpalgaon, (43) Mohane, (44) Tembhe, Pargane Warse, (45) Shirsole, (46) Umarpata, (47) Malgaon Pargane Versa, (48) Khargaon, (49) Kalambe, (50) Chorwad, (51) Lakhale, (52) Warse, (53) Shenwad, (54) Kudashi, (55) Manjari, (56) Mapalgaon, (57) Dangshirwade, (58) Bopkhel, (59) Shiv, (60) Khatyal, (61) Vardoli, (62) Kaksad, (63) Pankhede, (64) Samode, (65) Mhasadi, Pargane Pimpalner, (66) Pimpalner, (67) Chikase, (68) Jirapur, (69) Kokangaon, (70) Shevage, (71) Dhamandhar, (72) Virkhel, (73) Pargaon, (74) Mandane, (75) Balhane, (76) Deshirvade, (77) Kadyale, (78) Dhongaddigar, (79) Shelbari, (80) Degaon,

(*ii*) The eighty-two villages in Nandurbar tahsil and town Nandurbar as mentioned below:—

Nandurbar tahsil:—

(1) Bhangade, (2) Mangloor, (3) Vasalai, (4) Arditara, (5) Dhanora, (6) Pavale, (7) Kothade, (8) Umaj, (9) Kothali Khurd, (10) Vadajakan, (11) Nimbone Budruk, (12) Jalkhe, (13) Shirvade, (14) Ranale Khurd, (15) Natawad, (16) Karanjwe, (17) Shejwe, (18) Pimplod-tarf-Dhanore, (19) Loya, (20) Velavad, (21) Vyahur, (22) Dhulawad, (23) Gujar Bhavali, (24) Gujar Jamboli, (25) Karankhede, (26) Phulsare, (27) Umarde Budruk, (28) Narayanpur, (29) Ghirasgaon, (30) Dhekwad, (31) Biladi, (32) Khairale, (33) Khamgaon, (34) Nagasar, (35) Virchak, (36) Tokartale, (37) Waghale, (38) Ozarde, (39) Ashte, (40) Thanepada, (41) Amarave, (42) Patharai, (43) Dhamdai, (44) Varul, (45) Adachhi, (46) Lonkhede, (47) Karajkupe, (48) Nalave Khurd, (49) Sundarde, (50) Nalave Budruk Dudhale, (52) Nandarkhe, (53) Bhane, (54) Vasadare, (55) Wawad, (56) Chakle, (57) Dahindule Budruk, (58) Dahindule Khurd, (59) Kathore Digar, (60) Umarde Khurd, (61) Chaupale, (62) Akrale, (63) Vadbare, (64) Akhatwade, (65) Hatti *alias* Indi, (66) Palashi, (67) Ghuli, (68) Rakaswade, (69) Waghode, (70) Patonde, (71) Hol-tarf-Haveli, (72) Khodasgaon (73) Shahade, (74) Shinde, (75) Kolde, (76) Bhagsari, (77) Dhamdod, (78)Savalde, (79) Korit, (80) Sujatpur, (81) Tishi, (82) Dhandhane.

(*iii*) The one hundred forty-one villages in Shahada tahsil as mentioned below:—

Shahada tahsil:—

(1) Akaspur, (2) Nawagaon (Forest Village), (3) Virpur, (4) Dara, (5) Bhuta, (6) Kansai, (Forest Village), (7) Nandya Kusumwade (Forest Village), Rampur, (8) Chirade, (9) Nagziri (Forest Village), (10) Kusumwade, (11) Nandya (Forest Village), (12) Pimprani, (13) Ranipur, (Forest Village), (14) Fattepur, (15) Lakkadkot (Forest Village), (16) Kotbandhani (Forest Village), (17) Pimplod, (18), Kuddawad, (19) Lachhore, (20) Kanadi-tarf-Haveli, (21) Shirud-tarf Haveli, (22) Amode, (23) Alkhed (24) P dalde Budruk, (25) Budigavan, (26) Umarati, (27) Pimpri, (28) Mhasavad, (29) Anakwade, (30) Sulwade, (31) Tavalai, (32) , Mubarakpur, (33) Velavad, (34) Kalmadi-tarf-Boardi, (35) Wadi, (36) Sonawad-tarf-Boardi, (37) Thangche, (38) Javade-tarf-Boardi, (39) Tarhadi-tarf-Boardi,(40) Vardhe, (41) Pari, (42) Kothali-tarf-Haveli, (43), Aurangpur, (44) Chikhali Budruk, (45) Karankhede (46) Nandarde, (47) Vaijali, (48) Vaghode, (49) Prakashe, (50) Dhamlad, (51) Katharde Budruk, (52) Katharde Khurd, (53) Kalsadi, (54) Dhurkhede, (55) Bhade, (56) Pingane, (57) Ganor, (58) Adgoan, (59) Kharagaon, (60) Kochrare, (61) Biladi-tarf-Haveli, (62) Bahirpur, (63) Bramhanpur, (64) Sultanpur, (65) Raikhed, (66) Khed Digar, (67) Navalpur, (68) Chandsaili, (69) Godipur, (70) Padalde Khurd, (71) Bhagapur, (72) Javkhede, (73) Sonwai-tarf-Haveli, (74) Kavalith, (75) Tuki, (76) Sawkhede, (77) Karjot, (78) Lohare, (79) Gigapur, (80) Kurangi, (81) Tidhare, (82) Damalde, (83) Kalamad-tarf-Haveli, (84) Chikhali Khurd, (85) Bhortek, (86) Shrikhede, (87) Ozarte, (88) Ukhalshem, (89) Vagharde, (90) Jam, (91) Javade-tarf-Haveli, (92) Titari, (93) Hol Mubarakpur (Forest Village), (94) Vadgaon, (95) Pimparde,(96) Asalod, (97) Mandane, (98) Awage, (99) Tikhore, (100) Untawad, (101) Hol,

(102) Mohide-tarf-Haveli, (103) Junwane, (104) Lonkhede, (105) Tembhali, (106) Holgujari, (107) Asus, (108) Bupkari, (109) Maloni, (110) Dongargaon, (111) Kothal-tarf-Shaha ja, (112) Matkut, (113) Borale, (114) Kamravad, (115) Kahatul, (116) Vadchhil, (117) Londhare, (118) Udhalod, (119) Nimbhore, (120) Dhandre Budruk, (121) Chirkhan (Forest Village), (122) Asalod (New) (Forest Village), (123) Jainagar, (124) Dhandre Khurd (Forest Village), (125) Manmodya (Forest Village), (126) Dutkhede (Forest Village), (127) Bhongara (Forest Village), (128) Vadali, (129) Kondhawal, (130) Bhulane (Forest Village), (131) Chandsaili (Forest Village), (132) Ubhadagad (Forest Village), (133) Kakarde Khurd, (134) Khaparkhede (Forest Village), (135) Malgaon (Forest Village), (136) Langadi Bhavani (Forest Village), (137) Shahana (Forest Village), (138) Kakarde Budruk, (139) Abhanpur Budruk, (140) Katghar, (141) Nimbardi (Forest Village).

(*iv*) The sixty-two villages in Shirpur tahsil as mentioned below:—

Shirpur tahsil:—

(1) Borpani (Forest Village), (2) Malkatar (Forest Village), (3) Fattepur (Forest Village), (4) Gadhad Deo (Forest Village), (5) Kodid (Forest Village), (6) Gurhadpani (Forest Village), (7) Bhudaki (Forest Village), (8) Waghpade (Forest Village), (9) Saigarpada (Forest Village), (10) Manjriburdi (Forest Village), (11) Chondi (Forest Village), (12) Bhudaki (Forest Village), (13) Chandsurya (Forest Village), (14) Boradi (New) (Forest Village, (15) Kakadmal (Forest Village),(16) Vakawad (Forest Village), (17) Umarda (Forest Village), (18) Durabadya (Forest Village),(19) Mohide (Forest Vill ge) (20) Dondwada (Forest Village), (21) Tembha (For et Village), (22) Kharikhan (Forest Village), (23) Boradi, (24) Wasardi, (25) Nandarde, (26) Chandase, (27) Wadi Budruk, (28) Wadi Khurd, (29) Jaled, (30) Abhanpur Khurd, (31) Tarhad, (32) Ukhalwadi, (33) Mukhed, (34) Nimzari, (35) Varzadi, (36) Waghbarda, (37) Samryapada, (38) Lauki, (39) Sule (61), (40) Fattepur, (41) Hedakhed, (42) Arunapuri Dam (Deforested), (43) Sangavi, (44) Hated, (45) Zendya Anjan, (46) Palasner, (47) Khambale, (48) Panakhed (Forest Village), (49) Khairkhuti (Forest Village), (50) Joyada (Forest Village), (51) Chilare (Forest Village), (52) Lakdya Hanuman (Forest Village), (53) Mahadeo Dondwade (Forest Village), (54) Malapur (Forest Village), (55) Rohini, (56) Bhoiti, (57) Ambe, (58) Khamkhede Pargane Ambe, (59) Hiwarkhede, (Forest Village), (60) Higaon, (61) Vadel Khurd, (62) Kalapani (Forest Village).

4. The following in Jalgaon District —

(a) (*i*) The twenty-five villages in Chopda tahsil as mentioned below :—

Chopda tahsil:—

(1) Maratha (Forest Village),(2) Mordhida (Forest Village), (3) Umarti (Forest Village),(4) Satrasen (Forest Village), (5) Krishnapur (Forest Village), (6) Angurne, (7) Kharya Padav (Forest Village), (8) Vaijapur (Revenue) (52), (9) Mulyautar (Forest Village), (10) Vaijapur (Forest Village) (54), (11) Borajanti (Forest Village), (12) Malapur (Forest Village), (13) Bormali (Forest Village), (14) Karajane (Forest Village), (15) Melane (Forest Village), (16) Vishnapur (Forest Village), (17) Devhari (Forest Village), (18) Deoziri (Forest Village), (19) Kundyapani (Forest Village), (20) Ichapur Pargane Adawad, (21) Badhawani, (22) Badhai, (23) Kandane, (24) Moharad, (25) Asalwadi (Forest Village).

(*ii*) The thirteen villages in Yaval tahsil as mentioned below:—

Yaval tahsil:—

(1) Manapuri, (2) Tolane, (3) Khalkot, (4) Ichakhede, (5) Malod, (6) Haripura (Forest Village), (7) Vaghazira (Forest Village), (8) Parasade Budruk, (9) Borkhede Khurd, (10) Langda Amba, (11) Jamnya (Forest Village), (12) Gadrya (Forest Village), (13) Usmali (Forest Village).

(*iii*) The twenty-one villages in Raver tahsil as mentioned below :—

Raver tahsil:—

(1) Mahumandali (Forest Village), (2) Pimparkund (Forest Village), (3) Andharmali (Forest Village), (4) Tidya (Forest Village), (5) Nimdya (Forest Village), (6) Garbardi (Forest Village), (7) Janori, (8) Chinchati, (9) Pal, (10) Marwhal, (11) Jinsi, (12) Sahasraling (Forest Village), (13) Lalmati (Forest Village), (14) Abhode Budruk, (15) Lohare, (16) Kusumbhe Budruk, (17) Kusumbe Khurd, (18) Pimpri, (19) Mohagan Budruk, (20) Padale Budruk, (21) Mahumandali (old) (Deserted).

5. The following in Ahmednagar District:—

(*a*) The ninety-four villages in Akole tahsil as mentioned below:—

Akole tahsil:—

(1) Tirdhe, (2) Padoshi, (3) Mhalungi, (4) Ekdare, (5) Sangavi, (6) Keli Rumhanwadi, (7) Bitaka, (8) Khirvire, (9) Kombhalne, (10) Tahakari, (11) Samsherpur, (12) Savargaon Pat, (13) Muthalane, (14) Bari, (15) Waranghusi, (16) Ladagaon, (17) Shenit, (18) Pabhulwandi, (19) Babhulwandi, (20) Ambevangan, (21) Deogaon, (22) Pendshet, (23) Manhere, (24) Shelvihire, (25) Panjare, (26) Chinchond, (27) Waki, (28) Titavi, (29) Pimparkane, (30) Udadawane, (31) Kodani, (32) Ghatghar, (33) Shinganwadi Rajur, (34) Murshet, (35) Shendi, (36) Samra,d(37) Bhandardara, (38) Ranad Budruk, (39) Ranad Khurd, (40) Malegaon, (41) Kohondi, (42) Digambar, (43) Guhire, (44) Katalapur, (45) Ratanwadi, (46) Mutkhel, (47) Terungan, (48) Rajur, (49) Vithe, (50) Koltembhe, (51) Kelungan, (52) Jamgaon, (53) Shirpunje Budruk, (54) Savarkute, (55) Kumshet, (56) Shirpunje Khurd, (57) Dhamanvan, (58) Ambit (59) Balthan, (60) Manik Ozar, (61) Puruchawadi, (62) Maveshi, (63) Shiswad, (64) Wapjulshet, (65) Gondoshi, (66) Khadki, (67) Sakirwadi, (68) Pachanai, (69) Chinchavane, (70) Padalne, (71) Shelad, (72) Pimpri, (73) Ghoti, (74) Paithan, (75) Lavali Kotul, (76) Waghdari, (77) Shilvandi, (78) Kohone, (79) Lavali Otur, (80) Tale, (81) Kothale, (82) Somalwadi, (83) Vihir, (84) Shinda, (85) Ambit Khind, (86) Palsunde, (87) Pisewadi, (88) Phopsandi, (89) Satewadi, (90) Keli Otur, (91) Keli Kotul, (92) Khetewadi, (93) Esarthav, (94) Karandi.

6. The following in Pune District:—

(a) (*i*) The fifty-six villages in Ambegaon tahsil as mentioned below:—

Ambegaon tahsil:—

(1) Don, (2) Pimpargaane, (3) Aghane, (4) Ahupe, (5) Tirpad, (6) Nhaved, (7) Asane, (8) Malin, (9) Nanawade,

(10) Amade, (11) Warsawane, (12) Kondhare, (13) Adivare, (14) Borghar, (15) Patan, (16) Kushire Khurd, (17)Panchale Budruk, (18) Kushire Budruk, (19) Digad, (20) Panchale Khurd, (21) Mahelunge-tarf-Ambegaon, (22) Savarali, (23) Megholi, (24) Vachape, (25) Sakeri, (26) Pimpari, (27) Ambegaon, (28) Jambhori, (29) Kalambai, (30) Kondhawal, (31) Phulavade, (32) Phalode, (33) Koltavade, (34) Terungaon, (35) Dimbhe Budruk, (36) Mahalunge-tarf-Ghoda, (37) Rajpur, (38) Chikhali, (39) Rajewadi, (40) Supeghar, (41) Taleghar, (42) Mapoli, (43) Dimbhe Khurd, (44) Pokhari, (45) Gohe Budruk, (46) Nigadale, (47) Gohe Khurd, (48) Apati, (49) Gangapur Khurd, (50) Amondi, (51) Kanase, (52) Gangapur Budruk, (53) Shinoli, (54) Pimpalgaon-tarf-Ghoda, (55) Sal, (56) Dhakale.

(*ii*) The sixty-five villages in Junnar tahsil as mentioned below :—

Junnar tahsil —

(1) Chilhewadi, (2) Ambegavhan, (3) Jambhulshi, (4) Khireshwar, (5) Muthalane, (6) Kolhewadi, (7) Kopare, (8) Mandave, (9) Singanore, (10) Alu, (11) Khubi, (12) Pimpalgaon Joga, (13) Karanjale, (14) Madh, (15) Pangri-tarf-Madh, (16) Kolwadi, (17) Pargaon-tarf-Madh, (18) Taleran, (19) Sitewadi, (20) Watkhale, (21) Nimgir, (22) Anjanwale, (23) Hadsar, (24) Devale, (25) Khaire, (26) Ghatghar, (27) Jalwandi, (28) Hirdi, (29) Undekhadak, (30) Rajpur, (31) Khatkale, (32) Manikdoh, (33) Kali kumbe, (34) Usran, (35) Vevadi, (36) Tejpur, (37) Phangulghavan, (38) Chavand, (39) Pur, (40) Khangaon, (41) Mankeshwar, (42) Surale, (43) Amboli, (44) Shiroli-tarf-Kukadner, (45) Wanewadi, (46) Aptale, (47) Keli, (48) Shivali, (49) Utchil, (50) Bortale, (51) Dhalewadi-tarf-Minher, (52) Bhivade Budruk, (53) Ingalon, (54) Bhivade Khurd, (55) Ghangaldare, (56) Sonavale, (57) Tambe, (58) Hivare-tarf-Minher, (59) Hatvij, (60) Ambe, (61) Pimparwadi, (62) Sukalewadhe, (63) Godre, (64) Khamgaon, (65) Somatwadi.

7. The following in Nanded District:—

(*a*) The one hundred fifty-two villages and town Kinwat in Kinwat tahsil as mentioned below:—

Kinwat Tahsil —

(1) Takli, (2) Padsa, (3) Sayepal, (4) Murli, (5) Wadsa, (6) Koli, (7) Ashta, (8) Gondegaon, (9) Madnapur (Mahore) (10) Bondgavan, (11) Umra, (12) Machandra Pard, (12) Karalgaon, (14) Sawarkhed, (15) Digdi (Kutemar), (16) Wai, (17) Hardap, (18) Naikwadi, (19) Hingani, (20) Wazra, (21) Tulshi, (22) Gondwadsa, (23) Anjankhed, (24) Bhorad, (25) Chorad, (26) Dhanora (Sindkhed), (27) Rampur, (28) Pathri, (29) Khambala, (30) Pardi, (31) Sindkhed, (32) Cinchkhed, (33) Hatola, (34) Waifani, (35) Dhundra, (36) Gouri, (37) Both, (38) Sailu, (39) Karanji (Sindkhed), (40) Bhagwati, (41) Wazra Budruk, (42) Umri, (43) Unakdeo, (44) Chais, (45) Pimpalsenda, (46) Sarkhani, (47) Delhi, (48) Nirala, (49) Noorgaon, (50) Titvi, (51) Lingi, (52) Nagapur, (53) Jununi, (54) Digadwazra, (55) Darsangvi (Sindkhed), (56), Singoda, (57) Sirpur, (58) Tembhi, (59) Patoda Budruk, (60) Mandvi, (61) Jawarla, (62) Palsi, (63) Belgaon, (64) Kanki, (65) Kothari, (Sindkhed), (66) Pimpalgaon (Sindkhed), (67) Dongargaon (Sindkhed), (68) Jarur, (69) Minki, (70) Pachunda, (71) Wanola, (72) Sakur, (73) Mendki, (74) Digdi (Mohanpur), 75) Dhanora (Digdi), (76) Mohapur, (77) Mungshi, (78) Singdi (Kinwat), (79) Malborgaon, (80) Nejpur (81) Rajgad, (82) Wadoli, (83) Anji, (84) Kanakwadi, (85) Loni, (86) Dhamandhari, (87) Pandhara, (88) Bellori (Kinwat), (89) Maregaon, (90) Kamthala, (91) Ambadi, (92) Kherda, (93) Malkapur, (94) Ghoti, (95) Sirmetti, (96) Bhimpur, (97) Pipalgaon (Kinwat), (98) Ghogarwadi, (99) Gokunda, (100) Mandva, (100), (101) Digdi (Mangabodi), (102) Nagzari, (103) Kothari (Chikhli), (104) Pradhan Sangvi, (105) Bendi, (106) Amadi, (107) Madnapur (Chikhli), (108) Shaniwar Peth, (109) Dabhadi, (110) Chikhli, (111) Hudi (Chikhli), (112) Endha, (113) Bhulja, (114) Darsangvi (Chikhli), (115) Malakwadi, (116) Penda, (117) Pardi Khurd, (118) Karla, (119) Degaon, (120) Lingdhari, (121) Pardi Budruk, (122) Bodhadi Khurd, (123) Bodhadi Budruk, (124) Sindgi (Chikhli), (125) Andbori (Chikhli), (126) Kopara, (127) Piperphodi, (128) Patoda (Chikhli), (129) Pipri, (130) Dhanora (Chikhli), (131) Sawari, (132) Thara, (133) Poth Reddy, (134) Singarwadi, (135)-Anjegaon, (136) Bhandarwadi, (137) Jaldhara (Chandra)-pur), (138) Belori (Chikhli), (139) Malkolari, (140) Digras, (141) Dongargaon (Chikhli), (142) Shivoni (Chikhli), (143) Paroti, (144) Sawargaon, (145) Jaldhara (Islapur), (146) Kothari, (147) Hudi (Islapur), (148) Karanji (Islapur), (149) Kupti Khurd, (150) Kupti Budruk, (151) Wagdhari, (152) Talari.

8. The following in Amravati District:—

(a) The tahsils of Chikhaldara and Dharni.

9. The following in Yavatmal District:—

(*a*) (*i*) The one hundred thirty villages in Maregaon tahsil as mentioned below :—

Maregaon Tahsil:

(1) Ghoguldara, (2) Shionala, (3) Buranda, (4), (4), Phapal, (5) Kanhalgaon (6), (6) Khadkadwai, (7) Ghodadhara, (8) Narsala, (9) Dhamani, (10) Madnapur, (11) Bori Khurd, (12) Pisgaon, (13) Wadgaon, (40). (14) Phiski (Forest Village), (15) Bhalewadi, (16) Pathari, (51), (17) Chinchala, (18) Pandharkawada (53), (19) Kharda (Forest Village), (54), (20) Pimprad (Forest Village), (21) Pimparwada, (22) Salbhatti (Forest Village), (23) Doldongargaon, (24) Machhindra, (25) Pandwihir, (26) Jalka, (27) Pandhardevi (Forest Village), (18) Ambora (Forest Village), (29) Chinchoni Botoni, (30) Awalgaon (Forest Village), (31) Kanhalgaon, (85), (32) Khairgaon, (86), (33) Sarati, (34) Buranda, (88), (35) Durgada, (36) Wagdhara, (37) Mendhani, (38) Ghanpur, (39) Hatwanjiri, (40) Khapri, (41) Uchatdevi (Forest Village), (42) Maregaon (Forest Village), (43) Khandani, (44) Mhaisdodka, (45) Palgaon, (46) Botoni, (47) Girjapur (Forest Village), (48) Pachpohar, (49) Ambezari, (50) Rohapat, (51) Raipur, (52) Sagnapur, (53) Hiwara Barsa, (54) Rampur (55) Katli Borgaon, (56) Pardi, (116), (57) Shibla, (58) Chiali (Forest Village), (59) Borgaon (Forest Village), (60) Pendhari, (61) Arjuni, (62) Kgaon, (63) Rajani, (64) Majara, (65) Gangapur (Forest Village), (66) BhoiRund (Forest Village), (67) Wanhona, (68) Susari, (69) Surla, (131), (70) Godani, (71) Nimani, (72) Darara, (73) Asan, (74) Jaglon, (75) Zamkola, (76) Isapur, (77) Kilona, (78) Umarghat, (79) Wallasa, (80) Junoni (Forest Village), (81) Lanchori, (82) Chinchghat, (83) Ambezari, Khurd, (84) Ambezari Budruk, (85) Karugaon Khurd, (86) Nimbadevi, (87) Tembhi, (88) Kundi, (89) Mandiv, (90) Junoni, (91) Parambha, (92) Pokharni (Forest Village), (93) Piwardol, (94) Bhorad

(Forest Village), (95) Chikhaldoh, (96) Mulgawaan, (97) Bhimnala, (98) Chatwan, (99) Araiakwad, (100) Gawara, (101) Matharjun, (102) Mahadapur, (103) Pandharwani, (104) Demadi Devi, (105) Mandwa, (106) Dongargaon (Forest Village), (107) Dabhadi, (108) Umari, (192), (109) Mudhati, (110) Parsodi, (111) Kodpakhindi, (112) Mangrul Khurd, (113) Mangrul Budruk, (114) Gopalpur, (115) Rampeth, (116) Chalbardi, (117) Jamani, (118) Shirola, (119) Adkoli, (120) Kinhalakloh, (121) Birsapeth, (122) Muchi, (123) Marki Budruk, (124) Marki Khurd, (125) Ganeshpur, (126), (126) Pawnar (Forest Village), (127) Krishnapur (Forest Village), (128) Khadkadi (Forest Village), (129) Shekapur, (130) Yeoti.

(*ii*) The forty-three villages in Ralegaon tahsil as mentioned below :—

Ralegaon Tahsil:—

(1) Lohara, (2) Eklara, (3) Sonurdi, (4) Watkhed, (5) Jalka, (6) Warna, (7) Pimpari Durga, (8) Mandawa, (9) Kolwan, (10) Soit, (11) Varud, (12) Bukai, (13) Zargad, (14) Khadki Sukli, (15) Dongargaon, (16) Tejani, (17) Anji, (18) Loni, (19) Borati (Forest Village), (20) Sarati, (21) Khairgaon Kasar, (22) Wardha, (23) Bhulgad, (24) Pimpalshenda, (75), (25) Atmur, (26) Sawarkhed, (27) Chonchi, (28) Wadhona, (29) Khamkund, (30) Pardi (Forest Village), (31) Umarvihir, (32) Anji, (33) Khatara, (34) Munzala, (35) Palaskund, (36) Vihirgaon, (37) Khairgaon, (38) Deodhari, (39) Singaldip, (40) Sonurli (41) Shindola, (42) Zotingdara, (43) Sakhi Khurd.

(*iii*) The one hundred three villages in Kelapur tahsil as mentioned below and town Pandharkawada:—

Kelapur tahsil:—

(1) Mohdari, (2) Jogin Kohla, (3) Mira, (4) Jira, (5) Ghoddara (Forest Village), (6) Sakhi Budruk, (7) Wadhona Khurd, (8) Zolapur (Forest Village), (9) Karanji, (10) Wadhona Budruk (11) Tiwsala (Forest Village), (12) Kothada, (13) Surdevi, (14) Chanai, (15) Asoli, (16) Mohada, (17) Karegaon, (163), (18) Chikhaldara, (19) Krishnapur, (20) Dabha, (21) Morwa, (22) Khairgaon, (199), (23) Wagholi, (24) Kusal, (25) Chopan, (26) Malkapur (Forest Village), (27) Kogaon, (28) Vadner, (29) Zuli, (30) Bhad Umari, (31) Patoda, (32) Pahapal, (33) Nagezari Khurd, (34) Bahattar, (35) Susari, (36) Naiksukali, (Forest Village), (37) Pedhari, (38) Pidpali, (39) Dongaragaon, (308). (40) Both, (41) Malegaon Khurd (Forest Village), (42) Hiwardari (Forest Village), (43) Malegaon Budruk (Forest Village), (44) Daryapur, (45) Pilwahiri, (46) Arli, (47) Hiwari, (48) Pimpalshenda, (333), (49) Karegaon, (334), (50) Wadwat, (51) Khairi, (336), (52) Ghubadi, (53) Konghara, (54) Sakhara Budruk, (55) Dharna, (56) Mangi, (343), (57) Dhoki, (344), (58) Wai, (59) Pimpalapur, (60) Ganeshpur, (347), (61) Khairgaon, (348), (62) Pandhari, (63) Niljai, (64) Maregaon, (352), (65) Ambhora (66) Dongargaon (358) (67) Pimpari, (353), (68) Khairgaon, (360), (69) Muchi, (70) Mangurda, (71) Pandharwani Budruk (Forest Village), (72) Kondhi, (73) Wedad, (74) Baggi, (75) Ghanmode, (76) Nandgaon, (77) Ganeshpur, (370), (78) Tatapur, (79) Zunzapur, (80) Gondwakadi, (81) Chalbardi, (82) Beluri, (83) Tadumari, (84) Bargaon, (377), (85) Antoli Budruk, (86) Mahandoli, (87) Sakhara, (88) Marathwakadi, (89) Dhoki, (382), (90) Ballarpur, (91) Tokwanjari, (92) Wanjari, (382), (83) Khairgaon Budruk, (94) Tembhi, (95) Radhapur (Forest Village), (96) Pilkhana (Forest Village), (97) Wasari, (98) Andharwadi, (99) Yedlapur (Forest Village), (100) Chanakha, (101) Nimdheli, (102) Rudha, (103) Sukli.

(*iv*) The fifty-five villages in Ghatanji tahsil as mentioned below :—

Ghatanji Tahsil:—

(1) Marwadi, (2) Rajurwadi, (3) Lingi, (4) Koli Khurd, (5) Koli Budruk, (6) Rampur Uncharni, (7) Kapshi, (8) Datodi, (9) Gudha, (10) Warud, (240), (11) Zaparwadi, (12) Umri, (242), (13) Palodi, (14) Kopri, (244), (15) Ghoti, (16) Bodadi, (17) Muchhati (Forest Village), (18) Jalandri, (19) Manuschhari, (20) Ayate, (21) Kap, (22) Kavatha Budruk, (23) Bilayat, (24) Khadki, (60), (25) Chimta, (26) Kopri Khurd, (27) Chincholi, (68), (28) Kinchi (Forest Village), (269), (29) Gawara (Forest Village), (30) Titwi, (31) Muradgavhan (Forest Village), (32) Pimpal Khuti (Forest Village), (33) Kharoni (Forest village), (34) Wadhona, (35) Dorli, (36) Rahati, (37) Rasa (Forest Village), (38) Zatala, (39) Chikhalwardha, (40) Tad-Sawali, (41) Saifal, (42) Nagezari Budruk, (43) Kawatha (Forest Village), (44) Parwa, (45) Mojhada, (46) Pardi, (47) Jamb, (48) Kaleshwar, (49) Shirad, (50) Dhunki (Forest Village), (51) Mathani (Forest Village), (52) Rajgaon (Forest Village), (53) Khapri (Forest Village), (54) Honegaon, (55) Ganeri.

(10) The following in Gadchiroli District :

(*a*) The tahsils of Ettapalli, Sironcha, Aheri, Dhanora, Kurkheda.

(b) (i) The sixty-two villages in Gadchiroli tahsil as mentioned below :—

Gadchiroli tahsil:—

(1) Nawgaon, (636), (2) Chak Churchura, (3) Kurhadi, (4) Chak Maushi, (5) Murmadi, (6) Bothada, (7) Palandur, (8) Gilgaon, (658), (9) Chak Kharpurdi, (10) Jepra, (11) Chak Dhibhana, (12) Marumbodi, (13) Kurkheda, (14) Khursa, (15) Visapur, (16) Sonapur, (17) Mendha, (680), (18) Sawrgaon, (683), (19) Kanori, (20) Pulkhal, (21) Mudza Budruk, (22) Mudza Tukum, (23) Krupala. (24) Masoli, (25) Ranbhumi, (26) Chandala, (27) Ranmul, (28) Kumbhi Patch, (29) Kumbhi Mokasa, (30) Made Mul, (31) Maroda, (32) Kosamghat, (33) Raipur, (718), (34) Rawanzora, (35) Pekinkasa, (36) Sawela, (37) Suimara, (38) Sakhera, (39) Karkazara, (40) Kanhalgaon, (725), (41) Keligatta, (42) Tohagaon, (43) Gajanguda, (44) Benoli, (45) Suryadongri, (46) Salaitola, (47) Bitantola, (48) Potegaon, (733), (49) Rajoli, (734) (50) Madras, (51) Jallor, (52) Devapur, (53) Ramgad, (738), (54) Gavalheti, (55) Deoda, (56) Kharadguda, (57) Talguda, (58) Jamgaon, (59) Kadsi, (60) Korkuti, (61) Nagweli, (62) Jalegaon.

(*ii*) The seventy-four villages in Armori tahsil as mentioned below :

Armori tahsil : –

(1) Koregaon, (6), (2) Kalamgaon, (3) Kural, (4) Selca Tukum, (5) Selda Lambe, (6) Kasari Tukum, (7) Kasarigaon, (8) Shivrajpur, (29), (9) Potegaon, (30), (10) Vihirgaon, (33), (11) Pimpalgaon, (12) Arat-tondi, (13) Dongargaon (Halbi), (14) Palasgaon, (43), (15) Navargaon, (16) Pathargota, (49), (17) Mangewada, (18) Armori, (19) Salmara, (20) Thanegaon, (21) Patanwada, (22) Puranawairagad, (23) Deulgaon, (69), (24) Sukala, (25) Mohazari *alias* Sakharbodi, (26) Chak Kernada, (27) Lohara, (78), (28) Chak Sonpur, (29) Hirapur, (80), (30) Dongartamsi, (31) Shiani Khurd, (32) Chavhela, (33) Mohatala Chak Kukodi, (34) Mendha, (89) (35) Dongartamsi Patch, (36) Nagarwadi, (37) Chak Naroti, (38) Chak Kurandi (39) Wadegaon, (40) Thotebodi (41) Dellanwadi, (42), Manapur, (43) Kosari, (44) Mangoda, (45) Tultuli, (46) Chaknagarwahi, (47) (Vihirgaon, (48) Kurandi, (49) Umari, (50) Yengada, (51) Pisewadadha, (52) Paraswadi, (113), (53) Dawandi, (54) Khadaki (115), (55) Bhakarandi, (56) Naroti Malgujar, (57) Koregaon, (119), (58) Warkheda, (59) Kharadi, (60) Bhansi, (61) Dorli, (62) Wanarchuwa, (63) Jambhali, (127), (64) Mendha, (128), (65) Narchuli, (66) Khairi, (67) Maregaon Patch, (68) Maregaon (140), (69) Chak Maregaon (70) Chak Chicholi, (71) Mousi Khamb, (72) Belgaon, (144), (73) Chicholi, (145), (74) Wankheda.

(*iii*) The one hundred thirty-two villages in Chamorshi tahsil as mentioned below :—

Chamorshi tahsil:—

(1) Saganpur, (758), (2) Bandhona, (764), (3) Gilgaon, (765), (4) Bhendi Kanhal, (771), (5) Thatari, (6) Chite Kanhar, (7) Kalamgaon, (8) Kurud, (9) Maler, (10) Kulegaon, (11) Nachangaon, (12) Bhadbhid, (788), (13) Walsara, (14) Chak Vispur, (15) Jogana, (16) Murmuri, (17) Rawanpalli, (18) Sonapur, (19) Darli, (20) Rekhagaon, (21) Yedanur, (22) Pailsanpeth, (23) Pandhri Bhatal, (24) Rajangatta, (25) Chak Amagaon No.1, (809), (26) Mutnur, (27) Abapur, (28) Murandapai, (29) Lenguda, (30) Adyal, (31) Karkapalli, (32) Chak Karakapalli, (33) Jangamkurul, (34) Fuser, (35) Dhekani, (36) Chak Mudholi No. 2, (37) Lakshamanpur, (38) Saganapur, (829), (39) Amboli, (40) Gahubodi, (41) Chak Narayanpur No. 2, (42) Chak Narayanpur No. 1, (43) Rajur Budruk, (44) Bhadbid, (835), (45) Manger, (46) Chichpally, (47) Wanarchuwa, (48) Jairampur, (49) Waigaon, (50) Narayanpur, (51) Rajur Khurd, (52) Haladwahi, (53) Mudholi, (54) Kothari, (845), (55) Bamhani Deo, (56) Somanpalli, (57) Kanhalgaon, (848) (58) Singela, (59) Belgatta, (60) Pethtala, (61) Chak Pethtala No. 1, (62) Pardideo, (63) Yadavpalli, (64) Rajpur, (856), (65) Jambhali Rith, (66) Meteguda, (67) Chak Belgatta, (68) Manjigaon, (69) Machhali ghot, (70) Chak Makepalli No. 4, (71) Darpanguda, (72) Chak Makepalli No. 2, (73) Chak Makepalli No. 3, (74) Garanji, (75) Chak Made Amgaon, (76) Chak Made Amgaon No. 1, (77) Chak made Amgaon No. 2, (78) Tumdi, (79) Regadi, (80) Makepalli Malgujari, (81) Borghat, (82) Ashti Nokewada, (83) Bramhanpeth, (84) Venganur, (85) Nokewada, (86) Allapalli, (87) Rengewahi, (88) Kolpalli (89) Ambela (Forest Village), (90) Gatta (Forest Village), (91) Adgepalli, (92) Surgaon (Forest Village) (93) Yellur, (94) Thakari, (95) Rajgatta, (908), (96) Lohara, (97) Mukaritola, (98) Bholkhandi (Forest Village), (99) Hetalkasa, (100) Bolepalli, (101) Pulligudam, (102) Kunghada, (103) Kolapur, (104) Gangapur, (105) Chandankhedi (106) Makra, (107) Basarwada, (108) Chaprala, (109) Chaidampatti, (110) Mukadi (Forest Village), (111) Fuski, (112) Singanpalli, (113) Dhananur, (114) Kothari, (930), (115) Ambatpalli, (116) Gomani, (117) Lagamhetti, (118) Damapur, (119) Bandukpalli, (120) Kodigaon, (121) Chichela, (122) Nagulwahi, (123), Chintugunha, (124) Tumurgunda, (125) Machingatta, (126) Yella, (127) Tikepalli, (128) Marpalli, (129) Jamgaon, (130) Kultha, (131) Rampur, (132) Lagam Chak.

(11) The following in Chandrapur District:—

The one hundred eighty-two villages in Rajura tahsil as mentioned below:—

Rajura tahsil:—

(1) Parasoda, (2) Raipur, (3) Kothoda Khurd, (4) Govindpur, (5) Kothoda Budruk, (6) Mehandi, (7) Pardi, (8) Jewra, (8), (9) Chanai Khurd, (10) Akola, (11)Korpana, (12) Durgadi, (13) Rupapeth, (14)Chanai Budruk, (15) Mandwa, (16) Kanergaon Budruk, (17) Katlabodi, (18) Shivapur, (19) Chopan, (20) Kerambodi, (21) Kukulbodi, (22) Tippa, (23) Mangulhira, (24) Khadki, (27), (25) Jamuldhara, (28), (26) Borgaon Budruk, (27) Borgaon Khurd, (28) Asapur, (29) Tangala, (30) Khairgaon, (33), (31) Hatloni (32) Yergaon, (33) Umarzara, (34) Yellapur, (35) Singar Pathar, (36) (Lambori, (37) Shedwai, (38) Narpathar, (39) Kodapur, (40) Gharpana, (41) Nokewada, (42) Gudsela, (43) Wani, (44) Kekazari, (45) Mohda, (46) Pudiyal Mohda, (47) Kamalapur, (48) Chickhkhod, (49) Wansadi, (50) Paramba, (51) Devghat, (52) Kusal, (53) Dahegaon, (54) Sonurlo, (70) (55) Kargaon Khurd, (71), (56) Dhanoli, (57) Piparda, (58) Chincholi, (59) Kargaon Budruk, (60) Markagondi, (76), (61) Belgaon, (62) Zulbardi, (63) Sawalhira, (64) Khiragaon, (80), (65) Pandharwani, (81), (66) Jambuldhara, (67) Dhanak Devi, (68) Yermi Isapur, (69) Sarangapur, (70) Jiwati, (71) Nagapur, (72) Markalmetta, (73) Dhonda Arjuni, (74) Dhondha Mandwa, (75) Teka Arjuni, (76) Teka Mandwa, (77) Rahpalli, Budruk, (78) Chikhli, (94), (79) Patan, (95), (80), Hirapur, (96), (81) Isapur, (82) Asan Khurd, (83) Asan Budruk, (84) Pipalgaon, (85) Palezari, (86) Borinavegaon, (87) Nanda, (88) Bibi (89) Dhunki, (90) Dhamangaon, (91) Kakhampur, (92) Wadgaon, (93) Injapur, (94) Chandur, (95) Kukadsat, (96) Khirdi, (97) Thutra, (98) Behlampur, (99) Manoli Khurd, (100) Jamani, (101) Nokari Budruk, (102) Sonapur, (103) Upparwai, (104) Bhurkunda Khurd, (105) Kaadki, (150), (106) Nokari Khurd, (107) Nagrala, (108) Palezari, (109) Kakban, (110) Dongargaon (155), (111) Chikhali, (156), (112) Bhurkhunda Budruk, (113) Pachgaon, (114) Sangaon, (159), (115) Tatakohadi, (116) Bhendvi, (117) Sukadpalli, (118) Markagondi, (119) Titvi, (120) Nadpa, (121) Yergavan, (122) Kawadgondi, (123) Sorakasa, (124) Kusumbi, (125) Jankapur, (126) Punaguda (Navegaon), (127) Dewada, (128) Khadki Raipur, (129) Govindpur, (130) Maraipatan, (131) Umarzara, (176) (132) Rahpalli Khurd,

(133) Dharmaram, (134) Bhoksapur, (135) Bambezari, (136) Bhari, (137) Pandarwani, (182) (138) Sindola, (139) Sondo, (140) Belgaon, (185), (141) Kakadghat, (142) Ganeri,(143) Khirdi, (144) Sedwai, (145) Babapur, (146) Hirapur, (200) (147) Sakhari, (148) Manoli Budruk, (149) Goyegaon, (150) Hardona Khurd, (151) Hardona Budruk, (152) Winirgaon, (224) (153) Magi, (154) Wangi, (155) Pandharpouni, (227), (156) Aheri, (157) Kochi, (158) Goraj, (159) Warur, (160) Raniweli, (161) Bhedoda, (162) Tembhurwahi (163) Chirud, (164) Chinchbodi, (165) Kawthala, (166) Sonurli, (167) Sirsi, (168) Berdi, (169) Bhenthala, (249), (166) Sonurli, (167) Sirsi, (168) Berdi, (169) Bhendala, (170) Kelzari. (171) Navegaon, (265), (172) Chinchala, (173) Wirur, (174) Siddheshwar, (175) Ghotta, (176) Dongargaon, (269), (177) Subai, (178) Kostala, (179) Lakkadkot (180) Ambezari, (181) Antargaon ,(277) (182) Annur.

3. Any reference in the preceding paragraph 2 to a territorial division by whatever name indicated shall be construed as a reference to the territorial division of that name as existing at the commencement of this Order.

ZAIL SINGH,

President.

[No. F. 19(2)/85-L.I]

R.V.S. PERI SASTRI, Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1985

अनुसूचित क्षेत्रातील पेसा गावांची माहिती - तालुका -अकोले, जिल्हा- अहमदनगर					
अ.क्र.	English	अनुसूचित क्षेत्रात समाविष्ट असलेल्या ग्रामपंचायतींची नावे	पंचायतीमध्ये समाविष्ट असलेल्या गावांची नावे	गावाची एकूण लोकसंख्या (२०११ नुसार)	आदिवासींची एकूण लोकसंख्या (२०११ नुसार)
१	Abitkhind	अबितखिंड		७३२	६९५
२	Ambevangan	अंबेवंगण		७६५	७४६
३	Ambit	आंबीत		६९२	६५४
			शिरपुंजे खु.	३२४	३२३
४	Babulwandi	बाभूळवंडी		१४७७	१२२३
५	Bari	बारी		१०७३	९९१
६	Bhandara	भंडारदरा		१७६५	१३३५
७	Chichondi	चिचोंडी		१६६३	१५२५
८	Chinchavane	चिंचावने		१२६४	१११४
९	Damanvan	धामणवण		१२९९	१२४७
१०	Deogaon	देवगाव		११६०	१०८५
११	Digambar	दिगंबर		७३३	६८४
१२	Ekdare	एकदरे		६४७	६४४
१३	Ghatghar	घाटघर		११७६	८५९
१४	Ghoti	घोटी		७५९	७२०
१५	Gondoshi	गोंदुशी		९०९	८८९
			माणिक ओझर	६१५	५६९
			बलठण	१०३२	१०३२
१६	Guhire	गुहिरे		९३२	८६९
१७	Jamgaon	जामगाव		७५९	४६७
१८	Jaynawadibetika	जायनावाडी	**बिताका**	२१२	०
१९	Kaliruhanwadi	केळी रुम्हणवाडी		२३७८	१४३०
२०	Karandi	करंडी		११७२	१०२७
२१	Katalapur	कातळापूर		१४८१	११२३
२२	Keli Kotul	केळी कोतूळ		११९२	१०९२
२३	Keli Otur	केळी ओतूर		१०५५	८६३
२४	Kelungan	केळुंगण		१४४०	१४३०
२५	khdaki kh	खडकी खु.		७७७	६६९
२६	Khirvare	खीरविरे		३२०४	१८१७
२७	Kobalne	कोंभाळणे		१२८१	३५७
२८	Kohane	कोहणे		९८७	९०४
२९	Kohondi	कोहंडी		१३०४	१२१४
३०	Koltambe	कोलटेंभे		५०५	४९२
३१	Kondni	कोदणी		३७५	३३०

३२	Kumshet	कुमशेत		६६७	६५२
३३	Ladgaon	लाडगाव		६५३	५७३
३४	Lavhali Otur	लव्हाळी ओतूर		४२६	४०६
			लव्हाळी कोतूळ	४६८	४५०
			कोथळे	७३२	७१९
			वागदरी	६१४	५८१
३५	Mahnar	मान्हेरे		२०५७	१८७८
३६	Malegaon	माळेगाव		८६६	८३९
३७	Maveshi	मवेशी		६६३	६२८
३८	Mhalugi	म्हाळुंगी		१०१२	७२९
३९	Mnyale	मण्याळे	**पिसेवाडी**	७४१	५१८
४०	Murshet	मुरशेत		८८८	७५८
४१	Muthalane	मुथाळणे		११९७	५२७
४२	Mutkhal	मुतखेल		१४१७	१३११
४३	Pachanai	पाचनई		६९६	६९६
४४	Padalane	पाडाळणे		१८८५	१२३२
४५	Padoshi	पाडोशी		१४४९	१३४६
४६	Paithan	पैठण		१७७८	१००६
४७	Palsunde	पळसुंदे		१४४०	१३६५
			फोफसंडी	८९३	८७५
४८	Panjare	पांजरे		१५४५	१५१३
४९	Pendshet	पेंडशेत		७४६	६०३
५०	Pimparkane	पिंपरकणे		१६०४	१५२१
५१	Rajur	राजूर		१००४६	४०४३
५२	Ranad BK	रणद बु.		११२३	११०८
			रणद खु.	२३९	२१९
५३	Ratanwadi	रतनवाडी		१११८	११०१
५४	Shenit Kh.	शेणीत खु.		१२५४	११७३
			पाभूळवंडी	७००	५६६
५५	Sakirwadi	साकीरवाडी		१३२९	१२९२
५६	Samrad	साम्रद		७८९	७३१
५७	Samsherpur	समशेरपूर		४८८३	१३००
५८	Sangavi	सांगवी		११३१	१०५६
५९	Satewadi	सातेवाडी		१६६०	१५८३
			खेतेवाडी	५७८	५३४
			येसरठाव	५८८	५५३
६०	Savarkute	सावरकुटे		१२५२	११०५
६१	Sawargaon Pat	सावरगाव पाट		२२४८	४०७
६२	Selad	शेलद		१८००	१२०६
६३	Shailvandi	शिळवंडी		५३८	५२२
६४	Shelvihire	शेलविहीरे		११३५	१०६७
६५	Sherpunje bk	शिरपुंजे बु.		१५७२	१५१९
६६	Shinganwadi	शिगणवाडी		९३६	८९०

६७	Shiswad	शिसवद		८१०	७६३
६८	Shendi	शेंडी		१८४२	१३१२
६९	Somalwadi	सोमलवाडी		६०६	६००
७०	Tahakari	टाहाकरी		१८४१	२९४
७१	Tarde	तिरडे		१६१५	१४८१
७२	Tela	तळे		६२३	५६९
			शिंदे	१८५	१८३
			विहीर	४९६	४३५
			पिंप्री	५६६	४९६
७३	Terungan	तेरुंगण		१०२१	९८९
७४	Titavi	टिटवी		९३५	८९१
७५	Udadawane	उडदावणे		१५३९	१४३७
७६	Vitha	विठा		१५००	८३८
७७	Waki	वाकी		९५१	८२३
७८	Wanjulshet	वांजळशेत		८९७	६८५
			पुरुषवाडी	६२६	६१४
७९	Wargushi	वारंघुशी		३११९	२७५८
एकूण सख्या (ग्रा.प. ७९ + गावे १५ = एकूण पेसा गावे- ९४)				**११६४६७**	**८८२८८**

टीप: उपरोक्त अनुक्रमे अनुक्रमांक १८ (बिताका) व ३९ (पिसेवाडी) हि दोन गावे पेसा अंतर्गत येतात. परंतु यांच्या ग्रामपंचायत या पेसा अंतर्गत येत नाहीत.

RNI No. MAHBIL /2009/37831
Reg. No. MH/MR/South-339/2014–16

सत्यमेव जयते

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

असाधारण भाग चार–ब

वर्ष ५, अंक १३२ (२)] **मंगळवार, मार्च ४, २०१४/फाल्गुन १३, शके १९३५** **[पृष्ठे ३०, किंमत : रुपये ९.००**

असाधारण क्रमांक ३३

प्राधिकृत प्रकाशन

महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र अधिनियमांन्वये तयार केलेले
(भाग एक, एक-अ आणि एक-ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त) नियम व आदेश.

ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग

बांधकाम भवन, २५, मर्झबान पथ, फोर्ट, मुंबई-४०००0१.

दिनांक ४ मार्च २०१४.

अधिसूचना

महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम.

क्रमांक. पीआरआय.२०१०/प्र.क्र.१३०/पं.रा-२.—ज्याअर्थी, संसदेने, संविधान (त्र्याहत्तरावी सुधारणा) अधिनियमाद्वारे समाविष्ट केल्याप्रमाणे, भारतीय संविधानाच्या भाग नऊ च्या तरतुदी ह्या, पंचायतीसंबंधीचे उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रांवर विस्तारित करणे) अधिनियम, १९९६ (१९९६ चा ४०) अधिनियमित करून लागू केल्या आहेत.

आणि ज्याअर्थी, उक्त केंद्रीय अधिनियमाच्या अनुरुप, महाराष्ट्र राज्य विधानमंडळाने, मुंबई ग्रामपंचायत आणि महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समिती (सुधारणा) अधिनियम, २००३ (२००३ चा २७) अधिनियमित करून आणि वेळोवेळी इतर सुधारणा अधिनियम अधिनियमित करून त्याद्वारे, महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम (१९५९ चा ३) यामध्ये अनुसूचित क्षेत्रातील ग्रामसभा आणि पंचायत यांसाठी विशेष तरतुदी असलेले प्रकरण तीन-अ समाविष्ट केले आहे.

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमात उक्त सुधारणा समाविष्ट केल्यानंतर त्याद्वारे, अनुसूचित क्षेत्रातील लोकांच्या परंपरा व रुढी, त्याची सांस्कृतिक ओळख, सामूहिक साधनसंपत्ती आणि तंटा निवारणाची रुढ पद्धती आणि गौण वनोत्पादनावरील मालकी, इत्यादींचे रक्षण व जतन करण्यासाठी अनुसूचित क्षेत्रातील ग्रामसभांना आणि पंचायतींना अधिकार प्रदान केले आहेत.

आणि त्याअर्थी, स्वयंशासनाला चालना देणा-या मुंबई ग्रामपंचायत आणि महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समिती (सुधारणा) अधिनियम, २००३ याची अमंलबजावणी करून त्याद्वारे, अनुसूचित क्षेत्रात राहणा-या लोकांच्या हितसंबंधांचे रक्षण करण्याचे आणि त्या प्रयोजनार्थ, त्यासंबंधीचे प्रभावी अंमलबजावणी सुनिश्चिती करण्याचे मुख्य कार्य ग्रामसभांना देणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.

त्याअर्थी, आता महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम (१९५९ चा ३) याच्या कलम १७६ च्या पोटकलम (२) चा खंड (सत्तेचाळीस) व प्रकरण तीन-अ मधील कलमे ५४अ, ५४ब, ५४क, ५४ड, कलम ५७ च्या पोटकलम (२) चा खंड (फ अ) आणि कलम १५३ ब यांद्वारे प्रदान केलेल्या अधिकारांचा आणि याबाबतीत त्यास समर्थ करणा-या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून, महाराष्ट्र शासन पुढील नियम करीत आहे. हे नियम उक्त अधिनियमाच्या कलम १७६ च्या पोटकलम (४) द्वारे आवश्यक असल्याप्रमाणे अगोदरच प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत :—

प्रकरण एक

प्रारंभिक

१. संक्षिप्त नाव व प्रारंभ :—(१) या नियमांना, महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रांवर विस्तारित करण्याबाबत) नियम, २०१४ असे म्हणावे.

(२) ते, जेथे अधिनियम अंमलात आहे राज्यातील अशा, सर्व अनुसूचित क्षेत्रांना लागू असेल.

२. व्याख्या :

(१) या नियमामध्ये, संदर्भानुसार दुसरा अर्थ अपेक्षित नसेल तर,—

(क) " अधिनियम " याचा अर्थ, महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम (१९५९ चा ३) असा आहे.

(ख) " प्रपत्र " याचा अर्थ नियामांसोबत जोडलेले प्रपत्र

(ग) " शासन " याचा अर्थ, महाराष्ट्र शासन असा आहे.

(घ) " ग्रामसभा " याचा अर्थ, ग्रामस्तरावरील पंचायतीच्या मतदार यादीमध्ये ज्यांची नावे समाविष्ट केलेली आहेत अशा सर्व व्यक्तींची मिळून बनलेली, अनुसूचित क्षेत्रातील ग्रामसभा, असा आहे.

(ङ) " सचिव " याचा अर्थ ग्राम पंचायत अधिनियमाच्या कलम ६० अन्वये नियुक्त केलेला किंवा नियुक्त केला आहे असे मानला जाणारा सचिव.

(च) " राज्य " याचा अर्थ, महाराष्ट्र राज्य आहे.

(२) या नियमामध्ये वापरण्यात आलेले परंतु व्याख्या न केलेले शब्द व शब्दप्रयोग यांना, महाराष्ट्र जमीन सुधारणा योजना अधिनियम (१९४२ चा २८); महाराष्ट्र सावकारी नियमन अध्यादेश, २०१४, (२०१४ चा अध्यादेश क्रमांक १) महाराष्ट्र दारूबंदी अधिनियम (१९४९ चा २५) ; महाराष्ट्र्र पोलीस अधिनियम (१९५१ चा २२); महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम (१९५९ चा ३); महाराष्ट्राचा मासेमारीबाबत अधिनियम १९६० (१९६१ चा महा-१); महाराष्ट औद्योगिक विकास अधिनियम, १९६१ (१९६२ चा महा-३); महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ (१९६२ चा महा-५). महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ (१९६६ चा महा.४१); महाराष्ट्र गौण वनोत्पादन (व्यापाराचे विनियमन) अधिनियम, १९६९ (१९६९ चा महा.५७); महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास अधिनियम, १९७६ (१९७७ चा महा-२८); महाराष्ट्र पाटबंधारे अधिनियम, १९७६ (१९७६ चा महा-३८); महाराष्ट्र वनविकास (शासनाकडून अथवा वनविकास महामंडळाकडून होणा-या वनोत्पादनाच्या विक्रीवरील कर) (चालू राहणे) अधिनियम, १९८३ (१९८३ चा महा २२); महाराष्ट्र अनुसूचित क्षेत्रांतील गौण वनोत्पादनाच्या मालकीचे हस्तांतरण व महाराष्ट्र गौण वनोत्पादन (व्यापाराचे विनियमन) (सुधारणा) अधिनियम, १९९७ (१९९७ चा महा. ४५), अनुसूचित जमाती आणि इतर पारंपारिक वननिवासी (वनहक्काची मान्यता) अधिनियम, २००६, (२००७ चा २)जैविक विविधता अधिनियम, २००२ (२००३ चा १८) यांमध्ये अनुक्रमे जे अर्थ नेमून दिलेले असतील, तेच अर्थ असतील.

प्रकरण दोन

ग्रामसभेची रचना व कार्ये

३. अनुसूचित क्षेत्रातील ग्रामसभेची रचना :—ग्रामस्तरावरील पंचायतीच्या मतदार यादीमध्ये नाव समाविष्ट असलेल्या सर्व व्यक्ती ह्या, त्या गावाच्या ग्रामसभेचे सदस्य असतील.

४. अनुसूचित क्षेत्रातील गाव घोषित करणे :—(१) आपल्या वस्तीची किंवा वस्तींच्या गटाची अथवा पाड्याची किंवा पाड्यांच्या गटाची गाव म्हणून नोंद केली जावी असे कोणत्याही वस्तीच्या किंवा वस्तींच्या गटाच्या अथवा पाड्याच्या किंवा पाड्यांच्या गटाच्या व्यक्तींचे मत झाले असेल तर, त्या व्यक्तींना, त्या वस्तीच्या किंवा पाड्याच्या अथवा वस्तींच्या किंवा यथास्थिति, पाड्यांच्या गटाच्या मतदार यादीत नाव नोंदवलेल्या एकूण मतदारांपैकी किमान निम्म्या मतदारांच्या बहुमताने तशा आशयाचा ठराव संमत करता येईल आणि त्याबाबतची माहिती जिल्हाधिका-याला कळवून तो ठराव संबंधित उप विभागीय अधिका-याकडे पाठवता येईल.

(२) उप-विभागीय अधिकारी, ३ महिन्यांच्या आत त्या ठरावाच्या गुणदोषांची चौकशी करील. या प्रयोजनासाठी तो, या बाबीस व्यापक प्रसिद्धी दिल्यानंतर व सर्व संबंधित घटकांशी विचारविनिमय करून, त्या वस्तीच्या किंवा पाड्याच्या अथवा वस्तींच्या किंवा पाड्यांच्या गटाच्या सर्व नोंदणीकृत मतदारांची एक बैठक बोलावील. त्यानंतर तो प्रस्तावित गाव त्या अधिनियमाच्या तरतुदींची पूर्तता करते किंवा कसे याबाबत स्पष्टपणे नमूद करून, आपल्या निष्कर्षासह एक अहवाल जिल्हाधिका-याला सादर करील :

परंतु, उप विभागीय अधिका-याने असा ठराव मिळाल्याच्या दिनांकापासून तीन महिन्यांच्या आत त्याबाबतच्या प्रश्नावर निर्णय केला नसेल तेव्हा जिल्हाधिकारी स्वतःहून अशा ठरावाची दखल घेईल आणि त्या संबंधात ४५ दिवसांत समुचित आदेश काढील.

(३) असा निर्णय फेटाळून लावणा-या उप विभागीय अधिका-याच्या निर्णयाविरुद्धचे अपील जिल्हाधिका-यांकडे करण्यात येईल व जिल्हाधिका-यांचा त्यावरील निर्णय अंतिम राहील.

(४) नवीन गाव हे आधिसूचित करावयाचे आहे याबाबत जिल्हाधिका-यांची खात्री पटली असेल तर तो त्या अधिनियमाच्या प्रकरण तीन-अ प्रमाणे अधिसूचना काढण्यासाठी विभागीय आयुक्ताकडे आपली शिफारस पाठवील ;

परंतु, जिल्हाधिकारी, उप विभागीय अधिका-याचा निर्देश मिळाल्याच्या दिनांकापासून पंचेचाळीस दिवसांच्या आत त्यावर निर्णय देईल, तसे न केल्यास, त्याबाबतीत गाव जाहीर केल्याची मान्यता देण्यात आली असल्याचे समजण्यात येईल.

५. **पंचायत ही ग्रामसभेची कार्यकारी समिती असणे :—**(१) पंचायतीला ग्रामसभेची कार्यकारी समिती असल्याचे मानण्यात येईल.

(२) पंचायत ही ग्रामसभेचे सर्वसाधारण अधीक्षण, नियंत्रण व निदेश यानुसार कार्य करील.

६. **अनुसूचित क्षेत्रातील ग्रामसभेचा सचिव कार्यालय इत्यादी :—**(१) एखाद्या पंचायतीत एकापेक्षा अधिक ग्रामसभा असतील तर अशा परिस्थितीत, ग्रामपंचायतीचा सचिव हा त्या सर्व ग्रामसभांचा सचिव असेल, त्याच्या अनुपस्थितीत महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमातील प्रकरण ३ मधील ५४ क प्रमाणे कार्यवाही करण्यात येईल.

(२) पंचायतीचे कार्यालय हेच ग्रामसभेचे कार्यालय असेल. एका पंचायतीमध्ये एकापेक्षा अधिक ग्रामसभा असतील तर, प्रत्येक ग्राम सभेचे तिच्या गावामध्ये सार्वजनिक इमारत, समाजमंदीर, शाळा किंवा जेथे जनतेला सहज प्रवेश मिळेल अशी कोणतीही जागा आणि अशी कोणतीही जागा उपलब्ध नसेल तर त्याबाबतीत एखाद्या सामान्य व्यक्तीचे घर, यासारखे तिचे स्वतःचे कार्यालय असेल.

परंतु, या कार्यालयासाठी कोणत्याही प्रकारचे भाडे दिले जाणार नाही :

७. **ग्रामसभेच्या बैठकी खुल्या स्वरुपात घेणे :—**(१) ग्रामसभेची प्रत्येक बैठक किंवा कार्यवाही जाहीरपणे आयोजित करण्यात येईल.

(२) ग्रामसभेची बैठक बंदिस्त इमारतीमध्ये घेण्यात येणार असली तरी, दरवाजे बंद ठेवण्याची किंवा प्रवेश बंद करण्याची कोणतीही तरतूद केली जाणार नाही.

८. निर्णय घेण्याबाबतची कार्यपद्धती :—(१) शक्य तेथवर ग्रामसभेचे कामकाज सर्वसंमतीने चालविण्यात येईल.

(२) बैठकीमध्ये कोणत्याही मुद्यावर एकमत न झाल्यास त्या मुद्यावर ग्रामसभेने तरतुदीनुसार ठरविल्याप्रमाणे घेण्यात येणा-या पुढील बैठकीमध्ये चर्चा करण्यात येईल.

(३) दुस-या बैठकीतदेखील एकमत न झाल्यास त्या बैठकीत बहुमताच्या आधारे निर्णय घेतला जाईल.

९. **ग्रामसभेच्या बैठकीची कार्यवाही :—**(१) निवडणुकीनंतर आणि प्रत्येक वित्तीय वर्षामध्ये पहिली ग्रामसभा सरपंचाच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात येईल. सरपंचाच्या अनुपस्थितीत उप सरपंच आणि त्या दोघांच्या (सरपंच व उप सरपंच) अनुपस्थितीत अनुसूचित जमातीचा सदस्य हा ग्रामसभेचा अध्यक्ष म्हणून निवडला जाईल. पंचायतीचा सरपंच किंवा उप सरपंच किंवा सदस्य हा वरील परिस्थितीव्यतिरिक्त एरव्ही ग्रामसभेचा अध्यक्ष म्हणून काम करण्यास पात्र असणार नाही :

परंतु ज्या गावामध्ये अनुसूचित जमातींची लोकसंख्या १० टक्यांपेक्षा कमी असेल तेथे, अनुसूचित जमातीतील नसलेल्या व्यक्तींमधून अध्यक्ष निवडता येईल.

(२) या नियमाच्या पोट-नियम (१) मध्ये नमूद केलेल्या बैठकी व्यतिरीक्त ग्रामसभेच्या बैठकीसाठी अध्यक्षाची निवड शक्य तेथवर सर्वसंमतीने करण्यात येईल. सर्वसंमती न झाल्यास, त्यावर बहूमत घेण्यात येईल केवळ अनुसूचित जमातींतील व्यक्ती हीच अध्यक्ष असेल.

(३) ग्रामसभेच्या बैठकीची गणपूर्ती एकूण सदस्यांच्या २५ टक्के किंवा १०० यापैकी जी कमी असेल त्या संख्येएवढी असेल.

(४) गणपूर्तीच्या अभावी बैठक तहकूब करण्यात येईल. तहकूब केलेल्या बैठकीनंतर बोलावण्यात आलेल्या बैठकीत देखील गणपूर्ती आवश्यक असेल.

(५) सचिव, ग्रामसभेच्या बैठकीमध्ये मागील महिन्यातील प्राप्ती व खर्च, कामगारांचा हजेरीपट खरेदी व विक्री यांच्या संपूर्ण अभिलेखाचे सविस्तर विवरणपत्र सादर करील.

(६) बैठकीची समाप्ती करताना सचिव हा ग्रामसभेने नामनिर्देशित केलेली व्यक्ती ग्रामसभेमध्ये घेण्यात आलेल्या निर्णयांचे संक्षिप्त विवरणपत्र तयार करील. ते विवरण पत्र त्या बैठकीमध्ये वाचून दाखविण्यात येईल. विवरणपत्राच्या खरेपणाबाबत एकमत झाल्यानंतर अध्यक्ष आणि सचिव आणि लेखनिक त्यावर स्वाक्षरी करतील.

१०. अनुसूचित क्षेत्रातील ग्रामसभेच्या स्थायी समित्या :—(१) ग्रामसभा गावाच्या कारभाराविषयीच्या विविध पैलुंबाबतच्या आपल्या जबाबदा-या पार पाडण्याच्या दृष्टीने शांतता समिती, न्याय समिती, साधनसंपत्ती नियोजन व व्यवस्थापन समिती, मादकद्रव्य नियंत्रण समिती, कर्ज नियंत्रण समिती, बाजार समिती, ग्रामसभाकोष समिती आणि ग्रामसभेस उचित वाटतील अशा इतर समित्या स्थापन करील. याशिवाय गरजेअनुसार तात्पुरती व तदर्थ अशा समित्यादेखील स्थापन करता येतील. ह्या समित्या ग्रामपंचायत व ग्रामसभा अशा दोन्हींना देखील उत्तरदायी असतील.

(२) स्थायी समितीचे सदस्य ग्रामसभा बैठकीमध्ये उपस्थित सदस्यांमधून निवडण्यात येतील. ग्रामसभेच्या कामाचे स्वरुप व आवश्यकता यावर अशा सदस्यांची निवड अवलंबून राहील. ग्रामसभा एकूण सदस्य आणि महिलांचे व समाजातील इतर घटकांचे प्रतिनिधित्त्व याबाबतची संख्या ठरवील. स्थायी समितीचा कार्यकाळ दोन वर्षे इतका असेल :

परंतु, कोणत्याही समितीच्या एकूण सदस्यांच्या निम्मेपेक्षा महिलांची संख्या कमी असणार नाही.

(३) स्थायी समितीच्या अध्यक्षाचे, नामनिर्देशन हे ग्रामसभेकडून संबंधित स्थायी समितीच्या सदस्यांमधून करण्यात येईल.

(४) स्थायी समितीच्या सचिवाची निवड ही, ग्रामसभेकडून करण्यात येईल. ग्रामसभेस संबंधित प्रशासकीय विभागाच्या सल्ल्याने स्थायी समितीचे काम करण्यासाठी त्या ग्रावाच्या अधिकारितेतील कोणत्याही कर्मचा-यास देखील नामनिर्देशित करता येईल. अशा कर्मचा-यास मत देण्याचा अधिकार नसेल आणि तो स्थायी समितीला तिचे कामकाज पार पाडण्यास सहाय्य करील.

(५) ग्रामसभेने विविध विषयांवर घेतलेल्या निर्णयांची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी ही, संबंधित स्थायी समितीवर असेल.

११. ग्रामसभेच्या स्थायी समितीची कार्यपद्धती :—ग्रामसभेच्या स्थायी समितीची कार्यपद्धती ग्रामसभेप्रमाणेच असेल ती पुढीलप्रमाणे असेल :—

(१) ग्रामपंचायतीसह सर्व स्थायी समित्यांच्या बैठकी खुल्या स्वरुपात होतील.

(२) स्थायी समितीच्या प्रत्येक बैठकीचा दिनांक, वेळ व ठिकाण आणि तीमध्ये करण्यात येणारे कामकाज अशा प्रत्येक बैठकीची नोटीस स्थायी समितीच्या सचिवाकडून किमान तीन दिवस अगोदर देण्यात येईल.

(३) स्थायी समितीच्या बैठकीची गणपूर्ती, अध्यक्षासह निम्म्यासंख्येएवढी असेल.

(४) ग्रामसभेच्या सदस्यास स्थायी समितीच्या कोणत्याही बैठकीस उपस्थित राहता येईल. अध्यक्षाच्या परवानगीने त्याला चर्चेच्या विषयावर कोणताही प्रश्न विचारता येईल :

परंतु त्याला किंवा अशा सदस्याला मतदान करण्याचा अधिकार असणार नाही.

(५) स्थायी समितीचे सर्व निर्णय, ग्रामसभेला लागू असलेल्या कार्यपद्धतीअनुसार घेण्यात येतील.

(६) स्थायी समितीच्या बैठकीमध्ये घेण्यात आलेल्या महत्त्वाच्या निर्णयांचा गोषवारा, कामकाज नोंदवहीमध्ये नोंदवून घेण्यात येईल आणि अशा बैठकीच्या कार्यवृत्तांवर अध्यक्ष व सचिव स्वाक्षरी करतील.

(७) स्थायी समित्यांचे सर्व निर्णय आणि इतर अभिलेख हा, त्या गावाच्या ग्रामसभेच्या लगेच पुढच्या बैठकीपुढे ठेवण्यात येईल.

१२. ग्रामसभेने घेतलेल्या निर्णयाविरुद्ध आक्षेप :—(१) पंचायत व ग्रामसभा यांचा सर्व अभिलेख सर्व ग्रामस्थांसाठी खुला असेल. पंचायत समितीने, जिल्हा परिषदेने आणि शासनाने पदनिर्देशित केलेल्या प्राधिका-यास तो अभिलेख तपासणी, छाननीकरिता उपलब्ध करून देण्यात येईल.

(२) आक्षेपाला ग्रामसभेने घेतलेल्या कोणत्याही निर्णयाविषयी घेतलेल्या कोणताही आक्षेप हा पुनर्विचारार्थ ग्रामसभेच्या सर्वसाधारण सभेमध्ये उपस्थित करता येईल.

(३) आक्षेप दूर करण्यासाठी ग्रामसभेला सहाय्य करण्याकरिता अभीक्षक असणे आवश्यक आहे असे आक्षेपकांचे अथवा अन्य कोणत्याही व्यक्तीचे मत असेल तर, त्याला अभीक्षकाने ग्रामसभेच्या बैठकीस उपस्थित राहण्याबाबत अभीक्षकाची नियुक्ती करण्याकरिता गट विकास अधिका-याला विनंती करता येईल.

(४) अभीक्षकाची आवश्यकता असल्याबाबत गट विकास अधिका-याची खात्री पटल्यास त्याला आक्षेपकाच्या सूचनेनुसार ग्रामसभेच्या बैठकीकरिता अभीक्षकास विस्तार अधिका-याच्या दर्जापेक्षा कमी नाही असा अधिकारी नियुक्त करता येईल.

(५) अशा प्रकारे नियुक्त केलेला अभीक्षक, आक्षेपकाच्या गा-हाण्यांचे निवारण करण्यात सहाय्य करील.

(६) तक्रारीचे निवारण न झाल्यास, आक्षेपकास अथवा अभीक्षकास ती बाब जिल्हापरिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिका-याकडे निर्दिष्ट करता येईल व तो त्या आक्षेपकास संबंधित बाबीची चौकशी करून आवश्यक त्या सूचना देईल.

१३. अनुसूचित क्षेत्रातील ग्रामसभांच्या संयुक्त बैठकी :—(१) प्रत्येक ग्रामसभा तिच्या अधिकारितेमध्ये तिची कार्ये पार पाडण्यास सक्षम असेल :

परंतु इतर ग्रामसभांबरोबर काम करणे आवश्यक आहे, अशा प्रकरणांमध्ये पंचायतीच्या अधिकारितेअंतर्गत येणा-या सर्व ग्रामसभांची एक संयुक्त बैठक बोलाविता येईल.

(२) ग्रामसभांची संयुक्त बैठक ही जणू काही त्या संबंधित ग्रामसभा ही एकच संस्था असल्याप्रमाणे, ग्रामसभेला लागू असलेल्या तरतुदी नुसार घेण्यात येईल.

(३) संयुक्त बैठकीमध्ये शक्य असेल तेथवर सर्वसंमतीने निवडून आलेली व्यक्ती त्या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी असेल.

(४) संयुक्त बैठकीमध्ये प्रत्येक ग्रामसभेचे किमान २५ टक्के सदस्य किंवा प्रत्येक ग्रामसभेचे शंभर सदस्य यापैकी जी कमी असेल तेवढी उपस्थिती बंधनकारक असेल. बैठकीत गणपूर्ती न झाल्यास, त्याच दिवशी पुढील बैठकीचा दिनांक निश्चित केला जाईल आणि तो सर्व ग्रामसभांना पाठविण्यात येईल.

(५) निर्णय प्रक्रिया ही, एकल ग्राम सभेमधील निर्णय प्रक्रियेप्रमाणेच असेल.

प्रकरण तीन

ग्रामसभा लेखे

१४. अनुसूचित क्षेत्रातील ग्रामसभा कोष :—(१) ग्रामसभा एक ग्रामसभा कोष ठेवील.

(२) या कोषामध्ये रोख रक्कम व माल यांसारख्या ऐच्छिक अंशदानासह कोणत्याही रुपामध्ये प्राप्त झालेले अंशदान आणि गौण वन उपज, गौण खनिजे इत्यादी पासून मिळालेली रक्कम आणि ग्रामसभेने साधनसंपत्तीच्या वापरावर लादलेले आकार किंवा आकारलेला द्रव्यदंड यांचा समावेश असेल. यामध्ये शासनाला आवश्यक वाटेल त्याप्रमाणे कोणत्याही प्रकांती योजनेखाली हस्तांतरित केलेल्या बाबींचाही समावेश असेल.

(३) हा ग्रामसभा कोष, ग्रामसभेच्या नियंत्रणाखाली असेल. ग्रामसभेला तिच्या ठरावांनुसार कोषाचा वापर करण्याचे संपूर्ण अधिकार असतील.

(४) ग्रामसभा कोष हा पंचायतीचा सचिव व ग्रामसभेने सर्वानुमते नामनिर्देशित केलेले इतर दोन सदस्य यांचा समावेश असलेल्या ग्रामसभा कोष समितीद्वारे चालवण्यात येईल. दोन सदस्यांपैकी एक सदस्य ही महिला असेल. सर्व लेखे माहितीसाठी व अंतिम मंजुरीसाठी ग्रामसभेसमोर मांडण्यात येतील.

१५. ठेवावयाचे लेखे :—(१) ग्रामसभा कोषाचे लेखे हे ग्रामसभा कोष समितीच्या सदस्याकडून एका नोंदवहीत ठेवण्यात येतील.

(२) ग्रामसभा कोषाच्या जमा व खर्चाचे विवरणपत्र ग्रामसभेच्या पुढील बैठकीत सादर करण्यात येईल.

१६. ग्रामसभा निहाय लेखे :—प्रत्येक ग्रामसभा जमा व खर्चाचा एक स्वतंत्र लेखा ठेवील. तो लेखा संबंधित ग्रामसभेकडून प्रमाणित करण्यात येईल. ग्रामसभा कोषाचे व पंचायतीचे लेखे, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद व स्थानिक निधी प्राधिकारी यांच्या लेखापरिक्षणाच्या अधीन असतील :

परंतु ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग, पारदर्शकता व उत्तरदायित्व यांची सुनिश्चिती करण्यासाठी नियम प्रसिद्ध केल्याच्या दिनांकापासून एका वर्षाच्या आत, ग्रामसभा कोषाच्या अभिलेखांचे इलेक्ट्रॉनिक परिरक्षण करण्यासह लेखांकनाअनुदेश प्रशिक्षण देणे व त्याबाबतीत तरतूद करणे यांसाठी प्रयत्न करील.

प्रकरण चार

शांतता व सुरक्षा आणि तंटामुक्ती

१७. अनुसूचित क्षेत्रामध्ये शांतता, सुरक्षा राखण्यामध्ये व तंटामुक्तीसाठी ग्रामसभेची भूमिका :—समाजातील परंपरा आणि संबंधित कायदे व त्याखालील संबंधित नियम लक्षात घेता, ग्रामसभेने तिच्या क्षेत्रात शांतता, सुरक्षा व सुव्यवस्था राखणे हे ग्रामसभेचे मूलभूत कर्तव्य असेल.

(१) ग्रामसभा तिच्या क्षेत्रात पुढील कार्ये /कामे करण्यासाठी सक्षम असेल :—

(एक) शांततापूर्ण वातावरण ठेवणे ;

(दोन) प्रत्येक नागरिकाच्या स्वाभिमानाची व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची जोपासना करण्याबाबत उपाययोजना करणे ;

(तीन) महिलांशी असभ्य वर्तणूक, सार्वजनिक ठिकाणी मारामा-या किंवा भांडणे इत्यादीसह समाजविघातक घटकांसारख्या दुष्ट प्रवृत्तींना पायबंद घालणे, तंटे मिटविणे.

१८. शांतता समिती :—(१) ग्रामसभेला शांतता समिती घटीत करता येईल, शांतता समितीमध्ये किमान ३३ टक्के महिला आणि ५० टक्के अनुसूचित जमातीतील सदस्य असतील.

(२) शांतता समिती शेजारच्या गावांबरोबर निकोष संबंध ठेवील. शांतता समिती शेजारच्या गावांचे सामाईक हित व परस्परावलंबित या बाबींमध्ये शेजारच्या गावांशी विचारविनिमय करून त्याआधारे कोणती कार्यवाही करण्यात येईल याची खातरजमा करील.

(३) ग्रामसभेला, पुढील बाबतीत शांतता समितीस अधिकार प्रदान करता येतीलः

(एक) गावच्या शांततेला बाधक ठरणा-या घटनांची चौकशी करणे आणि निर्णय घेण्यासाठी ग्रामसभेला माहिती देणे.

(दोन) शांतता भंग करणा-या घटकांना समुपदेशन करणे व लवाद म्हणून कामे करणे.

(तीन) आवश्यकता असेल तेथे तात्काळ कार्यवाही करणे व त्यानंतर ग्रामसभेला माहिती कळविणे.

(चार) ग्रामसभेच्या मान्यतेने योग्य कार्यवाही करण्यासाठी उप विभागीय दंडाधिकारी किंवा पोलीस अधिकारी यांना माहिती देणे किंवा विनंती करणे.

१९. पोलिसांची भूमिका :—पोलिसांना कोणत्याही गुन्ह्यांसंबंधात माहिती मिळाली असेल तर, पोलीस ठाण्यामध्ये अहवालाची नोंद केल्यानंतर त्याची एक प्रत सर्व प्रकरणांमध्ये ग्रामसभा किंवा शांतता समिती यांना पाठविण्यात येईल.

प्रकरण - पाच

नैसर्गिक साधनसंपत्ती शेती व जमीन यांचे व्यवस्थापन

२०. नैसर्गिक साधनसंपत्तीबाबत ग्रामसभेने संरक्षक उपाययोजना करणे :—(१) स्थानिक परंपरेनुसार आणि केंद्र व राज्य सरकारांच्या कायद्याच्या आशयानुसार पाणी, वन, जमीन व खनिज यांसह ग्रामसभेच्या क्षेत्रात स्थित नैसर्गिक साधनसंपत्ती तसेच जिच्यावर त्या ग्रामसभेचा परंपरागत अधिकार आहे अशी साधनसंपत्ती यांबाबत संरक्षक उपाययोजना करणे आणि त्यांचे जतन करणे याकरिता ग्रामसभा सक्षम आहे. हे कार्य पूर्णत्वास नेण्यासाठी, ग्रामसभेला त्यांच्या व्यवस्थापनामध्ये क्रियाशील भूमिका बजावता येईल.

(२) ग्रामसभा, पुढील गोष्टी घडून येतील अशा प्रकारे साधनसंपत्तीचा विनियोग होत असल्याबाबत खात्री करील **:—**

(एक) उपजिविकेची साधने शाश्वत आहेत ;

(दोन) लोकांमधील विषमता वाढत नाही ;

(तीन) साधन संपत्ती काही लोकांपुरतीच मर्यादित ठेवलेली नाही ;

(चार) शाश्वततेचा विचार करून स्थानिक साधनसंपत्तीचा पूर्ण विनियोग होत आहे.

(३) प्रचलित नियमांनुसार नैसर्गिक व इतर साधनसंपत्तीवरील व्यक्तिगत अधिकार यथोचितरीत्या प्रदान केले असले तरी त्यांचे व्यवस्थापन हे सामूहिक वारशांचा अंगभूत आशय विचारात घेऊन करण्यात येईल.

२१. साधनसंपत्ती नियोजन व व्यवस्थापन समिती :—(१) ग्रामसभेची एक स्थायी साधनसंपत्ती नियोजन व व्यवस्थापन समिती असेल.संबंधित विभागांचे सर्व प्रतिनिधी या साधनसंपत्ती नियोजन व व्यवस्थापन समितीचे सल्लागार म्हणून कार्य करतील आणि त्यांच्या सभांना उपस्थित राहतील.

(२) साधनसंपत्ती नियोजन व व्यवस्थापन समिती गावाच्या प्रदेशातील आणि सभोवतालच्या प्रदेशातील सर्व साधनसंपत्तीच्या कायम स्वरूपी उपयोग व ग्रामसभेच्या अधिकार क्षेत्रात एक योजना आखील आणि त्यानुसार तिचा वापर करण्यासाठी ग्रामसभेस सल्ला देईल व सहकार्य करील.

(३) साधनसंपत्ती नियोजन व व्यवस्थापन समिती ही, साधनसंपत्तीचे व्यवस्थापन व वापर याविषयीचे मतभेद अथवा विवाद यांसह तिच्या सर्व पैलूंचा विचार करील. ग्रामसभेला असे विवाद मिटवण्याकरिता साधनसंपत्ती नियोजन व व्यवस्थापन समितीस प्राधिकार देता येईल. जर साधनसंपत्ती नियोजन व व्यवस्थपन समिती विवाद मिटवण्यास समर्थ नसेल तर, त्या विवादांवर ग्रामसभेंच्या बैठकींमध्ये विचार करण्यात येईल. ग्रामसभेचा निर्णय अंतिम असेल.

(४) साधनसंपत्ती नियोजन व व्यवस्थपन समितीला शेती, गौण खनिज यांसारख्या विनिर्दिष्ट बाबींसंबंधात तिच्या कार्यांमध्ये सहाय्य करण्यासाठी उप-समित्या स्थापन करता येतील.

(२२) अनुसूचित क्षेत्रात ग्रामसभेने शेतीकरिता नियोजन करणे :—(१) शेतीद्वारे शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या वर्धनक्षम होतील अशाप्रकारे ग्रामसभा तिच्या गावामध्ये शेतीकरिता नियोजन करण्यास व त्याबाबत उपाययोजना करण्यास सक्षम आहे.

(२) ग्रामसभेच्या निर्णयांमध्ये इतर गोष्टींबरोबरच पुढील महत्त्वाचे मुद्दे अंतर्भुत असतील.

(क) जमिनीची धूप थांबविणे.

(ख) पिकांचे रक्षण करण्यासाठी चराईक्षेत्रामध्ये नियमितता आणणे आणि कुरणांची क्षमता वाढविणे.

(ग) पावसाचे पाणी साठवणे त्याचा शेतीसाठी वापर करणे व त्याच्या वितरणाची व्यवस्था करणे.

(घ) परस्पर सहकार्याने अथवा अन्य प्रकारे बिया, खते, इत्यादी तसेच ज्ञानाची देवाणघेवाण करणे याबाबत तरतूद केल्याची सुनिश्चिती करणे.

(ङ) सेंद्रीय खते, रासायनिक खते व कीटकनाशके यांचे प्रचालन करणे.

२३. अनुसूचित क्षेत्रातील भू-व्यवस्थापन :—(१) ग्रामसभा गावाच्या भू-अभिलेखामध्ये शेतक-यांची नावे अचूकपणे नोंदवलेली आहेत आणि अभिलेख योग्यरित्या ठेवण्यात आलेला आहे याची सुनिश्चित करण्याकरिता ग्रामसभेच्या बैठकीमध्ये संपूर्ण जमिनीच्या अभिलेखाचा आढावा घेईल.

(२) संस्थात्मक किंवा बिगर संस्थात्मक धनकोंचा जमिनीच्या गहाणासंबंधातील सर्व प्रकरणे माहितीसाठी ग्रामसभेसमोर ठेवण्यात येतील.

२४. अनुसूचित क्षेत्रातील जमिनीच्या अन्यसंक्रामणास प्रतिबंध :—(१) अनुसूचित जमातीतील व्यक्तींची कोणतीही जमीन अनुसूचित जमातेतर व्यक्तींकडे बेकायदेशीरपणे हस्तांतरित होणार नाही याची ग्रामसभा सुनिश्चिती करील.

(२) ग्रामसभा तिच्याकडे आलेल्या तक्रारींच्या आधारे किंवा स्वतः होऊन कोणत्याही जमीन व्यवहारांची चौकशी करण्यास किंवा तसे करण्यासाठी शांतता समितीला प्राधिकृत करण्यास सक्षम असेल.

(३) शांतता समिती तिचे निष्कर्ष ग्रामसभेपुढे ठेवील.

(४) अनुसूचित जमातीतील व्यक्तींच्या जमिनींचे बेकायदेशीरपणे अनुसूचित जमातेतर व्यक्तींकडे अन्यसंक्रामण करण्याचे प्रयत्न केले जात आहेत, असे ग्राम सभेचे मत असल्यास तिला अशा व्यवहारास मनाई करण्याच्या सूचना देता येतील.

(५) ग्रामसभेस गावाच्या भू-अभिलेखाबाबत पुढील कामे करता येतील :—

(क) जमिनीच्या व्याप्तीचा तपशील आणि उपभोक्त्यांसह खातेदारांची नावे समाविष्ट असलेली धारणजमिनींची यादी तयार करणे.

(ख) खातेदार हा खरोखरीच अनुसूचित जमातीचा आहे किंवा कसे हे पाहण्याकरिता सर्व खातेदारांच्या सामाजिक दर्जाच्या दाव्यांच्या खरेपणाची पडताळणी करणे.

(ग) जमीन एखाद्या आदिवासीच्या नावावर खरेदी केलेली आहे आणि बिगर आदिवासी व्यक्तीकडून तिचा उपभोग घेतला जात आहे किंवा कसे याबद्दल पडताळणी करणे.

(घ) इच्छा असल्यास शेतात प्रत्यक्ष जाऊन ती जमीन आदिवासीकडून अथवा ज्यांनी पट्टा गहाण इत्यादींवर घेतलेली असेल अशा आदिवासीतेतर व्यक्तींकडून करण्यात येत आहे किंवा कसे याबाबत प्रत्यक्ष पाहणी करणे.

(ङ) शासकीय जमिनीच्या अभिहस्तांकना करीता लाभाधिकारींची यादी तयार करणे.

(च) वरील (क) ते (ङ) मध्ये नमूद केलेल्या सर्व प्रकरणांमध्ये वेळोवेळी सुधारणा करण्यात आलेल्या महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ (१९६६ चा महा. ४१) किंवा त्याखाली केलेले नियम यांच्या तरतुदीतील संहितेचा भंग करून विवक्षित व्यवहार करण्यात आला असलेबाबत संपूर्ण तपासणीअंती ग्रामसभेची खात्री पटल्यास, ग्रामसभा ज्यांच्याबाबतीत भंग करण्यात आला असेल त्या बाबींचा तपशील नमूद केलेला ठराव संमत करील. हा ठराव प्राप्त झाल्यानंतर, सक्षम प्राधिकारी परिणामकारक कारवाई करील.

(६) जमिनीच्या ताब्यासंबंधात परस्पराविरोधी दावे असतील तर, ग्रामसभा एक बैठक बोलावील आणि योग्य तो ठराव संमत करण्यासाठी संबंधितांकडून अशा दाव्यांच्या पुष्ठ्यर्थ पुरावा मागवील. ग्रामसभा, बिगर आदिवासी व्यक्तींच्या नावे अन्यसंक्रामण झाल्याबाबतची कोणतीही तक्रार प्राप्त झाल्यावर एक बैठक बोलावील किंवा स्वतः होऊन योग्य तो निर्णय देईल आणि अनुसूचित जमातीच्या जमिनीच्या मालकाकडे जमिनीचा ताबा पूर्ववत करण्यासाठी आवश्यक ती कारवाई करण्याकरिता सक्षम अधिका-याकडे देण्याकरिता पाठवील.

(७) ग्रामसभेच्या निर्णयाने व्यथित झालेल्या कोणत्याही व्यक्तीस ठरावाच्या दिनांकापासून साठ दिवसांच्या कालावधीच्या आत सक्षम प्राधिका-याकडे विनंतीअर्ज दाखल करता येईल.

(८) सक्षम प्राधिका-यास एकतर तो विनंतीअर्ज दाखल करून घेता येईल किंवा फेटाळून लावता येईल किंवा ग्रामसभेकडे पुनर्विचारार्थ निर्दिष्ट करता येईल.

(९) असा निर्देश प्राप्त झाल्यावर, ग्रामसभा तीस दिवसांच्या कालावधींच्या आत बैठक बोलावील, विनंती अर्जावर सुनावणी करील, त्या निर्देशावर ठराव संमत करील आणि तो सक्षम प्राधिका-याकडे पाठवील.

(१०) संबंधित सक्षम प्राधिकारी ग्रामसभेच्या ठरावावर विचार करील आणि एकतर विनंतीअर्ज स्वीकारणारा किंवा फेटाळणारा समुचित आदेश देईल.

(११) सक्षम प्राधिकारी, आदिवासी व बिगर आदिवासीं यांच्या समावेश असलेल्या जमिनीच्या अन्यसंक्रामणाच्या प्रत्येक प्रकरणात, ग्रामसभेने विचारात घेतलेल्या मताबद्दल, संबंधित सचिवांच्या मार्फत संबंधित ग्रामसभेला न चुकता कार्यवाहीत सहभागी करून घेईल आणि ग्रामसभेच्या मताची यथोचितरीत्या तपासणी करण्यात येईल. यामुळे सक्षम प्राधिकारी, स्वतःहून किंवा वैयक्तिक तक्रारींवरुन आदिवासीकडून बिगर आदिवासींकडे जमिनीच्या होणा-या अन्यसंक्रामणास प्रतिबंध करण्याची किंवा ती जमीन आदिवासींना परत करण्याची कार्यवाही सुरू केली असेल तेव्हा देखील वरील बाबतीत दखल घेण्यात येईल.

(१२) सक्षम प्राधिकारी, प्रत्येक प्रकरणातील न्यायनिर्णयाच्या प्रती ग्रामसभेला देईल.

२५. अन्यसंक्रामण केलेली जमीन परत करणे :—(१) जर ग्रामसभेला आढळून आले की, अनुसूचित जमातीतील सदस्याव्यतिरिक्त कोणत्याही व्यक्तीकडे, अनुसूचित जमातीची मालकी असलेल्या कोणत्याही जमिनीचा, कोणत्याही कायदेशीर प्राधिकाराशिवाय ताबा असेल तर, ग्रामसभा मुळात ती जमीन ज्या व्यक्तीच्या मालकीची होती त्या व्यक्तीकडे आणि ती व्यक्ती मृत असेल तर तिच्या कायदेशीर वारसाकडे अशा जमिनीचा ताबा परत करण्याचा ठराव मंजूर करील. ग्रामसभेचा निर्णय सक्षम प्राधिका-याला कळविण्यात येईल तो ठरावाची पडताळणी करण्यासाठी संक्षिप्त चौकशी करील व जमीन परत करील.

(२) सक्षम प्राधिका-याच्या मते, ठराव कायदेशीर नसेल तर, तो त्याच्या मतांसह तो ठराव पुनर्विचारासाठी ग्रामसभेकडे लेखी पाठवील.

(३) ग्रामसभेने नमूद केलेल्या कारणांसह आपला निर्णय कायम ठेवला असेल व लेखी पुरावा दाखल केला असेल तर सक्षम अधिकारी सखोल चौकशी करील व त्यामध्ये कार्यवाहीत सहभागी झालेल्या पक्षकारांपैकी ग्रामसभा हा एक पक्षकार असेल आणि त्यानंतर तो अंतिम निर्णय देईल.

(२६) भूमी संपादनापूर्वी विचारविनिमय :—(१) शासन, त्यावेळी अंमलात असलेल्या कोणत्याही कायद्याच्या तरतुदींन्वये अनुसूचित क्षेत्रात भूमी संपादनाचा विचार करीत असेल तेव्हा, शासन किंवा संबंधित भूमी प्राधिकारी प्रस्तावासोबत पुढील लेखी माहिती ग्रामसभेकडे सादर करील :—

(एक) नैसर्गिक साधनसंपत्ती व त्याच्या लगत राहणारी जनता यांच्यावर प्रकल्पाच्या होणा-या संभाव्य परिणामांसह प्रस्तावित प्रकल्पाचा संपूर्ण आराखडा.

(दोन) प्रस्तावित भूमीसंपादनाचे तपशील.

(तीन) गावामध्ये स्थायिक होण्याची शक्यता असलेले नवीन लोक आणि ते क्षेत्र व समाज यांवरील संभाव्य परिणाम आणि गावातील लोकांचा प्रस्तावित सहभाग त्यांच्या नुकसानभरपाईची रक्कम, नोकरीच्या संधी.

(चार) पूर्नवसन आराखडा.

(२) संपूर्ण माहिती मिळाल्यानंतर, संबंधित ग्रामसभा या संबंधित प्राधिकरणांच्या किंवा शासनाच्या प्रतिनिधींना बोलाविण्यास सक्षम असतील. समन्स पाठविलेल्या अशा सर्व व्यक्तींनी मुद्यानिहाय स्पष्ट व अचूक माहिती सादर करणे अनिवार्य असेल.

(३) सर्व वस्तुस्थितीचा विचार केल्यानंतर, ग्रामसभा प्रस्तावित भूमी संपादनास आणि विस्थापित व्यक्तींच्या पुनर्वसन योजनेसंबंधात शिफारस करील.

(४) ग्रामसभेच्या शिफारशीवर जिल्हाधिका-याकडून विचार करण्यात येईल.

(५) जिल्हाधिकारी हा, ग्रामसभेच्या शिफारशींशी सहमत नसेल तर तो ती बाब पुनर्विचारार्थ ग्रामसभेकडे पुन्हा पाठवील.

(६) दुस-यांदा विचारविनिमय केल्यानंतर, जिल्हाधिका-याने ग्रामसभेच्या शिफारशींविरुद्ध आदेश दिला असेल तर तो तसे करण्याची कारणे लेखी नमूद करील आणि ती, माहितीसाठी ग्रामसभेकडे पाठवील.

(७) मोठ्या प्रकल्पांच्या बाबतीत अशा प्रकल्पांमुळे बाधित झालेल्या सर्व ग्रामसभांशी विचारविनिमय करण्यात येईल.

२७. अनुसूचित क्षेत्रामधील प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनवर्सन :— (१) संबंधित जमीन संपादन करणारी एजन्सी पुनर्वसनासंबंधातील सर्व तपशील ग्रामसभेसमोर ठेवील. सर्व समस्या व प्राधिका-यांनी दिलेली उत्तरे यांची ग्रामसभेच्या कार्यवृत्तांमध्ये नोंद घेण्यात येईल.

(२) ग्रामसभेने बहुमताने निर्णय घेतल्यास पायाभूत सोयीसुविधांसारखी कामे पंचायतीमार्फत करण्यात येतील. ज्यामध्ये तांत्रिक कौशल्याची आवश्यकता असेल अशी कामे संबंधित विभाग व समुचित स्तरावरील पंचायती कडून करण्यात येतील.

२८. जलस्त्रोतांचे नियोजन व व्यवस्थापन :—(१) जलस्त्रोतांच्या वापराचे व्यवस्थापन अशा रीतीने करण्यात येईल की, ते भावी पिढ्यांकरिता अक्षत राहील आणि त्या जलस्त्रोतांवर सर्व ग्रामस्थांचे समान अधिकार असतील

(२) पंचायतीतील गौण जलस्त्रोतांचे व्यवस्थापन पंचायतीकडून करण्यात येईल. एका पंचायतीपेक्षा अधिक पंचायतींमध्ये असलेल्या जलस्त्रोतांचे व्यवस्थापन पंचायत समितीकडून करण्यात येईल आणि एका पंचायत समितीपेक्षा अधिक पंचायत समित्यांमध्ये असलेल्या जलस्त्रोतांचे जिल्हा परिषदेकडून व्यवस्थापन करण्यात येईल.

(३) पंचायत किंवा पंचायत समिती किंवा यथास्थिति जिल्हा परिषद यांना संबंधित ग्रामसभेशी किंवा पंचायत समितीशी विचारविनिमय केल्यानंतर, ग्रामसभेच्या परंपरा व प्रचलित कायद्यांचा आशय लक्षात घेऊन संबंधित वेगवेगळ्या प्रयोजनांसाठी गावात उपलब्ध असलेल्या पाण्याच्या वापराचे विनियमन करता येईल, आणि तसेच पाणी वापराच्या प्राथम्यक्रमाविषयी निर्णय देखील घेता येईल.

(२९) सिंचनाचे व्यवस्थापन :—(१) पंचायत किंवा पंचायत समिती किंवा यथास्थिति जिल्हा परिषद संबंधित साधनसंपत्ती नियोजन व व्यवस्थापन समितीचा सल्ला घेतल्यानंतर सिंचनासाठी पाण्याचा वापराचे विनियमन करील.

(२) सर्वांना समप्रमाणात पाणी मिळेल अशा रीतीने सिंचनासाठी पाण्याचा वापर करण्यात येईल.

३०. गौण जलस्त्रोतांचे व्यवस्थापन :—(१) पंचायत किंवा पंचायत समिती किंवा यथास्थिति जिल्हा परिषद संबंधित साधनसंपत्ती नियोजन व व्यवस्थापन समित्यांशी आणि संबंधित विभागांशी विचारविनिमय करून, सिंचनाकरिता आणि इतर प्रयोजनाकरिता व्यवस्था करील.

(२) सर्व व्यक्तींना गावातील भूप्रदेशांतर्गत स्थित असलेल्या जलस्त्रोतामध्ये करारानुसार मासेमारी करण्याचा समन्यायी अधिकार असेल.

(३) स्थानिक परंपरा ध्यानात घेता, कोणतीही व्यक्ती अथवा व्यक्तींचा गट यांच्या आधिकारितेमध्ये अन्यायरितीने वाढ करत नाही, याची खात्री करण्याच्या दृष्टीने आणि माशांच्या अविरत उपलब्धतेची देखील खात्री करण्याच्या दृष्टीने, मासेमारीच्या कोणत्याही बाबतीत आवश्यक त्या शर्ती लादील.

३१. इतर सामूहिक मत्तांचे व्यवस्थापन :—(१) ज्या मत्तांचा वापर परंपरेने समाजाकडून सामूहिकरीत्या केला जात असेल अशा मत्तांचे व्यवस्थापन ग्रामसभेकडून करण्यात येईल.

(२) सामूहिक मत्तांची नोंदवहीमध्ये नोंद करण्यात येईल आणि त्या मत्तांची मालकी, वापर, प्रयोजन यांमध्ये फेरफार करण्यात आलेला नाही आणि त्यावर अतिक्रमण करण्यात आलेले नाही याबाबत दरवर्षी तपासणी करण्यात येईल.

(३) देणगी, श्रमदान सहाय्य यांद्वारे निर्माण झालेल्या कोणत्याही नवीन सामूहिक मत्तांची, नोंदवहीमध्ये तात्काळ नोंद करण्यात येईल.

(४) सामूहिक मत्तांचा वापर, ग्रामसभेमार्फत सामूहिक निर्णयानुसार करण्यात येईल.

प्रकरण सहा

खाण व खनिजे

३२. अनुसूचित क्षेत्रामध्ये गौण खनिजांकरिता योजना तयार करण्याचा ग्रामसभेचा अधिकार :—(१) ग्रामसभा ही, तिच्या क्षेत्रात आढळून येणारी माती, दगड, वाळू, इत्यादींसह सर्व गौण खनिजांचे उत्खनन व वापर यासाठी योजना तयार करण्याकरिता व त्यावर नियंत्रण ठेवण्याकरिता सक्षम असेल.

(२) ग्रामसभांना, पारंपारिक प्रथेनुसार त्यांच्या वैयक्तिक गरजांसाठी गौण खनिजांचा वापर करता येईल :

परंतु अशा खनिजांच्या वापरासाठी ग्रामसभेची परवानगी अनिवार्य असेल.

(३) शासनाचा संबंधित विभाग हा, ग्रामसभेशी विचारविनिमय करून, मगच खाणकाम पट्टा देईल किंवा गौण खनिजांचा लिलाव करील.

(४) ग्रामसभेला, गौण खनिजांचा पट्ट्यांमध्ये पर्यावरणाचे संरक्षण करणे, रोजगार, इत्यादींसाठी शर्ती सूचवता येतील.

(५) गौण खनिजाच्या उत्पादनाचा व्यापार होण्याची शक्यता असलेल्या संबंधित गावांमध्ये, गौण खनिजांचा व्यापारी दृष्टीने वापर करण्यास परवानगी देण्यापूर्वी, ग्रामसभेची पूर्वमंजूरी घेणे ही संबंधित खनिकर्म विभागाची जबाबदारी असेल. खनिकर्म विभागाचा संबंधित अधिकारी या बाबतीत ग्रामसभेला संपूर्ण माहिती पुरविल.

(६) संबंधित खनिकर्म विभाग हा, खाणपट्टा व लिलावासंबंधातील सर्व तपशील ग्रामसभेला देईल. ग्रामसभेला कोणतीही बेकायदेशीर कृती थांबविण्याचा अधिकार असेल. संबंधित खनिकर्म विभाग, ग्रामसभेने केलेल्या तक्रारींवर विचार करील आणि त्याने त्यावर केलेल्या कार्यवाहीबाबत ग्रामसभेला माहिती कळवील.

(७) ग्रामसभा ही, योग्य निर्णय घेऊन, तिची मान्यता किंवा नकार चार आठवड्यांच्या आत कळवील.

(८) ग्रामसभेचा निर्णय बंधनकारक व अंतिम असेल.

परंतु असे की, या नियमांतील तरतूदी फक्त बिगर वनक्षेत्रासाठी लागू राहतील.

३३. लिलावाद्वारे गौण खनिजांच्या समुपयोजनाकरिता परवानगी देणे :— गौण खनिजांच्या समुपयोजनाकरिता कोणत्याही शासकीय विभागाने कोणतीही परवानगी दिलेली असेल तर, उक्त शासकीय विभागाने ग्राम सभेची आवश्यक सहमती मिळवणे अनिवार्य आहे.

प्रकरण सात

मनुष्यबळ

३४. अनुसूचित क्षेत्रामध्ये ग्रामसभेने मनुष्यबळाकरिता नियोजन करणे :— (१) केंद्र व राज्यशासनाच्या विविध योजनांनुसार कार्ययोजना तयार करून व एकतर तिच्यामार्फत अथवा पंचायतीमार्फत त्याची अंमलबजावणी करून गावातील मनुष्यबळाचा पुरेपूर वापर होत असल्याबद्दल खात्री करण्याच्या दृष्टीने कामे हाती घेण्यास ग्रामसभा सक्षम आहे.

(२) ग्रामसभेस, लोकांमध्ये सहकार्याची भावना उत्पन्न होईल, त्यांच्यामध्ये ज्ञान, काम इत्यादींची परस्पर देवाणघेवाण होईल असे कोणतेही काम हाती घेता येईल.

३५. गावाबाहेरील कामगार घेणे :— (१) कामांसाठी गावाबाहेरील कामगार घेणा-या सर्व व्यक्तींनी, कामाचे स्वरुप व शर्ती विनिर्दिष्ट असलेल्या लेखी वा मौखिक कराराविषयी ग्रामसभेला संपूर्ण माहिती देणे आणि गावाबाहेरील कोणत्याही कामगारांना कामावर घेण्यापूर्वी तिची परवानगी मिळविणे त्यांना अनिवार्य आहे.

(२) वर नमूद केलेल्या कार्यपद्धतीनुसार ग्रामसभेने परवानगी दिल्यानंतरच लोकांना कामासाठी गावाच्या बाहेर घेऊन जाणे शक्य होईल.

(३) शासकीय व संघटीत क्षेत्रातील आस्थापनांहून अलग अशा खाजगी अथवा असंघटीत क्षेत्रातील व्यवस्थापकांना महिला व बाल कल्याणाविषयी घेण्यात येणा-या कार्यक्रमाची/योजनांची माहिती संबंधित ग्राम सभेला देणे बंधनकारक असेल.

प्रकरण आठ

मादकद्रव्य नियंत्रण

३६. मादकद्रव्य पदार्थांचे विनियमन :— ग्राम सभा, तिच्या अधिकारितेमध्ये, कोणत्याही प्रकारच्या मादकद्रव्याशी संबंधित सर्व घटकांवर पूर्ण नियंत्रण असण्यास सक्षम असेल. याचा अर्थ ग्राम सभेस,—

(क) आदिवासींना त्यांच्या स्वतःच्या वापराकरिता स्थानिक दारु बनवण्यास दिलेली सूट पूर्णतः थांबवता येईल किंवा गावामध्ये तिचे उत्पादन, विक्री, वितरण, सेवन वा साठा करण्यावर कोणत्याही प्रकारची बंदी आणता येईल.

(ख) एखाद्या दुकानातून किंवा अन्य कोणत्याही मार्गाने कोणत्याही प्रकारच्या मादक पदार्थाची विक्री थांबवण्याच्या सूचना देता येतील. परंतू या सूचना तात्काळ किंवा करार समाप्तीनंतर लगेचच अंमलात येतील.

(ग) कोणत्याही प्रकारचा मादक पदार्थ गावाच्या प्रदेशामध्ये आणण्यास अथवा प्रदेशातून बाहेर घेऊन जाण्यास बंदी घालता येईल.

(घ) कोणत्याही ठिकाणी मादक पदार्थाच्या साठ्यास प्रतिबंध करता येईल किंवा त्यावर मर्यादा घालता येईल.

(ङ) तिच्या गावाच्या प्रदेशामध्ये दारुच्या अथवा अन्य मादक पदार्थांच्या वापरावर संपूर्णपणे बंदी घालता येईल किंवा कोणताही निर्बंध लादता येईल.

(च) गावाच्या प्रदेशामध्ये किंवा बाजारात दारु बनवण्यामध्ये वापरली जाणारी मोहाची फुले (महुआ), काकवी (जॅगरी) इत्यादींच्या विक्रीस मनाई करता येईल.

(छ) ताडीचा, अथवा अन्य कोणत्याही स्थानिक मादक पदार्थाचा वापर यथोचित सुचना देऊन विनियमित करता येईल.

३७. मादकद्रव्य नियंत्रण समिती :—(१) ग्रामसभेस मादक पदार्थाशी संबंधित तक्रारींची चौकशी करण्यासाठी, नशा नियंत्रण समिती स्थापन करता येईल आणि लोकांच्या लाभाकरिता, मादक पदार्थावरील नियंत्रणासंबंधात एकतर करण्यात आलेल्या तक्रारींवरुन अथवा स्वतःहोऊन यथोचित सूचना देखिल करता येतील.

(२) मादकद्रव्य नियंत्रण समितीच्या किमान निम्मे सदस्य महिला असतील.

(३) मादकद्रव्य नियंत्रण समितीच्या जबाबदा-यांमध्ये पुढील बाबी समाविष्ट असतील :—

(क) कोणत्याही प्रकारच्या मादकद्रव्याची निर्मिती करणारे कारखाने हे, लायसनमध्ये नमूद केलेल्या सर्व शर्तींचे तंतोतंत पालन करीत असल्याची खात्री करणे आणि कोणतेही उल्लंघन झाल्यास, त्याबाबत सक्षम प्राधिका-यांना कळविणे.

(ख) मद्य निर्मिती, त्याची वितरण व्यवस्था, त्याचे पर्यावरणीय परिणाम, इत्यादींसह जनकल्याणाशी संबंधित सर्व बाबी ग्रामसभेपुढे सादर करण्यास संबंधित कारखान्याच्या मालकाला सांगणे.

(४) ग्राम सभेस, नशा नियंत्रण समितीचे कार्य सुरळीत पार पाडण्याकरिता संबंधित उत्पादनशुल्क विभागाचा सल्ला व त्याची मदत घेता येईल.

३८. मादक पदार्थ उत्पादकांना ग्रामसभेच्या सूचना :— ग्रामसभेस जनकल्याणाशी संबंधित बाबीसंदर्भात मादक पदार्थ बनविणा-या कोणत्याही कारखान्याच्या मालकाला योग्य त्या सूचना देता येतील आणि तिला आवश्यक वाटल्यास संबंधित उत्पादनशुल्क विभागास अथवा जिल्हाधिका-यास हस्तक्षेप करण्याची विनंती देखील करता येईल.

३९. अनुसूचित क्षेत्रांमध्ये नवीन कारखाना किंवा दुकान सुरू करणे :— (१) ग्रामसभेच्या सहमतीखेरीज, दारु अथवा अन्य मादक पदार्थाची निर्मिती करण्याचा कारखाना स्थापन करण्यात येणार नाही.

(२) ग्रामसभेच्या अधिकारितेमध्ये दारु अथवा मादक पदार्थांची निर्मिती करण्याचा कारखाना स्थापन करण्याबाबतचे किंवा दारुची विक्री करण्याकरिता नवीन दुकान सुरू करण्याबाबतचे शासकीय वा अन्य कोणत्याही अभिकरणाकडून आलेले सर्व प्रस्ताव ग्राम सभेपुढे सादर करणे आवश्यक असेल.

(३) गावातील रहिवासी असलेले आदिवासी किंवा आदिवासी लोकांचा गट हेच केवळ, अनुसूचित क्षेत्रांमध्ये नवीन दुकान किंवा नवीन कारखाना सुरू करण्याकरिता अर्ज करण्यास पात्र असतील.

(४) ग्राम सभेचा निर्णय अंतिम असेल.

(५) ग्राम सभेचा अशा मुद्यावर निर्णय झालेला नसेल किंवा त्या प्रस्तावावर विचार करण्यात आला नसेल तर, तो प्रस्ताव अस्वीकारार्ह असल्याचे मानण्यात येईल.

(६) दारुच्या कारखान्यामुळे गावाच्या हद्दीमध्ये प्रदुषण किंवा कारखाना बंद करण्यासाठी ग्रामसभेला ठराव करता येईल. ग्रामसभेचा ठराव संबंधित कारखान्यावर/शासकीय प्राधिकरणावर बंधनकारक राहील.

(७) गणपूर्तीच्या अभावी, वर नमूद केलेल्या प्रस्तावावर ग्राम सभेच्या बैठकीमध्ये विचार केला जाणार नाही.

४०. दारुची दुकाने चालू ठेवणे :— (१) कोणत्याही वर्षाकरिता दारुचे दुकान चालू ठेवण्यासाठी संबंधित उत्पादनशुल्क विभाग ग्राम सभेच्या बैठकीमध्ये एक प्रस्ताव सादर करावा लागेल.

(२) दारुचे दुकान चालू ठेवण्यास परवानगी देण्याकरिता ग्राम सभेमध्ये ठराव मंजूर झाला तरच दारुचे दुकान चालू ठेवता येईल. जर ग्राम सभेने दारुचे दुकान बंद करण्याबाबतचा ठराव मंजूर करण्याचे ठरविले असेल आणि दुकानदाराने स्वेच्छेने ते दुकान बंद केले नसेल तर, नशा नियंत्रण समिती स्वेच्छानिर्णयानुसार ते दुकान बंद करण्यासाठी यथोचित कारवाई करण्यास सक्षम असेल.

(३) ग्रामसभेमध्ये उपस्थित बहुसंख्य महिलांचे ते दुकान बंद करावे असे मत असेल तर, तो ग्राम सभेचा निर्णय असल्याचे समजण्यात येईल.

प्रकरण नऊ

गौण वनोत्पादन

४१. अनुसूचित क्षेत्रामध्ये गौण वनोत्पादन :— (१) अनुसूचित क्षेत्रातील सर्व गौण वनोत्पादनाचे व्यवस्थापन ग्रामसभेकडे विहित असेल.

(२) ग्रामसभा, साधनसंपत्ती नियोजन व संनियत्रण समिती अथवा शासन नियुक्त करील अशा समिती मार्फत गौण वनोत्पादनावरील मालकी हक्काचे संरक्षण करणे, ते गोळा करण्यासाठी प्रवेश मिळविणे त्याचा वापर व विनियोग पार पाडील.

(३) साधनसंपत्ती नियोजन व संनियंत्रण समिती, संपूर्ण ग्रासभेच्या लाभाकरिता अशा गौण वनोत्पादनाचा निरंतर वापर व समान व्यवस्थापन करण्याचा हेतूने, सर्व गौण वनोत्पादनासाठी एक व्यवस्थापन व वन संवर्धन योजना तयार करील.

(४) साधनसंपत्ती नियोजन व संनियंत्रण समिती मध्ये वन विभागाचा एक सदस्य असेल असा सदस्य हा, शासनाकडून ठरविण्यात येईल त्याप्रमाणे, संबंधित वन विभागाच्या योग्य स्तरामधील असेल :

परंतु, अशा सदस्यास, मतदानाचा हक्क असणार नाही तसेच त्याला साधनसंपत्ती नियोजन व संनियंत्रण समितीच्या सचिवाचे पद धारण करता येणार नाही.

(५) असा सदस्य, कार्यकारी योजना, गौण वनोत्पादनाचा निरंतर वापर, समुचित वनसंवर्धन विघापद्धती इत्यादीसारख्या तांत्रिक बाबींवर साधनसंपत्ती नियोजन व संनियंत्रण समिती आणि ग्रामसभेस सल्ला देईल.

(६) साधनसंपत्ती नियोजन व संनियंत्रण समिती, मार्गस्थ मालाच्या परवान्याचा प्रश्न, उत्पन्नाच्या विक्रीमधून येणा-या उत्पन्नाचा वापर किंवा व्यवस्थापन योजनेतील सुधारणा यासारख्या बाबीं ग्रामसभेपुढे तिच्या मान्यतेसाठी सादर करेल.

(७) वनोत्पादनाची कापणी, निविदा, विक्री इत्यादी बाबी पारदर्शक पद्धतीने पार पाडण्याचे कर्तव्य साधनसंपत्ती नियोजन व संनियंत्रण समिती अधिनियमातील तरतुदीविरुद्ध होणार नाही अशा पद्धतीने गौण वनोत्पादनाच्या व्यवस्थापनात पारदर्शकता व प्रभाविपणा असेल याची सुनिश्चिती होण्यासाठी, शासन ग्रामसभेस किंवा पंचायतीस वेळोवेळी सूचना देऊ शकेल किंवा निदेश देऊ शकेल.

(८) ग्रामसभा, जर तिची इच्छा असेल तर, गौण वनोत्पादनाचा कायमस्वरुपी वापर करण्याची संधी, पणन व वित्तीय व्यवस्थापन व लेखे ठेवणे यांसंबंधीचे तांत्रिक ज्ञान याबाबतचा आराखडा तयार करण्यासाठी आवश्यक त्या सर्व सहाय्याची तरतूद करण्याकरिता संबंधित वन विभागाची मदत मागू शकेल. वन विभागाचा हा सल्ला, ग्रामसभेसमोर तिच्या विचारार्थ सादर करण्यात येईल.

(९) ग्रामसभेस, गौण वनोत्पादन मर्यादित प्रमाणात असण्याच्या प्रकरणीसाधनसंपत्ती कमी असणा-या व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल गटाच्या काही मोजक्याच लोकांना ते वनोत्पादन गोळा करणे व त्याचा वापर करणे याकरिता आळीपाळीने व्यवस्था करता येईल.

(१०) ग्रामसभा, गौण वनोत्पादनाचे समुपयोजन करण्यासंबंधातील दंड आकारणे यांसह, नियमांचे काटेकोरपणे पालन करण्यासाठी आणि गौण वनोत्पादन गौळा करणारे लोक, ते गोळा करताना वनाचे नुकसान होईल अशी कोणतेही कृती करत नाही याची सुनिश्चिती करण्यासाठी, सक्षम असेल.

(११) राज्य शासन आणि समुचित स्तरावरील पंचायत, गौण वनोत्पादनाचे व्यवस्थापन सुरळीतपणे होईल यासाठी ग्रामसभेस प्रशिक्षण व कामे हाती घेणे, मूल्यात भर घालणे व बाजाराशी दुवा साधणे इत्यादी प्रयोजनांकरीता सहाय्य, मार्गदर्शन व मनुष्यबळ पुरविण्यासाठी योजना तयार करील.

४२. गौण वनोत्पादनासाठी योजना :— (१) गुरे चारणे, नांगर बनविणे अशांसारख्या गावांच्या गरजा भागविण्यासाठी ग्रामसभा, संबंधित वन अधिका-यांशी विचार विनिमय करून लोकांकडून पारंपारिकरीत्या वापरल्या जाणा-या वन साधनसंपत्तीचा वापर करण्याकरिता गौण वनोत्पादनांची योजना तयार करील. या योजनेअंतर्गत, प्रत्येक व्यक्ती ही, साधनसंपत्ती नियोजन व संनियंत्रण समितीकडून परवानगीपत्र मिळाल्यानंतर साधनसंपत्तीचा वापर करण्यास सक्षम असेल.

(२) ग्रामसभा, गरीब व्यक्तींचे हित व त्यांची उपजीविका यांचे संरक्षण याची संनिश्चिती करता यावी म्हणून यासंबंधात आवश्यक ते निदेश देईल.

(३) वनसंवर्धन, पर्यावरणाची सुधारणा व ग्रामसभेच्या संबंधित अनुसूचित क्षेत्रामध्ये स्थानिक स्तरावर रोजगारात वाढ करणे यांकरिता संबंधित विभागांशी विचारविनिमय करून समुचित कार्यक्रम तयार करता येतील.

(४) ग्रामसभा क्षेत्रांमधून लाकूड किंवा वनोत्पादने घेऊन जाण्यासंबंधात कोणतेही चौकशी करण्यासाठी सक्षम असेल.

(५) चौकशी करताना कोणत्याही बेकायदेशीर कामांबद्दल संशय वाटत असेल तर ग्रामसभा तातडीने ते काम जागच्या जागी थांबविण्यास सक्षम असेल आणि, उचित कार्यवाही करण्यासाठी संबंधित प्राधिकरणाला ते कळवील.

(६) पंचायत, विकास समिती किंवा स्थायी समिती ही, गौण वनोत्पादन गोळा करण्यापासून ते त्याच्या मुल्यात वाढ करणे व ग्रामसभेच्या मान्यतेने, त्याची बाजारात विक्री करणे यांसारखी गौण वनोउत्पादना संबंधातील कामे हाती घेऊ शकेल.

(७) वरील कामकाजातील वित्तीय व्यवहार, ग्रामसभा किंवा शासनाने अधिकार प्रदान केलेले प्राधिकरण, यांच्याकडून तपासणी करण्याकरिता खुले असतील.

प्रकरण दहा

बाजारांचे व्यवस्थापन

४३. अनुसूचित क्षेत्रांमधील बाजारांवर नियंत्रण :— ग्रामसभा ही पुढील बाबींसह, तिच्या क्षेत्रातील बाजारांना मान्यता देण्यास, त्यांच्यावर नियंत्रण ठेवण्यास व त्यांचे व्यवस्थापन करण्यास सक्षम असेल :

(क) बाजारातील दुकानदार व ग्राहक यांना पाणी, तात्पुरता निवारा व इतर भौतिक सुविधा उपलब्ध करून देणे,

(ख) बाजारात हानीकारक वस्तूंची आवक व विक्री यांना प्रतिबंध करणे.

(ग) व्यवहारांमध्ये वजन, माप व पैशाचे प्रदान चोखपणे केले जात आहे व त्यात कोणत्याहीप्रकारे शोषण केले जात नाही याची सुनिश्चिती करणे.

(घ) आकारण्यात येणा-या दरांविषयीची माहिती मिळविणे व तिची देवाणघेवाण करणे.

(ङ) दरांच्या बाबतीत फसवणूक किंवा चुकीची माहिती देणे इत्यादी सर्व अनुचित प्रथांना प्रतिबंध करणे ;

(च) बाजारात किंवा त्याच्या सभेवतालच्या क्षेत्रात जुगार, बेटिंग, सट्टे लावणे, कोंबड्यांच्या झुंजी यांसारख्या गोष्टींना प्रतिबंध करणे ;

(छ) लहान विक्रेत्यांव्यतिरिक्त बाजारातील दुकानदारांवर कर लादणे यासाठी पंचायतीस सल्ला देणे ;

(ज) वस्तुनिष्ठ तत्त्वांच्या आधारे, लहान विक्रेता म्हणून ती कोणती व्यक्ती पात्र असेल ते ठरवणे.

प्रकरण अकरा

सावकारी

४४. अनुसूचित क्षेत्रामधील सावकारी व्यवहारांवर नियंत्रण :— (१) ग्रामसभेस तिच्या सदस्यांमधून एक कर्ज नियंत्रण समिती घटित करता येईल.

(२) ही, समिती लायसनप्राप्त सावकारांसह बिगर शासकीय सावकारांकडून, होणा-या शोषणाच्या, व्याजखोरीच्या अवैध सावकारी किंवा अग्रिम या प्रसंगाची तपासणी करू शकेल.

(३) कोणतीही अवैधता आढळण्याच्या प्रसंगी, ऋण नियंत्रण समिती, तिचा अहवाल, शिफारशीसह कारवाईकरिता समुचित प्राधिकरणाकडे पाठवील.

प्रकरण बारा

लाभार्थी निश्चित करणे, आयोजनांना मान्यता, पर्यवेक्षण इत्यादींबाबतचे अधिकार

४५. ग्रामसभेने अनुसूचित क्षेत्रामधील लाभार्थी निश्चित करणे :— (१) ग्रामसभा, शासनाच्या योजना, सूचना व निदेश यांची एकरूपता लक्षात घेऊन विकास कार्यक्रमांकरिता, कुटुंबांच्या सामाजिक व आर्थिक स्थितीच्या आधारे गावातील लोकांमधून लाभार्थी निश्चित करण्यासाठी मार्गदर्शक तत्वे व निकषांना अंतिम रूप देण्यास सक्षम असेल.

(२) संबंधित विभाग ग्राम सभेला सर्व माहिती देईल. ग्रामसभा विचारविमर्श केल्यानंतर, लाभार्थींची यादी निश्चित करील.

४६. ग्रामसभेची कार्यक्रमांना मान्यता :— (१) पंचायतीने गावासाठीच्या योजना व प्रकल्पांकरिता सर्व ग्रामसभांची मान्यता मिळवणे तिच्यावर बंधनकारक असेल.

(२) गावामध्ये कोणताही कार्यक्रम किंवा प्रकल्प सुरू करण्यापूर्वी पंचायत, तो ग्रामसभेपुढे तिच्या मान्यतेसाठी सादर करील.

४७. उपरोक्त नियम ४५ व ४६ यांबाबत विभागांनी व पंचायतीने ग्रामसभेच्या निर्णयाचे अनुपालन करणे :— आपले अधिकार वापरताना ग्रामसभेने कोणत्याही संबंधित विभागाच्या अथवा आधिका-याच्या कार्यालयीन कामामध्ये अडथळा येईल किंवा अडथळा येण्याची शक्यता असेल असा निर्णय घेतला असेल तर त्याबाबतीत पुढीलप्रमाणे कार्यवाही केली जाईल :—

(क) संबंधित विभागाच्या प्रतिनिधी किंवा अधिकारी विवादग्रस्त बाबीवरील कारवाई पुढे ढकलील आणि ग्रामसभेला तिने आपल्या निर्णयावर पुनर्विचार करावा अशा विनंतीसह आपले मत सादर करील.

(ख) संबंधित विभागास ग्रामसभेचा निर्णय समाधानकारक वाटला नाही तर, ते प्रकरण निर्णयाच्या दिनांकापासून पंधरा दिवसाच्या आत मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांचेकडे निर्देशित केले जाईल त्यावर अधिनियम, १९९६ च्या तरतुदींच्या आधारे ते निर्णय देतील.

४८. खर्चाचे प्रमाणन :— ग्रामसभेने हाती घेतलेल्या कामांकरिता, ग्रामसभेकडून प्रपत्र " अ " मधील सर्व निधीच्या वापराचे प्रमाणन मिळविणे पंचायतीवर बंधनकारक असेल.

४९. कामांसबंधी ग्रामसभेला द्यावयाचा तपशील :— (१) त्या क्षेत्रामध्ये काम हाती घेतलेल्या सर्व संबंधित विभागांकडून चालू असलेल्या प्रत्येक कामांसंबंधिचा संपूर्ण तपशील ग्रामसभेच्या बैठकीत मांडण्यात येईल.

(२) कामाचा दर्जा आणि करण्यात आलेला खर्च यांच्याशी संबंधित कोणताही आक्षेप असल्यास ते प्रकरण ग्रामसभेपुढे ठेवण्यात येईल. ग्रामसभा त्या प्रकरणांचा तपास करील आणि त्यात सुधारणा करण्यासाठी योग्य त्या सूचना देईल.

(३) कोणताही कार्यक्रम पूर्ण झाल्यावर, त्याचा सविस्तर तपशील, ग्रामसभेच्या पुढच्या बैठकीत सादर करण्यात येईल.

५०. सामाजिक क्षेत्राचे परीक्षण :— (क) (१) ग्रामसभा, शाळा, रुग्णालये यांसारख्या स्थानिक संस्थांचे तसेच सर्व सामाजिक क्षेत्रीय योजनांचे वेळोवेळी परीक्षण करण्यास सक्षम असेल.

(२) ग्रामसभेस तिच्या परीक्षण कार्यामध्ये सहाय्य करण्यासाठी विशेष समित्या घटित करता येतील.

(३) स्थानिक संस्थांच्या सामाजिक क्षेत्रिय योजनांच्या कार्यान्वयनामध्ये सुधारणा घडवून आणण्याच्या दृष्टीने, ग्रामसभेने दिलेल्या सूचना विभागाच्या संबंधित पदाधिका-यांकडून योग्यरितीने विचार करण्यात येईल.

५१. सामाजिक लेखाजोखा आणि विकास कार्यक्रमांचे संनियंत्रण :— ग्रामसभा दक्षता व संनियंत्रण समिती स्थापन करील ही समिती पुढील गोष्टींची देखील सुनिश्चिती करील.—

(क) कामाच्या ठिकाणी आणि कोणत्याही सार्वजनिक ठिकाणीही कामासंबंधीची माहिती स्थानिक भाषेत दर्शविण्यात आलेली आहे.

(ख) कामाची प्रगती व दर्जा राखण्यात आला आहे.

(ग) कामगारांना नावाचे वाचन करून सार्वजनिक जागेत पगार दिला जातो.

५२. अनुसूचित क्षेत्रामध्ये समाजाचा, सामाजिक, धार्मिक व परंपरागत व्यवस्थापन प्रथा यांच्याशी सुसंगत असा राज्याचा कायदा असणे :—(१) राज्याच्या विद्यमान कायद्याच्या कोणत्याही तरतुदी अनुसूचित क्षेत्रात विस्तारित होत असताना त्या त्यांच्या रुढी, सामाजिक व धार्मिक प्रथा आणि समाजाच्या साधनसंपत्तीच्या पारंपरिक व्यवस्थापन प्रथा किंवा अशी कोणतीही विषयवस्तू, जी अनुसूचित क्षेत्राच्या अधिकारकक्षेत येते ती, यांच्याशी सुसंगत नाही, असे ग्रामसभेचे मत असेल तर, ती तशा आशयाचा ठराव संमत करील.

(२) अशा प्रकारे संमत केलेला ठराव ग्रामसभा जिल्हापरिषदेचा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, यांच्या कडे पाठवील, जो पाचव्या अनुसूचीच्या आवश्यकतेला अनुसरुन राज्यपालांना पाठवावयाच्या एका प्रतीसह, तो ठराव शासनाकडे पाठवील.

(३) शासन अशा ठरावावर आवश्यक ती कार्यवाही करील आणि त्या बाबत ग्रामसभेला सूचित करील.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

डॉ. नरेश गिते,
शासनाचे उप सचिव.

प्रपत्र "अ"

उपयोजन प्रमाणपत्र

उपयोजनाचे प्रमाणपत्र, अनुदान-निहाय व कोषागार–निहाय स्वतंत्रपणे पाठविण्यात यावे.

(मंजुरी देणा-या प्राधिका-याचे नाव) यांनी दिनांक ________________ रोजी मंजुरी आदेश क्रमांक. _________ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे___________________________________ या प्रयोजनासाठी वापरण्यात आलेल्या _______________ कोषागारामधून ____________________ सहाय्यक अनुदानासाठी _________________ एम. एच. अन्वये दिनांक ______________________ व्ही. आर. क्रमांक ______________ नुसार रुपये ________________ इतक्या रकमेसाठी प्रमाणपत्र देण्यात येत आहे.

संगणक क्रमांक _______________

नियंत्रण अधिका-याची सही

(रबरी शिक्क्यासह)

RURAL DEVELOPMENT AND WATER CONSERVATION DEPARTMENT

Bandhkam Bhavan, P.W.D. Building, 25, Marzban Road,
Fort, Mumbai 400 001. dated 4th March, 2014.

NOTIFICATION

MAHARASHTRA VILLAGE PANCHAYAT ACT.

No. PRI-2010/CR-130/PR-2— Whereas, the Parliament has by enacting the provisions of the *Panchayats* (Extension to the Scheduled Areas) Act, 1996 (Act No. 40 of 1996) extended the provisions of the Part IX of the Constitution of India, as inserted by the Constitution (Seventy-third Amendment) Act ;

And whereas, in consonance with the said Central Act, the Maharashtra State Legislature has amended the Maharashtra Village Panchayats Act (III of 1959) by enacting the Bombay Village Panchayats and the Maharashtra Zilla Parishads and Panchayat Samities (Amendment) Act, 2003 (Mah. XXVII of 2003) and other amending Act, enacted from time to time has inserted therein Chapter III-A providing the special provisions for *Gram Sabha* and *Panchayat* in the Scheduled Areas;

And whereas, the Maharashtra Village Panchayats Act, after its said amendments empowers the *Gram Sabhas* and *Panchayats* in the Scheduled Areas to safeguard and preserve the traditions and customs of the people, their cultural identity, community resources and customary modes of dispute resolution and ownership of minor forest produce, etc ;

And whereas, the implementation of the Bombay Village Panchayats and the Maharashtra Zilla Parishads and Panchayat Samities (Amendment) Act, 2003, which promotes self-governance, giving a central role to the *Gram Sabhas*, is vital to safeguard the interests of the people living in the Scheduled Areas; and for that purpose to make rules to ensure the effective implementations thereof .

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (xlvii) of sub-section (*2*) of section 176 read with sections 54A, 54B, 54C, 54D of Chapter III-A, clause (fa) of sub-section (*2*) of section 57, sub-section (*2*) of section 58 and section 153B of the Maharashtra Village Panchayats Act (III of 1959) and of all other powers enabling it in this behalf, the Government of Maharashtra hereby makes the following rules, the same having been previously published as required by sub-section (*4*) of section 176 of the said Act, namely :–

CHAPTER I
PRELIMINARY

1. Short title and extent :— (*1*) These rules may be called the Maharashtra Village Panchayats Extension to Scheduled Areas (PESA) Rules, 2014.

(*2*) They shall extend to all the Scheduled Areas in the State where the Act is in force.

2. Definitions :— (*1*) In these rules, unless the context otherwise requires,—

(*a*) "Act" means the Maharashtra Village Panchayats Act 1958 (III of 1959) ;

(*b*) "Form" means form appended to the rules ;

(*c*) "Government" means the Government of Maharashtra ;

(*d*) " *Gram Sabha* " means a village assembly in the Scheduled Area, comprising all persons whose names are included in the electoral rolls for the *Panchayat* at the village level ;

(*e*) " Secretary " means a secretary of Panchyat appointed or deemed to be appointed under section-60 of the Maharashtra Village Panchyat Act.

(*f*) "State" means the State of Maharashtra.

(*2*) Words and expressions used but not defined in these rules shall have the meanings respectively assigned to them in The Maharashtra Land Improvement Schemes Act (XXVIII of 1942); The Bombay Money-lenders Act 1947 (Bombay XXXI of 1947) ; The Maharashtra Prohibition Act (XXV of 1949); The Maharashtra Police Act (XXII of 1951); the Maharashtra Village Panchayats Act (III of 1959); The Maharashtra Fisheries Act, 1961 (Mah.I of 1961); The Maharashtra Industrial

Development Act, 1961 (Mah. III of 1962); The Maharashtra Zilla Parishads and Panchayat Samitis Act, 1961 (Mah. V of 1962); the Maharashtra Land Revenue Code, 1966 (Mah. XLI of 1966); The Maharashtra Forest Produce (Regulation of Trade) Act, 1969 (Mah. LVII of 1969); The Maharashtra Housing and Area Development Act, 1976 (Mah. XXVIII of 1977); The Maharashtra Irrigation Act, 1976 (Mah. XXXVIII of 1976); The Maharashtra Forest Development (Tax on Sale of Forest-produce by Government or Forest Development Corporation) (Continuance) Act, 1983 (Mah. XXII of 1983). The Maharashtra Transfer of Ownership of Minor Forest Produce in the Scheduled Areas, and the Maharashtra Minor Forest Produce (Regulation of Trade) (Amendment) Act. 1997 (Mah. XLV of 1997); The Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006. (No. 2 of 2007) Biological Diversity Act, 2002 (No. 18 of 2003).

CHAPTER II

COMPOSITION AND FUNCTION OF GRAM SABHA

3. Composition of Gram Sabha in the Scheduled Area :— All the people included in the electoral rolls for the Panchayats at village level shall be the members of the *Gram Sabha* of that village.

4. Declaration of village in the Scheduled Area :— (*1*) If the people of any habitation or a group of habitation or hamlet or a group of hamlet are of the opinion that their habitation or hamlet, or group of habitation or hamlet would be recorded as a village, they may pass a resolution by a majority of at least half the registered voters in the voting list of that habitation or hamlet or group of habitation or hamlet, as the case may be, to this effect and forward it to the concerned Sub-Divisional Officer, under the intimation of the Collector.

(*2*) The Sub-Divisional Officer shall enquire into the merits of the resolution within three months. For this purpose he shall call a meeting of all the registered voters of that habitation or hamlet, or group of habitation or hamlet after giving wide publicity, and conduct an enquiry considering all relevant factors. He shall then submit a report to the Collector with his findings, stating explicitly whether the proposed village conforms to the provisions of the Act :

Provided that, if the Sub-Divisional Officer does not decide on the question within three months from the day of receipt of such resolution, then the Collector shall *sue-motto* take the cognizance of such resolution and may pass an appropriate order in this regard within 45 days.

(*3*) An appeal against the decision of the Sub-Divisional Officer rejecting such resolution shall lie with the Collector whose decision shall be final.

(*4*) The Collector, if satisfied that a new village is to be so notified, shall sent his recommendation to the Divisional Commissioner, for notification of the new village as per Chapter III-A of the Act :

Provided that the decision on a reference from the Sub-Divisional Officer shall be taken by the District Collector within forty-five days from the receipt of such a reference failing which approval shall be deemed to be given.

5. Panchayat to be Executive Committee of Gram Sabha :— (*1*) The Panchayat shall be deemed to be the Executive Committee of the *Gram Sabha.*

(2) The *Panchayat* shall function under the general superintendence, control and direction of the *Gram Sabha.*

6. Secretary, office, etc. of Gram Sabha in the Scheduled Area :— (*1*) In a situation where there are more than one *Gram Sabhas* in a *Panchayat,* the Secretary of the *Panchayat* shall be the Secretary of all the *Gram Sabhas*. In his absence the procedure will be followed as per section 54 C of Chapter-III of Maharashtra Village Panchyat Act.

(*2*) The office of the Panchayat shall be the office of the *Gram Sabha.* If there is more than one *Gram Sabha* in a *Panchayat*, each *Gram Sabha* shall have its own office in its village, such as public building, Samaj Mandir, School or any place where public have easy access, and in the case that no such place is available the house of an ordinary person:

Provided that no rent shall be paid in any form for such office.

7. Gram Sabha meetings to be in public in the Scheduled Area :— (*1*) Every meeting or proceeding of the *Gram Sabha* shall be conducted in public.

(*2*) Even if a meeting of the *Gram Sabha* is to be held in a closed building, there shall not be any provision of closing the doors or prohibiting entry.

8. Method of taking decisions :— (*1*) As far as possible, the working of the *Gram Sabha* shall be done with consensus.

(*2*) In case of non-consensus on any issue in a meeting, that matter shall be discussed in the next meeting to be held, as decided by the *Gram Sabha* as per provision.

(*3*) If there is no consensus in the second meeting also, a decision shall be taken on the basis of a majority, in that meeting.

9. Proceedings of meeting of Gram Sabha :— (*1*) After election and in every financial year, the First *Gram Sabha* shall be held under the Chairpersonship of the *Sarpanch.* In his absence, *Upa-Sarpanch,* and in absence of both *Sarpanch* and *Upa-Sarpanch*, a Panchayat member of the Scheduled Tribe shall be elected as a Chairperson by the *Gram Sabha.* No *Sarpanch* or *Upa-Sarpanch* or a member of *Panchayat* shall be eligible to act as Chairperson of the *Gram Sabha*, except on the occasion mentioned above:

Provided that in villages where the population of Scheduled Tribes is less than ten per cent., a Chairperson may be selected from among persons who do not belong to the Scheduled Tribes.

(*2*) For the meetings of the *Gram Sabha,* other than the meetings mentioned in sub-rule (1) of this rule, the selection of the Chairperson shall be made with consensus to the extent possible. In case there is no consensus, it shall be by majority vote. The Chairperson shall be the person, who belongs to the Scheduled Tribes only.

(*3*) The quorum of the meeting of the *Gram Sabha* shall be twenty-five per cent. of the total members or one hundred, whichever is lower.

(*4*) In the absence of quorum, the meeting shall be adjourned. The quorum shall be necessary even in the meeting convened after adjournment.

(*5*) A detailed statement of the complete record of income and expenditure of the last month, muster roll of workers, sale and purchase shall be produced in the meeting of the *Gram Sabha* by the Secretary.

(*6*) While concluding the meeting, a brief statement of the decisions taken in the *Gram Sabha* shall be prepared by the Secretary. That statement shall be read out in the meeting. After a consensus upon the correctness of the statement, the Chairperson, Secretary and writer shall sign.

10. Standing Committees of Gram Sabha in the Scheduled Area :— (*1*) The *Gram Sabha* may constitute Standing Committees such as the Peace Committee, Justice Committee, Resource Planning and Management Committee, Intoxication Control Committee, Debt Control Committee, Market Committee, Sabha Kosh Committee and other Committees as deemed appropriate by the *Gram Sabha* in order to fulfil its responsibilities regarding various aspects of the working of the village. Besides, temporary and *ad-hoc* Committees may be constituted as per requirement. These committees shall be answerable to both *Panchayat* and *Gram Sabha.*

(*2*) The members of the Standing Committees shall be selected in the *Gram Sabha* meeting amongst the members present. The selection of such member shall be depends upon the nature of work and requirement of the *Gram Sabha*. The *Gram Sabha* shall decide total numbers of members and representation to women and other section in the society. The tenure of such Standing Committee shall be two years :

Provided that, not less than half of the members of any Standing Committee shall be women.

(*3*) The Chairperson of the Standing Committee shall be nominated by the *Gram Sabha* from amongst the members of the Standing Committee concerned.

(*4*) The Secretary of the Standing Committee shall be selected by the *Gram Sabha*. The *Gram Sabha* may, in consultation with the concerned Administrative Departments also nominate any officials to work for the Standing Committee within the jurisdiction of village, as a non-voting member and he shall assist the Standing Committee in its functioning.

(*5*) The responsibility to implement the decisions taken by the *Gram Sabha* on various subjects shall be the concerned Standing Committee.

11. Procedure of Standing Committees of Gram Sabha:— The procedure of the Standing Committees of the *Gram Sabha* shall be as follows, namely:—

(*1*) Meetings of all Standing Committees including *Panchayat* shall be in open.

(*2*) Notice of every meeting of the Standing Committee, specifying the date, time and place thereof and business to be transacted shall be given by the Secretary of the Standing Committee at least three days in advance.

(*3*) The quorum for meeting of the Standing Committee shall be one-half, including the Chairperson.

(*4*) A member of the *Gram Sabha* may attend any meeting of the Standing Committee. He may ask any question on the topic during discussion with the permission of the Chairperson:

Provided that such member shall not have right to vote.

(*5*) All the decisions of the Standing Committees shall be taken as per the procedure of the *Gram Sabha*.

(*6*) The gist of the important decisions taken in the meetings of the Standing Committees shall be recorded in the proceeding book and minutes of such meeting shall be signed by the Chairperson and Secretary.

(*7*) All decisions of the Standing Committees and other records shall be placed before the next immediate *Gram Sabha* of the village.

12. Objection against by Gram Sabha:— (*1*) All the records of the *Panchayat* and *Gram Sabha* shall be open to all villagers. It shall be made available for inspection, scrutiny to the authority designated by the *Panchayat Samitis*, *Zilla Parishads* and Government.

(*2*) Any objection made about any decision taken by the *Gram Sabha*, may be raised by the objector in general meeting of the *Gram Sabha* for reconsideration.

(*3*) If the objector or any other person is of the opinion that an observer is necessary to assist the *Gram Sabha* for resolving the objection, he may make a request to the Block Development Officer to depute an observer to attend the *Gram Sabha* meeting.

(*4*) If the Block Development Officer is satisfied about the need for an observer, he may depute not below the rank of Extension Officer an observer for the meeting of the *Gram Sabha* under intimation to the objector.

(*5*) The observer so appointed shall facilitate the redressal of the grievance of the objector.

(*6*) If the issue is not resolved, the objector or observer may refer the issue to the Chief Executive Officer of the *Zilla Parishad* who shall enquire into the issue and issue necessary instructions.

13. Joint meetings of Gram Sabhas in the Scheduled Area.— (*1*) Every *Gram Sabha* shall be competent to execute its functions in its jurisdiction:

Provided that, in matters in which working with other *Gram Sabhas* is required, a joint meeting of all *Gram Sabhas* falling under the jurisdiction of the Panchayat shall be conducted.

(*2*) The joint meeting of the *Gram Sabhas* shall be conducted as per the provisions applicable to the *Gram Sabha* as if the *Gram Sabhas* concerned is a single entity.

(*3*) The joint meeting shall be chaired by the person elected by consensus as far as possible.

(*4*) In the joint meeting, attendance of a minimum of twenty-five per cent., members from each *Gram Sabha* or one hundred members from each *Gram Sabha*, whichever is lower, shall be mandatory. In case there is no quorum, the date of next meeting shall be finalized on the same day and the same shall be sent to all *Gram Sabhas*.

(*5*) The decision making process shall be the same as in the case of a single *Gram Sabha*.

CHAPTER III

GRAM SABHA ACCOUNTS

14. Gram Sabha Kosh in the Scheduled Area:— (*1*) The *Gram Sabha* shall maintain a *Gram Sabha Kosh*.

(*2*) Kosh shall consist of the contribution received in any form including voluntary contributions of cash and goods, and the amount received from minor forest produce, minor minerals, etc., and surcharges imposed on the consumption of the resources and fines levied by the *Gram Sabha*. It may also include transfers under any devolution scheme, as may be decides by the Government.

(*3*) The Kosh shall be under the control of Gram Sabha. The *Gram Sabha* shall have the complete rights of its usage as per resolutions of the *Gram Sabha*.

(*4*) The Kosh shall be operated by a *Gram Sabha Kosh* Committee comprising of the Secretary of Panchayat and another two members nominated with consensus or elected by the *Gram Sabha*. At least one member out of these two members shall be a woman. All accounts shall be audited and presented before the *Gram Sabha* for information and final approval.

15. Accounts to be maintained:— (*1*) The accounts of the *Gram Sabha Kosh* shall be maintained in a register by a member of the *Gram Sabha Kosh* Committee.

(*2*) The receipts and expenditure statement of the *Gram Sabha Kosh* shall be produced in the next meeting of *Gram Sabha*.

16. Gram Sabhawise accounts:— Every Gram Sabha shall keep a separate account of receipt and expenditures which shall be certified by the concerned *Gram Sabha*. Account of *Gram Sabha Kosh* and *Panchayat* shall be subject to audit by the *Panchayat Samiti*, *Zilla Parishad* and Local Fund Authority :

Provided that the Rural Development and Water Conservation Department shall endeavor to provide accounting instructions, training, and provision for electronic maintenance of records of the *Gram Sabha Kosh* within one year of the rules being published to ensure transparency and accountability.

CHAPTER IV

PEACE, SECURITY AND DISPUTE RESOLUTION

17. Role of Gram Sabha in maintaining peace, security and dispute resolution in the Scheduled Area.— (*1*) In keeping with community traditions and the spirit of the relevant laws and rules made thereunder, it shall be the fundamental duty of the *Gram Sabha* to maintain peace, security and order in its area.

(*2*) The *Gram Sabha* is competent for the following action and works in its region to,–

(*i*) maintain a peaceful atmosphere;

(*ii*) Safeguard the self-respect and maintain the freedom of expression of every citizen;

(*iii*) Counter the vices of anti-social elements including indecent behavior with women, fighting or quarrelling in public place, etc.

(*iv*) Resolve disputes.

18. Peace Committee :— (*1*) The *Gram Sabha* may constitute a Peace Committee. The Peace Committee shall have at least thirty three per cent. women, and a minimum fifty per cent. Scheduled Tribes.

(*2*) The Peace Committee shall maintain a healthy relationship with the neighbouring villages, and to ensure that in matters of common interest and inter dependence of neighbouring villages, any action taken shall be based on consultation with the neighbouring villages.

(*3*) The *Gram Sabha* may empower the Peace Committee to,–

(*i*) inquire into incidents that vitiate peace of the village and report to *Gram Sabha* for a decision;

(*ii*) Counsel those breaking peace and arbitrate;

(*iii*) Take immediate action where necessary, and subsequently report to the *Gram Sabha*;

(*iv*) With the approval of the *Gram Sabha* make a report or request to the Sub-Divisional Magistrate or police officer for suitable action.

19. Role of Police.— If the police receives information regarding any crime, after the report is registered in the police station, a copy of the same shall be sent for information to the *Gram Sabha* and the Peace Committee in all cases.

CHAPTER V

MANAGEMENT OF NATURAL RESOURCES, AGRICULTURE AND LAND

20. Gram Sabha to safeguard natural resources in the Scheduled Area.— (*1*) The *Gram Sabha* is competent to safeguard and preserve the natural resources located in its area as well as those over which it enjoys traditional rights including water, forest, land and minerals as per local tradition and the spirit of the laws of the Central and State Governments. To fulfil this role, the *Gram Sabha* may play active role in their management.

(*2*) The *Gram Sabha* shall ensure that resources are utilized in such a way that,–

(*i*) Livelhold means are sustained;

(*ii*) inequality amongst the peoples does not increase;

(*iii*) resources are not confined to a few people;

(*iv*) there is full utilization of local resources, in keeping with sustainability.

(*3*) Though as per the prevalent rules, individual rights over natural and other resources shall be suitably honoured, their management shall be done keeping in view the inherent spirit of the community legacy.

21. Resource Planning and Management Committee.— (*1*) There shall be a standing Resource Planning and Management Committee of the *Gram Sabha*. Representatives of all the concerned Departments shall function as advisors to the Resource Planning and Management Committee and attend its meetings.

(*2*) The Resource Planning and Management Committee shall chalk out a plan for the sustainable use of resources vested with the *Gram Sabha* within the territory of the village and those in the surrounding and shall advise and co-operate with the *Gram Sabha* members to make use of them accordingly.

(*3*) The Resource Planning and Management Committee shall consider all the aspects, including difference of opinion or dispute about the management and use of the resources. The *Gram Sabha* may authorize the Resource Planning and Management Committee to resolve such disputes. If the Resource Planning and Management Committee is not able to resolve the same, it shall be considered in the meetings of the *Gram Sabha*. The decision of the *Gram Sabha* shall be final.

(*4*) The Resource Planning and Management Committee may constitute sub-committees on specific issues such as farming, minor minerals, etc., to assist it in its functions.

22. Gram Sabha to plan for farming.— (*1*) The *Gram Sabha* shall be competent to plan and take action about the farming of its village in such a way to make farming economically viable for the farmer.

(*2*) The decisions of the *Gram Sabha*, *inter-alia*, may include the following major points,–

(*a*) To prevent soil erosion;

(*b*) To regulate grazing in order to protect crops and enhance the capacity of meadows;

(*c*) To accumulate rain water, use it for farming and provide for its distribution;

(*d*) With mutual co-operation or otherwise, to ensure provision of seeds, manure, etc. as well as knowledge sharing;

(*e*) To promote on organic manures, fertilizers and insecticides.

23. Land Management in the Scheduled Area.— (*1*) The *Gram Sabha* shall review the records of the entire land of the village in the meetings of the *Gram Sabha* to ensure that the farmer's names are correctly recorded and records are properly maintained.

(*2*) All matters regarding mortgage of land to institutional and non-institutional creditors shall be put up before the *Gram Sabha* for information.

24. *Prevention of land alienation in the Scheduled Area:*— (*1*) The *Gram Sabha* shall ensure that no land belonging to Scheduled Tribes is unlawfully transferred to non-Scheduled Tribe persons.

(*2*) The *Gram Sabha* shall be competent to enquire into any land transactions, or authorize the Peace Committee to do so, on the basis of complaints or *suo-motto*.

(*3*) The Peace Committee shall place its findings before the *Gram Sabha*.

(*4*) If the *Gram Sabha* is of the opinion that attempts are being made to alienate lands belonging to Scheduled Tribes unlawfully, it may issue instructions to prohibit the transaction.

(*5*) The *Gram Sabha* may undertake the following activities with respect to the land record of the village,-

(*a*) prepare a list of land holding containing the details of extent of land held and names of the *khatedars* along with enjoyers;

(*b*) verify the veracity of social status claims of all the *khatedars* as to whether the *khatedar* is a genuine Scheduled Tribe;

(*c*) verify as to whether the land is purchased in the name of a tribal and enjoyed by a non-tribal;

(*d*) visit the field if desired and physically verify as to whether the land are cultivated by the tribal or by the non-tribal taken on lease, mortgage, etc.;

(*e*) approve the list of beneficiaries for assignment of Government land;

(*f*) in all cases mentioned at (*a*) to (*e*) above, if *Gram Sabha* after thorough investigation is satisfied that certain occupation of land is in violation of the provisions of the Maharashtra Land Revenue Code, 1966 (Mah. XLI of 1966) or rules made there under, as amended from time to time, the *Gram Sabha* shall pass resolution mentioning the details of violation. After receipt of this resolution, the competent authority shall initiate consequential action.

(*6*) If there are conflicting claim in respect of the possession of lands, the *Gram Sabha* shall convene a meeting and call for evidence in support of such claims from the concerned to pass appropriate resolution. The *Gram Sabha* shall also convene a meeting on receipt of any complaint on alienation of land in favour of non-tribal or *suo-motto* pass appropriate resolution and shall forward the same to the competent authority to take necessary action to restore the land to the Scheduled Tribe owner.

(*7*) Any person aggrieved by the resolution of *Gram Sabha* may within a period of sixty days from the date of resolution, file a petition to the competent authority.

(*8*) The competent authority may either allow or reject or refer the petition to the *Gram Sabha* for consideration.

(*9*) After receipt of such reference, the *Gram Sabha* shall meet within a period of thirty days, hear the petition, pass resolution on that reference and forward the same to the competent authority.

(*10*) The concerned competent authority shall consider resolution of the *Gram Sabha* and pass appropriate order, either accepting or rejecting the petition.

(*11*) The competent authority shall invariably implead the *Gram Sabha* through the Secretary concerned for their considered opinion in every case of land alienation involved tribal and non-tribal and the opinion of the *Gram Sabha* shall be duly examined. This shall also be the case when the proceedings initiated by the competent authority takes cognizance *suo-motto* or on individual complaints, to prevent land alienation from tribal to non-tribal or restore land to a tribal.

(*12*) The competent authority shall furnish the copies of the relevant Judgment to the *Gram Sabha* in every case.

25. *Restoration of alienated land.*— (*1*) If the *Gram Sabha* finds that any person other than a member of the Scheduled Tribe, is in possession of any land belonging to a Scheduled Tribe, without any lawful authority, the *Gram Sabha* shall pass a resolution to restore the possession of such land to that person to whom it originally belonged and if that person is dead, to his legal heirs. The decision of the *Gram Sabha* shall be conveyed to the competent authority who shall make a brief enquiry to verify the resolution and restore the land.

(*2*) In case the competent authority is of the considered opinion that the resolution is not lawful, he shall in writing refer the resolution to the *Gram Sabha* for reconsideration with his observations.

(*3*) In case the *Gram Sabha* maintains its decision with reasons recorded and evidence adduced in writing, the competent authority shall hold detailed enquiry in which one of the impleaded parties shall be the Gram Sabha, and give a final decision.

26. Consultation before land acquisition.— (*1*) When the Government considers to acquire land in the Scheduled Area under the provisions of any Act, is in the force, the Government or the concerned land acquiring authority shall submit to the *Gram Sabha*, the following written information along with the proposal, namely:–

(*i*) The complete outline of the proposed project including the possible impact of the project on natural resources and people residing near it;

(*ii*) Details of the proposed land acquisition;

(*iii*) New people likely to settle in the village and possible impact on the area and society, and the proposed participation, amount of compensation, job opportunities for the people of the village, etc.;

(*iv*) Rehabilitation plan.

(*2*) After getting complete information, the concerned *Gram Sabhas* shall be competent to call the representatives of the concerned authorities and the Government to discuss with them either individually or collectively. It shall be mandatory for all such persons summoned to furnish point-wise clear and correct information.

(*3*) The *Gram Sabha* after considering all the facts, shall make a recommendation regarding the proposed land acquisition and rehabilitation plan of persons displaced.

(*4*) The recommendation of the *Gram Sabha* shall be considered by the Collector.

(*5*) In case the Collector is not in agreement with the recommendations of the *Gram Sabha*, he shall sent the case again to the Gram Sabha for reconsideration.

(*6*) If after a second consultation, the Collector passes an order against the recommendations of the *Gram Sabha*, he shall record the reasons for doing so in writing and it shall sent to *Gram Sabha* for information.

(*7*) In case of big projects, all the *Gram Sabhas*, which are affected by such projects shall be consulted.

27. Rehabilitation of project affected persons in the Scheduled Area.— (*1*) The concerned land acquiring agency shall put all the details of rehabilitation before the *Gram Sabha*. All queries and replies given by authority shall be recorded in the minutes of the *Gram Sabha*.

(*2*) If the *Gram Sabha* decides by a majority that the works like providing amenities shall be done through *Panchayat*. Works which requires technical skill may be done by the concerned Department or the *Panchayat* at the appropriate level.

28. Planning and management of water resources:— (*1*) Management of use of water resources shall be made in such way that these are kept intact for future generations, and all the villagers have equal rights over these resources.

(*2*) Minor water bodies within a *Panchayat* shall be managed by the *Panchayat*, those extending to more than one *Panchayat* by the *Panchayat* Samiti, and those extending to more than one *Panchayat Samiti* by the *Zilla Parishad*.

(*3*) The *Panchayat* or *Panchayat Samiti* or *Zilla Parishad*, as the case may be, after consulting with the concerned *Gram Sabhas* or *Panchayat Samitis*, keeping in view of their traditions and the spirit of prevalent laws, shall regulate the use of available water in the village for various purposes and also decide about the priority of use.

29. Management of irrigation:— (*1*) The *Panchayat* or *Panchayat Samiti* or *Zilla Parishad*, as the case may be, shall regulate the use of water for irrigation after taking the advice of the concerned Resource Planning and Management Committees.

(*2*) The use of water for irrigation shall be such that equitable access is allowed to all.

30. Management of minor water bodies.— (*1*) The *Panchayat* or *Panchayat Samiti* or *Zilla Parishad,* as the case may be, shall make arrangements for the irrigation and other purposes, in consultation with concerned Resource Planning and Management Committees and concerned Departments.

(*2*) All persons shall have equitable rights to fishing as per convention in the water resources located within the territory of the village.

(*3*) Keeping in view the local traditions the *Panchayat* shall impose necessary conditions regarding any aspect of fishing to ensure that any individuals or a group of persons do not increase their jurisdiction in an unjust manner and also to ensure the sustained availability of the fish.

31. Management of other community assets.— (*1*) The management of the assets which are used commonly by the community traditionally shall be done by the *Gram Sabha*.

(*2*) Community assets shall be recorded in the register and verified it annually so that their ownership, use, purpose is not changed and they are not encroached upon.

(*3*) Any new community assets created through donation, shramadan, aid shall be recorded immediately in the register.

(*4*) Use of community assets shall be done as per decision of the community through *Gram Sabha*.

CHAPTER VI

MINES AND MINERALS

32. Power of Gram Sabha to plan for minor minerals in the Scheduled Area:— (*1*) The *Gram Sabha* is competent to plan and control the excavation and use of all the minor minerals including soil, stones, sands, etc., which is to be found in its area.

(*2*) The villagers may use minor minerals for their individual needs as per the traditional practice:

Provided that, the permission of the *Gram Sabha* shall be mandatory for use of such minerals.

(*3*) The concerned Government Department shall award mining lease or make auction of minor minerals only after consultation with the Gram Sabha.

(*4*) The *Gram Sabha* may suggest conditions for protecting the environment, employment, etc., in the leases of minor minerals.

(*5*) In villages having commercial feasibility of minor mineral production, before permitting the minor minerals to be used commercially, it shall be the responsibility of the concerned Mineral Department to obtain the prior sanction of the *Gram Sabha*. The concerned officer of the Mineral Department shall provide complete information to the *Gram Sabha* in this regard.

(*6*) The concerned Mining Department shall give all details of lease and auction to the *Gram Sabha*. The *Gram Sabha* shall have right to stop any illegal activity. The concerned Mining Department shall look into complaints made by the *Gram Sabha* and shall inform to the *Gram Sabha* about the action taken by it.

(*7*) The *Gram Sabha* shall forward its approval or rejection by passing an appropriate solution within four weeks.

(*8*) The decision of the *Gram Sabha* shall be final and binding :

Provided that the provisions of this rule shall be applicable to non-forest area only.

33. Grant of permission for exploitation of minor minerals by auction.— If any permission is given by any Government Department for the exploitation of minor minerals, it shall be mandatory for the said Government Department to obtain the necessary concurrence from the *Gram Sabha*.

CHAPTER VII

MANPOWER

34. *Gram Sabha to plan for labour force in the Scheduled Area :—* (*1*) The *Gram Sabha* is competent to undertake activities in order to ensure that there is full utilization of the village labour force by preparing a work plan under various schemes of the Central and State Government and executing them either by itself or through the *Panchayat*.

(*2*) The *Gram Sabha* may take any action which encourages co-operation among the peoples, sharing each other's knowledge, work, etc.

35. *Workers taken outside the village :—* (*1*) It shall be mandatory for all persons taking workers outside the village for jobs to provide complete information to the *Gram Sabha* about the written or oral agreement specifying nature and conditions of work, and obtain its permission before taking any workers outside the village.

(*2*) Only after getting the permission of the *Gram Sabha* as per the procedure mentioned above, it shall be possible to engage the people out for work.

(*3*) Apart from the establishments of the Government or organized sector, it shall be mandatory for mangers of private or unorganized sector to keep the *Gram Sabha* concerned informed, from time to time, about the well-being of the womenfolk.

CHAPTER VIII

INTOXICATION CONTROL

36. *Regulation of intoxicants in the Scheduled Area :—* The *Gram Sabha* shall be competent to have full control over all the aspects related to any type of intoxicant in its jurisdiction, that is to say, the *Gram Sabha* may,—

(*a*) completely stop the relaxation of allowing tribal to manufacture local liquor for their own use or impose any type of ban on its production, sale, distribution, consumption or storage in the village;

(*b*) give instructions to stop the sale of any type of intoxicant from a shop or in any other manner:

Provided that these instructions shall come into force immediately or after expiration of contract;

(*c*) impose a ban on any type of intoxicant for bringing or taking it outside the village territory;

(*d*) prohibit or impose a limit on the storage of intoxicants at any place;

(*e*) completely stop the use of liquor or other intoxicants in its village territory and impose any restriction;

(*f*) prohibit the sale of *Mahua,* Jaggrey, etc., which are used in making of liquor within the territory of the village or in the market;

(*g*) regulate the use of *Taadi*, or any local intoxicant by issuing suitable instructions.

37. *Intoxication Control Committee:—* (*1*) The *Gram Sabha* may constitute an Intoxication Control Committee to inquire into complaints related to intoxicants, and also either on the basis of complains or suo-motto, make suitable suggestions regarding the control of intoxicants for the benefit of the people.

(*2*) At least half of the members of the Intoxication Control Committee shall be women.

(*3*) The responsibilities of the Intoxication Control Committee shall include,-

(*a*) to ensure that the factories manufacturing any type of intoxicants adhere to all the conditions mentioned in the license and in case of any infringements, report to the competent authorities;

(*b*) to ask the owner of the concerned factory to present all matters related to the welfare of the people including manufacture of liquor, its distribution system, environmental impact, etc. before the *Gram Sabha*.

(4) The *Gram Sabha* may take advice and help from the concerned Excise Department for the smooth functioning of the Intoxication Control Committee.

38. Instructions by Gram Sabha to manufactures of intoxicants:— The *Gram Sabha* may give appropriate instructions to the owner of any factory manufacturing intoxicants on matters related to the welfare of people, and also make a request to the concerned Excise Department or Collector to intervene if it considers necessary.

39. Opening a new factory or shop in the Scheduled Area:— (*1*) Without concurrence of the *Gram Sabh*a, no new factory for manufacturing liquor or other intoxicants shall be established.

(*2*) All proposals to construct a factory to manufacture liquor or other intoxicants or to open a new shop for the sale of liquor in the jurisdiction of the *Gram Sabha*, either by the Government or any other agency, shall be required to be presented before the *Gram Sabha*.

(*3*) Only tribal or group of tribals, who are inhabitants of the village shall be eligible to apply for opening new shop or new factory in the Scheduled Areas.

(*4*) The decision of the *Gram Sabha* shall be final.

(*5*) In case the *Gram Sabha* remains undecided on the issue or if the proposal is not considered, then that proposal shall be deemed to be unacceptable.

(*6*) The *Gram Sabha* may pass the resolution to close down the liquor factory for pollution in the village area and the decision of the *Gram Sabha* will be mandatory on concerned factory and Government Authority.

(*7*) In the absence of a complete quorum, the above-mentioned proposal shall not be considered in the meeting of the *Gram Sabha*.

40. Continuance of liquor shops :— (*1*) In order to continue a liquor shop for any year, a proposal shall have to be presented by the concerned Excise Department in the meetings of the *Gram Sabha*.

(*2*) A liquor shop may continue only if a resolution is passed in the *Gram Sabha* to allow continuing the sale of liquor. If *Gram Sabha* decide to close the liquor shop by passing resolution to that effect and the shop is not closed by the shopkeeper voluntarily, then the Intoxication Control Committee by its own discretion shall be competent to take appropriate action for closing the shop.

(*3*) If the majority women present in the *Gram Sabha* are of the opinion to close the shop then it shall be considered as opinion of the *Gram Sabha*.

CHAPTER IX

MINOR FOREST PRODUCE

41. Management of minor forest produce in the Scheduled Area :— (*1*) The management of all minor forest produce in the Scheduled Area shall vest to the *Gram Sabha*.

(*2*) The *Gram Sabha* shall choose to carry out the right of ownership, access to collection, use, and disposal of minor forest produce through the Resource Planning and Monitoring Committee or any other committee formed by the Government for this purpose

(*3*) The Resource Planning and Monitoring Committee shall prepare a management and conservation plan for all minor forest produce in order to sustainably and equitably manage such minor forest produce for the benefit of the entire *Gram Sabha*.

(*4*) For the purposes of the exercise of the Right to Minor Forest Produce by the *Gram Sabha*, the Resource Planning and Monitoring Committee shall have a forest official of the appropriate level as decided by the Government as an *ex-officio* member. Provided that such a member shall not have right to vote, as well as he shall not hold the post of Secretary of the Resource Planning and Monitoring Committee.

(*5*) Such member shall advise to the Resource Planning and Monitoring Committee, and the *Gram Sabha* about technical matters, such as the working plan, sustainable use of minor forest produce, appropriate silvicultural practices, etc.

(*6*) The transit permits for access to minor forest produce shall be issued by the Resource Planning and Monitoring Committee in its meeting.

The Resource Planning and Monitoring Committee shall put all decisions pertaining to the issue of transit permits, use of income from sale or produce or modification of management plans before the *Gram Sabha* for its approval.

(*7*) It shall be the duty of the Resource Planning and Monitoring Committee to carry out the harvesting, tender, sale of produce, etc. in a transparent fashion. The Government may give instructions or issue directions to the *Gram Sabha* or *Panchayat*, from time to time, so as to ensure that the transparency and effectiveness, in the management of minor forest produce, in a manner which is not contrary to the provisions of the Act.

(*8*) The *Gram Sabha* may, if it so desires ask for the assistance of the concerned Forest Department to provide all possible help in chalking out plans for sustainable access to the minor forest produce, marketing and technical knowledge for financial management and account keeping. This advice of the Forest Department shall be put before *Gram Sabha* for its consideration.

(*9*) The *Gram Sabha* may, in case of limited quantity of a minor forest produce, make a cyclic arrangement for its collection and use by a few people such as resource less and economically weaker groups.

(*10*) The *Gram Sabha* is competent for strict compliance of rules in the exploitation of minor forest produce, including levying of penalties, and to ensure that collectors of minor forest produce do not commit any act which damages the forest.

(*11*) The State Government and the Panchayats at the appropriate level shall form schemes to give assistance, guidance and manpower for the purposes of training and handholding, value addition, and market linkages to the *Gram Sabha*, so that the minor forest produce manage smoothly.

42. Scheme for minor forest produce:— (*1*) For meeting of village requirements, such as grazing, making houses and ploughs, the *Gram Sabha* shall chalk out a minor forest scheme for the use of forest resources used traditionally by the people in consultation with the concerned Forest Officers. Under this scheme every person shall be able to use the resources after getting permission letter from the Resource Planning and Monitoring Committee.

(*2*) The *Gram Sabha* may issue necessary directions in this regard, so as to ensure that the interest of the poor persons for their picking up of livelihood are protected.

(*3*) The *Gram Sabha* may chalk out suitable programs in consultation with concerned Departments to conserve the forest, improve the environment and enhance the employment at local level in their respective Scheduled Areas.

(*4*) The *Gram Sabha* is competent to make any inquiry about the wood or forest produce, which passing through their areas.

(*5*) If, on enquiry, there is a doubt of any illegal operation, then the *Gram Sabha* is competent to stop it on the spot immediately, and inform the same to the concerned authority for taking appropriate action.

(*6*) *The Panchayat*, Development Committee or Standing Committee can take minor forest produce related activities ranging from collection to value addition and marketing with the approval of the *Gram Sabha*.

(*7*) Financial transactions in above activities shall be open to examination by the *Gram Sabha* or any authority empowered by the Government.

CHAPTER X

MANAGEMENT OF MARKETS

43. Control over markets in the Scheduled Area:— The *Gram Sabha* is competent to approve, control and manage the markets within its territory, including to,-

(*a*) make available water, sheds and other physical facilities with shopkeepers and consumers in the market;

(*b*) prohibit the inflow and sale of harmful objects in the market;

(*c*) ensure that the weight, measurement and payment in the transactions are genuine and no exploitation is done in any form;

(*d*) obtain and share information about the prices being charged;

(*e*) prohibit all unfair practices, including cheating and misinformation regarding prices, etc.;

(*f*) prohibit gambling, betting, testing luck, cock-fighting, etc. in the market and its surrounding area;

(*g*) advise *Panchayat* to impose tax on shopkeepers of the market except small vendors;

(*h*) decide who qualifies as a small vendor based on objective principles.

CHAPTER XI

MONEY LENDING

44. *Control over money lending transaction in the Scheduled Area.*— (*1*) The *Gram Sabha* may constitute a Debt Control Committee from amongst its members.

(*2*) This Committee may investigate instances of exploitative, usurious, illegal lending or advances by non-Governmental lenders, including licensed money-lenders.

(*3*) In case of any illegality, the Debt Control Committee shall sent its report, with recommendation to the appropriate authority for action.

CHAPTER XII

IDENTIFICATION OF BENEFICIARIES, APPROVAL OF PLANS, SUPERVISION, ETC.

45. *Gram Sabha to identify beneficiaries in the Scheduled Area:*— (*1*) The *Gram Sabha* shall be competent to finalise guidelines and criteria for identification of beneficiaries on the basis of the socio-economic condition of the family for social and economic development programs from amongst the people of the village, in keeping uniformity with the Government scheme, instructions or directions.

(*2*) The concerned Department shall give all information to the *Gram Sabha*. After deliberation, the *Gram Sabha* shall finalise the list of beneficiaries.

46. *Approval of programs by Gram Sabha:*— (*1*) It shall be mandatory for the *Panchayat* to obtain the approval of all the *Gram Sabhas* on plans and projects for the village.

(*2*) Before beginning any program or project in the village the *Panchayat* shall present it before the *Gram Sabha* for its approval.

47. *Compliance of decision of Gram Sabha by Departments and Panchayats in case of rule 45 and 46 above:*— While using its rights, if the Gram Sabha takes a decision which causes hindrance or there is possibility of hindrance in the official work of any concerned Department or officer, then action shall be taken as follows, namely :—

(*a*) the representative of the concerned Department or officer shall postpone the action on the disputed matter and present his views to the *Gram Sabha*, with a request to reconsider its decision;

(*b*) if the concerned Department is not satisfied with the decision of the *Gram Sabha*, the matter shall, within fifteen days from the date of decision be referred to the Chief Executive Officer of the Zilla Parishad, who shall decide it in the light of provisions of the Act.

48. *Certification of expenses:*— It shall be mandatory for the *Panchayat* to obtain a certification of utilization of all funds in Form A, from the *Gram Sabha* for works undertaken by it.

49. *Details regarding works to be given to Gram Sabha:*— (*1*) The complete details of every work progress in the village shall be laid by all the concerned Departments, who working in that area, in the meetings of the *Gram Sabha*.

(*2*) If there is any objection pertaining to the quality of the work and the expenditure incurred, then the matter shall be placed before the *Gram Sabha*. The *Gram Sabha* shall examine the issue and give suggestions for its improvement.

(*3*) On completion of any programme, the complete details thereof shall be produced before the next meeting of the *Gram Sabha*.

50. *Review of social sector:*— (*1*) The *Gram Sabha* shall competent to review all social sector schemes as well as local institutions such as schools, hospitals, etc., from time to time.

(*2*) The *Gram Sabha* may constitute special Committees to assist in its reviews.

(*3*) The instructions given by the *Gram Sabha* for improving the implementation of social sector schemes of local institutions shall be considered appropriately by the concerned functionaries of the Departments.

51. Social audit and monitoring of development activities:— The *Gram Sabha* may constitute Vigilance and Monitoring Committee. This Committee shall ensure that,—

(*a*) information about work has been displayed at the work site and also at any public place in local language;

(*b*) progress and quality of work is maintained;

(*c*) payment to the worker are read out and given in public places.

52. State law to be in keeping with custom, social, religious and traditional management practices of community in the Scheduled Area:— (*1*) If a *Gram Sabha* is of the opinion that any provisions of the existing state law extended to the Scheduled Area are not in consonance with their custom, social and religious practices and traditional management practices of the community resources or any subject matter which is comes within the purview of the Scheduled Area, it may pass a resolution to that effect.

(*2*) Such resolution so passed shall be forwarded to the Chief Executive Officer of the Zilla Parishad by the *Gram Sabha*, who shall forward it to the Government with a copy to the Governor, in consonance with the requirement of the Fifth Schedule of the Constitution of India.

(*3*) The Government shall take necessary action on such Resolution and communicate it to the *Gram Sabha*.

By order and in the name of the Governor of Maharashtra,

DR. NARESH GITE,
Deputy Secretary to Government.

FORM—"A"

(*See* Rule 48)

UTILISATION CERTIFICATE

Utilisation Certificates should be forwarded Grant-wise and Treasury-wise separately.

Certificate that an amount of Rs. ________________ vides Vr No.___________________ dated __________under M.H._________ towards Grant-in-Aid from _________ Treasury was utilized for the purpose of ____as mentioned in the sanction order No.______________ dated ____________ of the_____________ (name of the sanctioning authority).

Computer No.______________

Signature of Controlling Officer
(with rubber stamp)

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004, EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI.

THE PROVISIONS OF THE PANCHAYATS (EXTENSION TO THE SCHEDULED AREAS) ACT, 1996No.40 OF 1996

(24th December, 1996)

An Act to provide for the extension of the provisions of Part IX of the Constitution relating to the Panchayats to the Scheduled Areas.

Be it enacted by Parliament in the Forty-seventh Year of the Republic of India as follows:-

Short title

1. This Act may be called the Provisions of the Panchayats (Extension to the Scheduled Areas) Act, 1996

Definition

2. In this Act, unless the context otherwise requires, "Scheduled Areas" means the Scheduled Areas as referred to in Clause (1) of Article 244 of the Constitution.

Extension of part IX of The Constitution

3. The provision of Part IX of the Constitution relating to Panchayats are hereby extended to the Scheduled Areas subject to such exceptions and modifications as are provided in section 4.

Exceptions and modifications to part IX of The Constitution

4. Notwithstanding anything contained under Part IX of the Constitution, the Legislature of a State shall not make any law under that Part which is inconsistent with any of the following features, namely:-

(a) a State legislation on the Panchayats that may be made shall be in consonance with the customary law, social and religious practices and traditional management practices of community resources;

(b) a village shall ordinarily consist of a habitation or a group of habitations or a hamlet or a group of hamlets comprising a community and managing its affairs in accordance with traditions and customs;

(c) every village shall have a Gram Sabha consisting of persons whose names are included in the electoral rolls for the Panchayat at the village level;

(d) every Gram Sabha shall be competent to safeguard and preserve the traditions and customs of the people, their cultural identity, community resources and the customary mode of dispute resolution;

(e) every Gram Sabha shall-

i. approve of the plans, programmes and projects for social and economic development before such plans, programmes and projects are taken up for implementation by the Panchayat at the village level;

ii. be responsible for the identification or selection of persons as beneficiaries under the poverty alleviation and other programmes;

(f) every Panchayat at the village level shall be required to obtain from the Gram Sabha a certification of utilisation of funds by that

Panchayat for the plans, programmes and projects referred to in clause(e);

(g) the reservation of seats in the Scheduled Areas at every Panchayat shall be in proportion to the population of the communities in that Panchayat for whom reservation is sought to be given under Part IX of the Constitution;

Provided that the reservation for the Scheduled Tribes shall not be less than one-half of the total number of seats;

Provided further that all seats of Chairpersons of Panchayats at all levels shall be reserved for the Scheduled Tribes;

(h) the State Government may nominate persons belonging to such Scheduled Tribes as have no representation in the Panchayat at the intermediate level or the Panchayat at the district level:

Provided that such nomination shall not exceed one-tenth of the total members to be elected in that Panchayat;

(i) the Gram Sabha or the Panchayats at the appropriate level shall be consulted before making the acquisition of land in the Scheduled Areas for development projects and before re-setling or rehabilitating persons affected by such projects in the Scheduled Areas; the actual planning and implementation of the projects in the Scheduled Areas shall be coordinated at the State level;

(j) planning and management of minor water bodies in the Scheduled Areas shall be entrusted to Panchayats at the appropriate level;

(k) the recommendations of the Gram Sabha or the Panchayats at the appropriate level shall be made mandatory prior to grant of prospecting licence or mining lease for minor minerals in the Scheduled Areas;

(l) the prior recommendation of the Gram Sabha or the Panchayats at the appropriate level shall be made mandatory for grant of concession for the exploitation of minor minerals by auction;

(m) while endowing Panchayats in the Scheduled Areas with such powers and authority as may be necessary to enable them to function as institutions of self-government, a State Legislature shall ensure that the Panchayats at the appropriate level and the Gram Sabha are endowed specifically with-

(i) the power to enforce prohibition or to regulate or restrict the sale and consumption of any intoxicant;

(ii) the ownership of minor forest produce;

(iii) the power to prevent alienation of land in the Scheduled Areas and to take appropriate action to restore any unlawfully alienated land of a Scheduled Tribe;

(iv) the power to manage village markets by whatever name called;

(v) the power to exercise control over money lending to the Scheduled Tribes;

(vi) thepower to exercise control over institutions and

functionaries in all social sectors;

(vii) the power to control over local plans and resources for such plans including tribal sub-plans;

(n) the State Legislations that may endow Panchayats with powers and authority as may be necessary to enable them to function as institutions of self-government shall contain safeguards to ensure that Panchayats at the higher level do not assume the powers and authority of any Panchayat at the lower level or of the Gram Sabha;

(o) the State Legislature shall endeavour to follow the pattern of the Sixth Schedule to the Constitution while designing the administrative arrangements in the Panchayats at district levels in the Scheduled Areas.

Continuance of existing laws on panchayats:

5. Notwithstanding anything in Part IX of the Constitution with exceptions and modifications made by this Act, any provision of any law relating to Panchayats in force in the Scheduled Areas, immediately before the date on which this Act receives the assent of the President, which is inconsistent with the provisions of Part IX with such exceptions and modifications shall continue to be in force until amended or repealed by a competgent Legislature or other competent authority or until the expiration of one year from the date on which this Act receives the assent of the President;

Provided that all the Panchayats existing immediately before such date shall continue till the expiration of their duration unless sooner dissolved by a resolution passed to that effect by the Legislative Assembly of that State or, in the case of a State having Legislative Council, by each House of the Legislature of that State.

K.L. MOHANPURIA,

Secy. To the Govt. of India

RNI No. MAHENG /2009/35528
Reg. No. MH/MR/South-344/2014-16

सत्यमेव जयते

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

असाधारण भाग आठ

वर्ष ६, अंक २२(४)] बुधवार, जून २५, २०१४/आषाढ ४, शके १९३६ [पृष्ठे ३, किंमत : रुपये २७.००

असाधारण क्रमांक ७०

प्राधिकृत प्रकाशन

महाराष्ट्र विधानमंडळाचे अधिनियम व राज्यपालांनी प्रख्यापित केलेले अध्यादेश व केलेले विनियम आणि विधी व न्याय विभागाकडून आलेली विधेयके (इंग्रजी अनुवाद).

In pursuance of clause (*3*) of article 348 of the Constitution of India, the following translation in English of the Maharashtra Village Panchayats (Amendment and Continuance) Act, 2014 (Mah. Act No. XVIII of 2014), is hereby published under the authority of the Governor.

By order and in the name of the Governor of Maharashtra,

H. B. PATEL,
Principal Secretary to Government,
Law and Judiciary Department.

MAHARASHTRA ACT No. XVIII OF 2014.

(First published, after having received the assent of the Governor in the "*Maharashtra Government Gazette*", on the 25th June 2014).

An Act further to amend the Maharashtra Village Panchayats Act.

Mah. Ord. II of 2014. WHEREAS the Governor of Maharashtra promulgated the Maharashtra Village Panchayats (Amendment) Ordinance, 2014, on the 30th January 2014 ;

AND WHEREAS upon the re-assembly of the State Legislature on the 24th February 2014, the Maharashtra Village Panchayats (Amendment) Bill, 2014 (L. C. Bill No. I of 2014), for replacing the said Ordinance by an Act of the State Legislature was passed by the Maharashtra Legislative Council on the 28th February 2014, and transmitted to the Maharashtra Legislative Assembly ;

AND WHEREAS thereafter, as, the session of the Maharashtra Legislative Assembly was prorogued on the 28th February 2014, the said Bill could not be passed by the Maharashtra Legislative Assembly ;

AND WHEREAS as provided by article 213 *(2) (a)* of the Constitution of India, the said Ordinance would have ceased to operate at the expiration of six weeks from the re-assembly of the State Legislature, that is, after the 6th April 2014 ;

AND WHEREAS both Houses of the State Legislature were not in session and the Governor of Maharashtra was satisfied that circumstances existed which rendered it necessary for him to take immediate action to continue the operation of the provisions of the said Ordinance, for the purposes hereinafter appearing; and, therefore, promulgated the Maharashtra Village Panchayats (Amendment and Continuance) Ordinance, 2014, on the 5th April 2014 ; Mah. Ord. IX of 2014.

AND WHEREAS, it is expedient to replace the said Ordinance by an Act of the State Legislature; it is hereby enacted in the Sixty-fifth Year of the Republic of India as follows :—

Short title and commencement.

1. *(1)* This Act may be called the Maharashtra Village Panchayats (Amendment and Continuance) Act, 2014.

(2) It shall be deemed to have come into force on the 30th January 2014.

Insertion of section 54-1A in III of 1959.

2. In Chapter III-A of the Maharashtra Village Panchayats Act (hereinafter referred to as "the principal Act"), before section 54-A, the following section shall be inserted, namely :— III of 1959.

Special provisions relating to village and *Gram Sabha*.

"**54-1A**. Notwithstanding anything contained in sections 4, 5 or any other provisions of this Act, in the Scheduled Areas,–

(a) a habitation or a group of habitations or a hamlet or a group of hamlets comprising a community and managing its affairs in accordance with traditions and customs, and which is declared as a village in the prescribed manner shall be the village for the purposes of this Chapter ;

(b) every village, so declared under clause *(a)*, shall have a *Gram Sabha* consisting of persons whose names are included in the electoral rolls for the panchayat at the village level and a panchayat may comprise of one or more than one of such villages.".

Mah. Ord. IX of 2014. **3.** *(1)* The Maharashtra Village Panchayats (Amendment and Continuance) Ordinance, 2014 is hereby repealed. Repeal of Mah. Ord. IX of 2014 and saving.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act as amended by the said Ordinance (including any notification issued) shall be deemed to have been done, taken or issued, as the case may be, under the corresponding provisions of the principal Act, as amended by this Act.

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004, EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI

RNI No. MAHENG /2009/35528

Reg. No. MH/MR/South-344/2014-16

सत्यमेव जयते

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

असाधारण भाग आठ

वर्ष ६, अंक २२(४)] बुधवार, जून २५, २०१४/आषाढ ४, शके १९३६ [पृष्ठे ३, किंमत : रुपये २७.००

असाधारण क्रमांक ७०

प्राधिकृत प्रकाशन

महाराष्ट्र विधानमंडळाचे अधिनियम व राज्यपालांनी प्रख्यापित केलेले अध्यादेश व केलेले विनियम आणि विधी व न्याय विभागाकडून आलेली विधेयके (इंग्रजी अनुवाद).

In pursuance of clause (*3*) of article 348 of the Constitution of India, the following translation in English of the Maharashtra Village Panchayats (Amendment and Continuance) Act, 2014 (Mah. Act No. XVIII of 2014), is hereby published under the authority of the Governor.

By order and in the name of the Governor of Maharashtra,

H. B. PATEL,
Principal Secretary to Government,
Law and Judiciary Department.

MAHARASHTRA ACT No. XVIII OF 2014.

(First published, after having received the assent of the Governor in the "*Maharashtra Government Gazette*", on the 25th June 2014).

An Act further to amend the Maharashtra Village Panchayats Act.

Mah. Ord. II of 2014. WHEREAS the Governor of Maharashtra promulgated the Maharashtra Village Panchayats (Amendment) Ordinance, 2014, on the 30th January 2014 ;

AND WHEREAS upon the re-assembly of the State Legislature on the 24th February 2014, the Maharashtra Village Panchayats (Amendment) Bill, 2014 (L. C. Bill No. I of 2014), for replacing the said Ordinance by an Act of the State Legislature was passed by the Maharashtra Legislative Council on the 28th February 2014, and transmitted to the Maharashtra Legislative Assembly ;

AND WHEREAS thereafter, as, the session of the Maharashtra Legislative Assembly was prorogued on the 28th February 2014, the said Bill could not be passed by the Maharashtra Legislative Assembly ;

AND WHEREAS as provided by article 213 *(2) (a)* of the Constitution of India, the said Ordinance would have ceased to operate at the expiration of six weeks from the re-assembly of the State Legislature, that is, after the 6th April 2014 ;

AND WHEREAS both Houses of the State Legislature were not in session and the Governor of Maharashtra was satisfied that circumstances existed which rendered it necessary for him to take immediate action to continue the operation of the provisions of the said Ordinance, for the purposes hereinafter appearing; and, therefore, promulgated the Maharashtra Village Panchayats (Amendment and Continuance) Ordinance, 2014, on the 5th April 2014 ; Mah. Ord. IX of 2014.

AND WHEREAS, it is expedient to replace the said Ordinance by an Act of the State Legislature; it is hereby enacted in the Sixty-fifth Year of the Republic of India as follows :—

Short title and commencement.

1. *(1)* This Act may be called the Maharashtra Village Panchayats (Amendment and Continuance) Act, 2014.

(2) It shall be deemed to have come into force on the 30th January 2014.

Insertion of section 54-1A in III of 1959.

2. In Chapter III-A of the Maharashtra Village Panchayats Act (hereinafter referred to as "the principal Act"), before section 54-A, the following section shall be inserted, namely :— III of 1959.

Special provisions relating to village and *Gram Sabha*.

"**54-1A**. Notwithstanding anything contained in sections 4, 5 or any other provisions of this Act, in the Scheduled Areas,–

(a) a habitation or a group of habitations or a hamlet or a group of hamlets comprising a community and managing its affairs in accordance with traditions and customs, and which is declared as a village in the prescribed manner shall be the village for the purposes of this Chapter ;

(b) every village, so declared under clause *(a)*, shall have a *Gram Sabha* consisting of persons whose names are included in the electoral rolls for the panchayat at the village level and a panchayat may comprise of one or more than one of such villages.".

Mah. Ord. IX of 2014. **3.** *(1)* The Maharashtra Village Panchayats (Amendment and Continuance) Ordinance, 2014 is hereby repealed. Repeal of Mah. Ord. IX of 2014 and saving.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act as amended by the said Ordinance (including any notification issued) shall be deemed to have been done, taken or issued, as the case may be, under the corresponding provisions of the principal Act, as amended by this Act.

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004, EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI

आदिवासी विकास विभागामार्फत राबविण्यात येणा-या वैयक्तिक लाभाच्या योजनेकरीता पेसा अधिनियमाच्या अनुषंगाने अनुसूचित जमातीच्या लाभार्थ्यांची निवड ग्रामसभेव्दारे करण्याबाबत.

महाराष्ट्र शासन

आदिवासी विकास विभाग

शासन निर्णय क्रमांकः ग्रासअ २०१३/ प्र.क्र. १५१ /का-१७

मंत्रालय , विस्तार इमारत, मुंबई ४०००३२

दिनांक : २६ नोव्हेंबर, २०१३

प्रस्तावना

आदिवासी विकास विभागामार्फत अनुसूचित जमातीच्या लाभार्थ्याच्या उन्नतीकरीता विविध प्रकारच्या सामुहिक व वैयक्तिक स्वरुपाच्या योजना राबविण्यात येतात. राज्यातील अनुसूचित जमातीची बहु लोकसंख्या ही ग्रामीण भागात आहे. विभागामार्फत राबविण्यात येणा-या वैयक्तिक योजनेचा लाभ हा नागरी तसेच ग्रामीण व आदिवासी क्षेत्रातील संबंधित लाभार्थ्यांना राज्यातील २९ प्रकल्प कार्यालय असलेल्या एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालर्याकडून देण्यात येतो. सद्य:स्थितीत नागरी, ग्रामीण व आदिवासी क्षेत्रातील लाभार्थ्यांची निवड ही प्रकल्प कार्यालयाकडून करण्यात येते. विभागामार्फत राबविण्यात येणा-या वैयक्तिक लाभाच्या योजनेचे लाभ लाभार्थ्यांना व्यापक स्वरुपात प्राप्त होण्याच्या दृष्टीने ग्रामीण व आदिवासी क्षेत्रातील अनुसूचित जमातीच्या लाभार्थ्यांची निवड ग्रामसभेमार्फत पेसा अधिनियमाशी सुसंगत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती.

शासन निर्णय

आदिवासी विकास विभागामार्फत अनुसूचित जमातीच्या लाभार्थ्याच्या उन्नतीकरीता विविध प्रकारच्या सामुहिक व वैयक्तिक स्वरुपाच्या योजना राबविण्यात येतात. आदिवासी विकास विभागामार्फत खालील प्रकारच्या वैयक्तिक लाभाच्या योजना अनुसूचित जमातीच्या लाभार्थ्यांकरीता राबविण्यात येतात:-

१) खावटी कर्ज योजना.

२) स्वाभीमान सबळीकरण योजनेतर्गंत भूमिहीन आदिवासींना जमिनी देणे.

३) कन्यादान योजना

४) पारधी समाजाच्या योजना

५) आदिम जमातीच्या कुटूंबाना व्यक्तीगत योजनेचा लाभ देणे.

६) शबरी आदिवासी घरकूल योजनेतर्गत आदिवासी पात्र लाभार्थ्यांना घरकूल उलब्ध करुन देणे.

७) आदिवासी शेतक-यांना विज पंप/ तेल पंप, एचडीपीई, पीव्हीसी पाईप्स उपलब्ध करुन देणे.

८) न्युक्लिअस बजेट योजनेतर्गंत राबविण्यात येणा-या योजनांकरीता अर्थसहाय्य.

उपरोक्त योजनांकरीता अनुसूचित जमातीच्या लाभार्थ्यांची निवड ही ग्रामसभेव्दारे करण्यात यावी. यामुळे पेसा अधिनियमाशी सुसंगत अशी कार्यवाही होईल. ग्रामसभेव्दारे निवड करण्यात आलेल्या लाभार्थ्यांना योजनेचा लाभ देण्यासाठी प्रशासकीय बाबींची पूर्तता प्रकल्पस्तरावर एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयाकडून करण्यात येवून त्यानुसार लाभार्थ्यांना अंतिमत: योजनेचा लाभ देण्यास या शासन निर्णयाव्दारे मान्यता देण्यात येत आहे.

आदिवासी उपयोजनेतर्गंत उपलब्ध करुन देण्यात येणा-या निधीतून, पंचायत समिती व जिल्हा परिषदेमार्फत राबविण्यात येणा-या वैयक्तिक लाभाच्या योजनांतील अनुसूचित जमातीच्या लाभार्थ्यांची निवड देखील ग्रामसभेमार्फत करण्यात यावी.

हा शासन निर्णय, ग्राम विकास व जलसंधारण विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक १२/१३/ पंरा ३, दिनांक २१.१०.२०१३ अन्वये दिलेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे.

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१३११२२१२५५५५८७२४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.

Khandare Mahadeo S

Digitally signed by Khandare Mahadeo S
DN: c=IN, o=Government of Maharashtra, ou=MTD, postalCode=400032, st=Maharashtra, cn=Khandare Mahadeo S
Date: 2013.12.11 12:53:19 +05'30'

(म.सो. खंडारे)

अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन

प्रत,

१. मा.राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई

२. मा. मुख्यमंत्र्याचे अप्पर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई
३. मा. उपमुख्यमंत्र्याचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई
४. मा.मंत्री / राज्यमंत्री, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय यांचे खाजगी सचिव
५. मा.सर्व मंत्री / राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव
६. सर्व मा. विधानसभा / विधान परिषद सदस्य
७. मा. मुख्य सचिव
८. प्रधान सचिव, आदिवासी विकास विभाग, यांचे वरीष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई ३२
९. प्रधान सचिव, ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग (ग्राम विकास व पंचायत राज), बांधकाम भवन, मर्झबान पथ, फोर्ट, मुंबई -०१
१०. अप्पर मुख्य सचिव, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई - ३२
११. प्रधान सचिव, कृषी, व पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्य व्यवसाय विभाग, मंत्रालय, मुंबई -३२
१२. आयुक्त, आदिवासी विकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक
१३. आयुक्त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे
१४. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य आदिवासी आर्थिक विकास महामंडळ
१५. प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधान भवन, मुंबई / नागपूर
१६. सर्व अप्पर आयुक्त, आदिवासी विकास, ठाणे, नाशिक, अमरावती व नागपूर
१७. सर्व विभागीय आयुक्त
१८. सर्व जिल्हाधिकारी
१९. सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद
२०. सर्व गटविकास अधिकारी, पंचायत समिती
२१. सर्व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालय
२२. वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२
२३. सर्व मंत्रालयीन विभाग
२४. सर्व उपसचिव/अवर सचिव/कक्ष अधिकारी , आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२
२५. उप सचिव, ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग (प.रां.- ३), बांधकाम भवन, मर्झबान रोड,फोर्ट, मुंबई -०१
२६. निवड नस्ती (का-१७)

अनुसूचित क्षेत्रातील बांबू कापणी व विक्रीची प्रकिया सुलभ करणे, व्यवस्थापन करणे, ग्रामसभा सक्षमीकरण करणे

महाराष्ट्र शासन
ग्राम विकास विभाग
शासन निर्णय क्रमांकः पेसा-२०१२ / प्र.क्र.६५/पंरा-२
बांधकाम भवन, २५, मर्झबान पथ
फोर्ट, मुंबई-४०० ००१
तारीख: २३ नोव्हेंबर २०१५

वाचा :

१) शासन निर्णय, ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग, क्रमांक: पेसा-२०१२ / प्र.क्र.६५/पंरा-२, दिनांक ३१ मार्च २०१५.

प्रस्तावना :

अनुसूचित (पेसा) क्षेत्रातील लोकांच्या हिताच्या व कल्याणाच्या दृष्टीने मा.राज्यपाल महोदयांनी दि.१९.८.२०१४ रोजीच्या अधिसूचनेअन्वये महाराष्ट्र वन उत्पादन (मालकी हक्कांचे हस्तांतरण) अधिनियम, १९९७ मध्ये सुधारणा केली असुन त्यानुसार अनुसूचित क्षेत्रात गौण वनउपजांच्या व्याख्येमध्ये सुधारणा केली आहे. त्यामध्ये "बांबूचा" समावेश केला आहे. त्यानुसार अनुसूचित क्षेत्रातील गौण वनउपजांची मालकी ग्रामसभेकडे/पंचायतीकडे विहीत करण्यात आली आहे.

अ) दि.३० ऑक्टोबर २०१४ च्या अधिसूचनेअन्वये भारतीय वन अधिनियम, १९२७ मध्ये सुधारणा करुन गौण वन उत्पादनासाठी वाहतूक परवाना (Transit Permit) देण्याचे अधिकार ग्रामसभांना देण्यात आलेले आहेत.

ब) ही बाब विचारात घेऊन बांबूची कापणी आणि विक्री यासाठी दि.३१ मार्च २०१५ रोजी पहिला शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला होता. सदर शासन निर्णय या संक्रमण वर्षापुरता मर्यादित असुन दि.३० जुन २०१५ पर्यतच वैध/लागु होता.

क) या शासन निर्णयाच्या अंमलबजावणीतुन या संक्रमण वर्षात असे दिसुन आले आहे की, गडचिरोली जिल्हयामध्ये बांबू कापणी व विक्रीच्या संदर्भात चांगला प्रतिसाद मिळालेला आहे. गडचिरोली जिल्हयातील २० ग्रामपंचायतींनी पर्याय क्रमांक -दोन ची निवड करुन आपले उत्पन्न मोठया प्रमाणात वाढवलेले आहे.

ड) असे असले तरी, मागील संक्रमण वर्षातील बांबू कापणीसाठी अत्यंत कमी कालावधी मिळालेला असल्याने इतर जिल्हयांमध्ये बांबू मोठया प्रमाणात कापणीसाठी उपलब्ध झालेला नव्हता.

इ) गडचिरोली जिल्हयात दि.२४ सप्टेंबर २०१५ रोजी आयोजित केलेल्या बैठकीत उपस्थित असलेल्या संबंधितांनी दिलेले अभिप्राय (feedback) आणि मागिल वर्षात राबविण्यात आलेल्या प्रक्रियांच्या अनुभवाच्या आधारे असे लक्षात येते की, जिल्हा मार्गदर्शन व तक्रार निवारण समितीने स्वंयप्रेरणेने ग्रामसभांना मार्गदर्शन करणे आवश्यक आहे. त्याचबरोबर ग्रामसभांचे कायमस्वरुपी भरीव सक्षमीकरण करणे आवश्यक आहे.

वरील सर्व अभिप्राय विचारात घेवुन दि.३१ मार्च २०१५ चा शासन निर्णय अधिक्रमीत करुन नवीन सुधारीत शासन निर्णय निर्गमित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती आणि त्यानुसार खालीलप्रमाणे निर्णय शासनाने घेतलेला आहे.

२. शासन निर्णय:-

ज्या अनुसूचित क्षेत्रामध्ये या हंगामात वनविभागाच्या Working Plan अनुसार बांबू कापणीयोग्य झाला आहे अशा विशेष क्षेत्रांची/गावांची/पंचायतींची मुख्य वनसंरक्षक/उपवनसंरक्षक यांनी निवड करावी आणि त्याची माहिती मुख्य कार्यकारी अधिकारी व स्थानिक गट विकास अधिका-याला दयावी.

एखादया गावी किंवा पंचायतीमध्ये बांबू कापणी योग्य आहे परंतु वनविभागाने सदर गावाची/ पंचायतीची निवड केलेली नाही किंवा सदर गाव / पंचायत अधिसुचित केलेले नसेल तर ग्रामसभेला जिल्हास्तरीय मार्गदर्शन तक्रार निवारण समितीकडे आपली भुमिका मांडता येईल व त्यावर जिल्हास्तरीय मार्गदर्शन व तक्रार निवारण समिती योग्य तो निर्णय घेईल आणि समितीचा निर्णय अंतीम राहील.

अनुसूचित क्षेत्रातील (पेसा क्षेत्र) बांबू क्षेत्र असलेल्या गावातील ग्रामसभा आणि पंचायत कोणत्या पध्दतीने बांबूची कापणी व विक्री यांची विल्हेवाट लावु इच्छिते यासाठी विचार विनिमय करण्यासाठी मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी त्या- त्या ठिकाणी ग्रामसभेचे आयोजन करावे.

आवश्यकता असल्यास महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम, १९५८ च्या कलम ७ (१) मधील तरतुदींनुसार विशेष ग्रामसभा आयोजित कराव्यात.

महाराष्ट्र वन उत्पादन (मालकी हक्कांचे हस्तांतरण) अधिनियम, १९९७ च्या तरतुदी व त्यामधील बदल, गौण वन उत्पादनाची व्याख्या या सर्व बाबी ग्रामसभेमध्ये सोप्या भाषेत समजावुन सांगण्यात याव्यात.

३. बांबूची कापणी व विक्री या संदर्भात ग्रामसभेस खालील दोन पर्यांयामधून एका पर्यायाची निवड करता येईल. यासाठी ग्रामसभेचे मत/ अभिप्राय ठरावाच्या स्वरुपात घेण्यात यावे. ठरावाचे नमुने अनुसूची-अ (पर्याय-एक) व अनुसूची-ब (पर्याय-दोन) मध्ये देण्यात आलेले आहेत.

पर्याय १. ग्रामसभा यांनी वनविभागाच्या सेवा प्राप्त करुन घेवुन वन विभागाच्या प्रचलित पध्दतीप्रमाणे वनविभागाने बांबूची कापणी व विक्री करावी व यापासुन येणारे उत्पन्न वन विभागाने मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद यांच्या खात्यावर जमा करावे आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी सदर रक्कम संबंधित ग्रामसभाकोष खात्यावर जमा करावी.

लिलाव करण्याअगोदर, स्थानिक गरजा व पारंपारिक व्यवसाय करणा-यांच्या गरजा / निस्तार हक्क विचारात घेवुन निर्णय घेईल व त्यानंतर शिल्लक राहीलेला बांबूचा लिलाव करेल.

किंवा

पर्याय २. ग्रामसभा स्वत: आवश्यकतेनुसार संबंधित विभागांचे तांत्रिक सहाय्य घेवून योग्य कार्यपध्दती अनुसरुन बांबूची कापणी, विक्री करु शकतात.

पर्याय २ निवडल्यास खालील पध्दतीचा अवलंब करण्यात यावा.

I. ग्रामसभा, ठरावांसह बांबू कापणीचे/ बांबू मिळविण्याचे परंपरागत क्षेत्र व त्याची हद्द निश्चित करील.

ही बाब पर्याय एक व पर्याय दोन निवडणा-या दोघांसाठीही लागु राहील.

II. एखादया प्रकरणी, शेजारील गावाबरोबर हद्दीबाबत/क्षेत्राबाबत विवाद निर्माण झाल्यास जिल्हाधिकारी वन विभागाशी तसेच सर्व संबंधिताशी विचार विनिमय करुन हद्द निश्चित करतील.

III. बांबूच्या कापणीसाठी ग्रामसभा, दोन ते तीन अनुभवी व्यक्तींची (Master Cutter) नियुक्ती करु शकेल. वन विभाग त्यांना बांबू कापणीचे अतिरिक्त प्रशिक्षण देऊ शकेल. हया व्यक्ती गावातील इतर ग्रामस्थांना बांबूची कापणी शास्त्रशुध्द पध्दतीने कशी करावी, याबाबतचे मार्गदर्शन करतील. कोणत्याही परिस्थितीत अशास्त्रशुध्द पदधतीने बांबूची कापणी होणार नाही याची खात्री करतील.

IV. कापणीसाठी येणारा मजुरांचा खर्च ग्रामसभा स्वत: भागवतील आणि जेथे- जेथे शक्य आहे तेथे आदिवासी विकास विभाग /आदिवासी विकास महामंडळ या उददेशासाठी फिरता निधी उपलब्ध करुन देतील. मानव विकास मिशन व इतर तत्सम योजनांखाली असलेला निधी यासाठी उपलब्ध करुन देता येईल (नियोजन विभाग शासन निर्णय

क्रमांक माविका-२०१४/प्र.क्र.१२/का-१४१८ दि.२१ ऑगस्ट २०१४). जिल्हाधिका-यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेली समिती ग्रामपंचायतीला मार्गदर्शन करेल व यासंदर्भात योग्य तो निर्णय घेईल.

V. पंचायत समितीच्या विस्तार अधिका-या पेक्षा कमी दर्जा नसलेल्या अधिका-याच्या उपस्थितीत ग्रामसभा बांबूची लिलाव पध्दतीने विल्हेवाट लावतील. लिलाव करण्याअगोदर, स्थानिक गरजा व पारंपारिक व्यवसाय करणा-यांच्या गरजा/निस्तार हक्क विचारात घेऊन ग्रामसभा निर्णय घेईल व त्यानंतर शिल्लक राहीलेल्या बांबूचा लिलाव करेल.

VI. ग्रामसभेने बांबू कापणी, विक्री वा विल्हेवाटीसाठी आदिवासी विकास विभाग अथवा संबंधित विभागाकडुन आगावु रक्कम घेतलेली असेल तर पंचायतीचा संबंधित अधिकारी अशी रक्कम वजा करुन घेईल आणि संबंधित विभागाला परत करेल.

VII. ग्रामसभेने कापणी केलेल्या बांबूची साठवणुक करण्यासाठी वनविभाग, जिल्हा परिषद, आदिवासी विकास विभाग अल्पदराने आपली आगारे (Depots) उपलब्ध करुन देतील.

ज्या ग्रामसभा पर्याय-२ निवडतील त्या वाहतूक परवाना (Transit Permit) देण्यास सक्षम असतील आणि वाहतुक परवाना पुस्तक (Transit Permit Book) वन विभागाकडुन वेळेवर उपलब्ध करुन घेण्यात येईल. यासंदर्भातील विलंब टाळण्यासाठी पर्याय म्हणुन जिल्हास्तरीय मार्गदर्शक व तक्रार निवारण समिती वाहतुक परवाना पुस्तक (Transit Permit Book) उपलब्ध करुन देऊ शकेल.

४. **ज्या ग्रामसभा कोणताही ठराव करणार नाहीत त्यांनी पर्याय -२ (दोन) ची निवड केली असे समजण्यात येईल.**

अनुसूचीत जमाती व इतर पारंपारीक वन निवासी (वन हक्क मान्य करणे) अधिनियम, २००६ अंतर्गत आदिवासी तसेच इतर पारंपारीक वन निवासी यांना गौण वनउपज मिळविण्याचे अधिकार प्रदान करण्यात आलेले आहेत. सदर अधिनियमामध्ये नमुद केलेल्या कार्यप्रणालीप्रमाणे जी ग्रामसभा बांबूची विल्हेवाट लावण्यास इच्छुक आहे त्यांचेवर हा शासन निर्णय बंधनकारक असणार नाही. त्यांनी सदर अधिनियम आणि त्याअंतर्गतच्या नियमाप्रमाणे कार्यवाही करावी.

५. **जिल्हा मार्गदर्शन व तक्रार निवारण समिती**

ग्रामसभा अथवा ग्रामसभेने नियुक्त केलेले प्रतिनिधी अथवा समितीच्या काही तक्रारी / अडीअडचणी असतील तर ते जिल्हा स्तरीय मार्गदर्शन व तक्रार निवारण समितीकडे अर्ज करु शकतील.

जिल्हास्तरीय मार्गदर्शन व तक्रार निवारण समिती खालील प्रमाणे असेल

१. जिल्हाधिकारी	अध्यक्ष
२. मुख्य वन संरक्षक (CCF)	सह-अध्यक्ष
३. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि.प.	अध्यक्ष
४. उप वन सरंक्षक (DCF)	सदस्य
५. प्रकल्प अधिकारी आदिवासी विकास विभाग	सदस्य
६. उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रा.प.)	सदस्य सचिव
७. जिल्हाधिकारी यांनी निवडलेले ग्रामसभेचे तीन सभासद	सदस्य
८. जिल्हाधिकारी यांनी निवडलेले समाजिक संघटनेतील दोन प्रतिनिधी	सदस्य

६ जिल्हयामध्ये ज्यावेळी पेसा कक्ष स्थापन करण्यात येईल त्यावेळी सदर कक्ष जिल्हा मार्गदर्शन व तक्रार निवारण समितीचे सचिवालय म्हणुन काम पाहील. सदर पेसा कक्ष मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रामपंचायत) यांच्या नियंत्रणाखाली काम करेल. पेसा अधिनियम आणि नियम याअंतर्गत येणारी सर्व कामे हा कक्ष पार पाडेल.

७. जिल्हा मार्गदर्शन व तक्रार निवारण समिती या शासन निर्णयाची अंमलबजावणी करताना येणा-या सर्व अडीअडचणी सोडविण्यासाठी आवश्यक ती पावले उचलेल. मार्गदर्शक सुचनांची अंमलबजावणी करण्यासाठी क्षेत्रीय स्तरावर सर्व प्रकारच्या मार्गदर्शक सुचना देईल. या

प्रेरणादायक मार्गदर्शक सुचनांमुळे हा संपुर्ण कार्यक्रम यशस्वी होण्यास मदत होईल. या समितीसाठी मार्गदर्शक सुचना **अनुसूची-एक** मध्ये दिलेल्या आहेत.

८. ग्रामसभांना सुयोग्य निर्णय घेण्यासाठी संबंधित तालुक्याचे गटविकास अधिकारी/पंचायत समितीचे अधिकारी/कर्मचारी योग्य ते मार्गदर्शन व मदत करतील.

ग्रामसभांना सशक्त करण्यासाठी आणि पर्याय क्रमांक-दोन यशस्वी करण्यासाठी **अनुसूची-दोन** मध्ये मार्गदर्शक सुचना देण्यात आलेल्या आहेत.

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१५११२०१०४७११३०२० असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.

V Giriraj

Digitally signed by V Giriraj
DN: c=IN, o=All India Service, ou=Principal Secretary, postalCode=400032, st=Maharashtra, cn=V Giriraj
Date: 2015.11.23 13:14:26 +05'30'

वि.गिरिराज
प्रधान सचिव, महाराष्ट्र शासन

प्रत,

१. मा.राज्यपालांचे सचिव,
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव,
३. मा.मंत्री (ग्राम विकास) यांचे खाजगी सचिव,
४. मा.राज्यमंत्री (ग्राम विकास) यांचे खाजगी सचिव,
५. मा.मुख्यसचिव, महाराष्ट्र शासन,
६. मा.प्रधान सचिव (आदिवासी विकास), मंत्रालय, मुंबई,
७. मा. सचिव (वने), मंत्रालय, मुंबई,

८. सर्व विभागीय आयुक्त,

९. जिल्हाधिकारी, ठाणे, पालघर, नाशिक, नंदुरबार, धुळे, अहमदनगर, जळगाव, अमरावती, यवतमाळ, चंद्रपुर, गडचिरोली, पुणे, नांदेड.

१०. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ठाणे, पालघर, नाशिक, नंदुरबार, धुळे, अहमदनगर, जळगाव, अमरावती, यवतमाळ, चंद्रपुर, गडचिरोली, पुणे, नांदेड.

११. उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रा.पं), ठाणे, पालघर, नाशिक, नंदुरबार, धुळे, अहमदनगर, जळगाव, अमरावती, यवतमाळ, चंद्रपुर, गडचिरोली, पुणे, नांदेड.

१२. गटविकास अधिकारी, पंचायत समिती, ठाणे, पालघर, नाशिक, नंदुरबार, धुळे, अहमदनगर, जळगाव, अमरावती, यवतमाळ, चंद्रपुर, गडचिरोली, पुणे, नांदेड. (जिल्हयातील सर्व पाचव्या अनुसूचीतील गावे असणारे तालुके)

१३. निवडनस्ती, पं.रा.-२.

अनुसूची-अ

ठराव क्र.१-(पर्याय-१)

ज्याअर्थी बांबूसह सर्व गौण वनउत्पादनांची मालकी पंचायत आणि ग्रामसभेकडे विहित करण्यात आली आहे.

म्हणुन आम्ही ग्रामसभेचे मतदार, बांबूची कापणी / विक्री/ वाहतुक आणि विल्हेवाट करण्यासाठी आमच्या वतीने **वनविभागास प्राधिकृत करीत आहोत.**

पुढे आम्ही असाही ठराव करतो की, आमच्या गावाची/ ग्रामपंचायतीची बांबू कापणी योग्य असलेली क्षेत्रे निश्चित करीत आहोत.

आम्ही, बांबू कापणी/ विक्रीची अंतिम विल्हेवाट लावण्याच्या संपुर्ण प्रक्रियेचे नियंत्रण, पर्यवेक्षण करण्यासाठी ग्रामसभेतील/ साधन संपत्ती नियोजन व सनियंत्रण समितीतील खालील प्रतिनिधींची नियुक्ती करीत आहोत. (४ प्रतिनिधीपर्यंत)

अनुसूची-ब

ठराव क्र.२-(पर्याय-२)

ज्याअर्थी बांबूसह सर्व गौण वनउत्पादनांची मालकी पंचायत आणि ग्रामसभेकडे विहित करण्यात आली आहे.

म्हणुन आम्ही ग्रामसभेचे मतदार असा ठराव करतो की, आमची ग्रामसभा बांबूची कापणी व विक्री खरेदी, वाहतुक आणि विल्हेवाट स्वत: करेल.

पुढे आम्ही असाही ठराव करतो की, आमच्या गावाची/ग्रामपंचायतीची बांबू कापणी योग्य असलेली क्षेत्र निश्चित करीत आहोत आणि बांबू कापणी व विक्रीसाठी, वनविभाग आणि इतर सर्व संबंधित विभाग आवश्यक ते सर्व तांत्रिक व इतर सहाय्य ग्रामसभेला करण्याची मागणी करीत आहोत.

<u>अनुसूची-एक</u>

मार्गदर्शक सुचना

जिल्हा मार्गदर्शन व तक्रार निवारण समितीची भुमिका आणि जबाबदारीशी संबंधित मार्गदर्शक सुचना :-

I. जिल्हा मार्गदर्शन व तक्रार निवारण समितीने ग्रामसभेची योग्य अशा पध्दतीने क्षमता बांधणी करणे गरजेचे आहे. ही क्षमता बांधणी अशा प्रकारे करण्यात यावी की, ग्रामसभा बांबु विक्री पारदर्शकरित्या परिणामकारकपणे करु शकतील. ग्रामसभांना क्षेत्रनिहाय प्रशिक्षण देता येऊ शकेल.

II. यासाठी बाबूंच्या हंगामात पेसा क्षेत्रात जिल्हा मार्गदर्शन व तक्रार निवारण समिती अर्धवेळ किंवा पुर्ण वेळ अतिरिक्त कर्मचारी वर्गाची नियुक्ती करु शकतात. हे कर्मचारी निवृत्त झालेले वन कर्मचारी अथवा सामाजिक कार्यकर्ते असु शकतात. समिती काही सेवा बाहय स्त्रोतांकडुन देखिल घेऊ शकतात.

III. यासाठी समिती मानव विकास कार्यक्रम, आदिवासी विकास विभागाच्या केंद्रिय अर्थसंकल्प व इतर अशा निधीतुन खर्च भागवु शकेल.

IV. जिल्हा मार्गदर्शन व तक्रार निवारण समितीने बांबूच्या विक्रीसाठी एक प्रमाणित पध्दत निश्चित करण्यासाठी ग्रामस्थाना मार्गदर्शन करणे आवश्यक आहे. या संदर्भात ग्राम समिती व खरेदीदारांच्यासाठी एक आदर्श विक्री करारनाम्याचे वितरण समितीला करता येईल.

V. ग्रामसभांकडुन कमी प्रमाणात गौण वनउपजाचा लिलाव करण्यात येतो. या लिलावातुन योग्य दराचा फायदा मिळण्यासाठी चांगली बाजारपेठ उपलब्ध करणे किंवा ग्रामसभांच्या संमतीने जिल्हयातील एकत्रित ई-लिलावाव्दारे विक्री करण्यासाठी व्यासपीठ (Platform) उपलब्ध करणे ही जिल्हा मार्गदर्शन व तक्रार निवारण समितीची कार्यकक्षा राहील.

VI. सदर समिती वाहतुक परवाना (Transit Permit) वन विभागाकडुन एकत्रित घेऊन ग्रामसभांना पुरवु शकेल.

VII. ग्रामसभेला वाहतुक परवाना (Transit Permit) विहित मुदतीत मिळेल याची खात्री समितीने करावी.

VIII. कामाच्या हंगामामध्ये ग्रामस्थांच्या अडचणी सोडविण्यासाठी जिल्हा / तालुका पेसा समन्वयक यांचा दुरध्वनी क्रमांक /सहायता केंद्र (HELPLINE) उपलब्ध करुन देता येईल.

IX. माहितीपत्रके किंवा चित्रपटाव्दारे ग्रामस्थाना मदत करता येऊ शकेल.

X. संसाधन नियोजन आणि व्यवस्थापन समितीच्या सदस्यांची शैक्षणिक सहल आयोजित करता येईल.

अनुसूची-दोन

ज्या ग्रामसभा पर्याय-२ निवडतील त्यांच्यासाठी मार्गदर्शक सूचनाः-

ग्रामसभेचे बळकटीकरण करण्यासाठी आणि बांबूची विक्री परिणामकारकरित्या हाताळण्यासाठी खालीलप्रमाणे मार्गदर्शक सुचना देण्यात येत आहेत.

I. गावक-यांना वेतन अदा करताना ग्रामसभाकोषातुन शक्यतो बँक खात्यातुन धनादेशाव्दारे अथवा पासबुकव्दारे अदा करावे. शक्यतोवर जेवढे आवश्यक असेल तेवढेच रोखीने वेतन अदा करावे.

II. बांबूच्या विक्रीतुन भरीव असे उत्पन्न ग्रामकोषामध्ये जमा होण्याची शक्यता असल्याने ही रक्कम फक्त पगारासाठी शक्यतो अदा करण्यात येवु नये काही प्रमाणात रक्कम (उदा.२५%) सार्वजनिक हितासाठी वापरावी.

III. पेसा नियम (प्रकरण तीन मध्ये नमुद केल्याप्रमाणे) योग्य पध्दतीने खाती पुस्तक ठेवणे आवश्यक राहील. यासाठी गावातील सुशिक्षित मुले ठेवता येऊ शकतील. त्यासाठी त्यांना योग्य मानधन देण्यात यावे.

IV. ग्रामस्थांनी कंत्राटदार किंवा त्यांच्या माणसाच्या माध्यमातून बांबू कापणी न करता स्वत: बांबू कापणी करणे आवश्यक आहे.

V. असे निदर्शनास आले आहे की, जर खालीलप्रमाणे बांबूची विक्री केली तर ग्रामसमितीला बांबू विक्रीतुन अधिक उत्पन्न मिळु शकते.

अ) बांबूच्या जुडग्यांची विक्री करण्याऐवजी पुर्ण बांबूची विक्री करणे.

आ) पुर्ण बांबू योग्य पध्दतीने प्रमाणित करुन श्रेणीनिहाय वेगळा करण्यात यावा.

ग्रामसभांनी या पध्दतीने व्यवहार केल्यास त्यांच्या उत्पन्नामध्ये भरीव वाढ होण्याची शक्यता आहे.

वरील मार्गदर्शक सुचनांच्या अंमलबजावणीतुन असे अपेक्षित आहे की, हळु हळु आणि नजीकच्या काही वर्षात ग्रामसभा बांबू कापणी आणि विक्री यांच्यामध्ये पुर्णपणे सक्षम झाल्याचे दिसुन येईल.

राज्यातील अनुसूचित क्षेत्रातील ग्रामपंचायतींना आदिवासी उपयोजनेअंतर्गत ५% निधी थेट अनुदान म्हणुन देण्याबाबत ग्रामसभा कोष संदर्भातील मार्गदर्शक सुचना.

महाराष्ट्र शासन
आदिवासी विकास विभाग
शासन निर्णय क्रमांक: पेसाअ-२०१५/प्र.क्र.९८/का.१७,
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक,
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२
दिनांक : २१ ऑगस्ट, २०१५

वाचा :-१. आदिवासी विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.पेसा२०१५/प्र.क्र.१९/का-१७, दि.२१.०४. २०१५.
२. ग्राम विकास व जलसंधारण विभागाची नस्ती क्र. पेसाअ २०१५/प्रक्र ३५ (भाग -१)/ पंरा २.

शासन निर्णय :-

राज्यात आदिवासी जनतेच्या हितासाठी व प्रगतीसाठी राज्यात पंचायत विस्तार अधिनियम, १९९६ अंतर्गत राज्य शासनाच्या ग्रामविकास विभागाने नियम तयार केले असुन त्यानुसार आदिवासी जनतेला त्यांच्या प्रथा, परंपरा तसेच नैसर्गिक साधन संपत्तीचे जतन करण्याचे अधिकार प्रदान करण्यात आलेले आहेत. राज्यातील आदिवासी जनतेची प्रगती व्हावी, त्यांना मुख्य प्रवाहात सामिल होता यावे यासाठी वाडया-वस्त्या-पाडे यांच्यासाठी स्वतंत्र ग्रामसभेची तरतुद करण्यात आली आहे. जेणे करुन आदिवासी ग्रामसभेमार्फत आपल्या हक्कांचे निर्णय घेवु शकतील.

आदिवासी जनतेच्या प्रगतीसाठी आदिवासी विकास विभागामार्फत एकुण नियतव्ययाच्या ५% मुक्त निधी अनुसूचित क्षेत्रातील ग्रामपंचायतींना उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. सदर निधी ग्रामपंचायतीच्या ठिकाणच्या गावांचा ग्रामसभा कोषाच्या खात्यामध्ये थेट वर्ग करण्यात येणार आहे. हा निधी मिळाल्यानंतर, निधी कशाप्रकारे व कोणत्या बाबींवर खर्च करावा याचा निर्णय संबंधित ग्रामपंचायतीची ग्रामसभा या विभागाने दि.२१ एप्रिल २०१५ रोजी निर्गमित केलेल्या संदर्भाधिन शासन निर्णयास अनुसरुन घेणार आहे असे असले तरी, यासाठी ग्रामसभा कोष संदर्भात मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करणे या विभागाच्या विचाराधीन होते. ही बाब विचारात घेवुन या शासन निर्णयान्वये खालीलप्रमाणे मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्यात येत आहेत.

१. अनुसूचित क्षेत्रासाठी महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमात प्रकरण ३-अ समाविष्ट करण्यात आले असुन कलम ५४-१अ,ब,क,ड समाविष्ट करण्यात आले आहे. यानुसार अनुसूचित क्षेत्रातील ग्रामसभा व पंचायत यासाठी विशेष तरतुदी करण्यात आलेल्या आहेत. कलम ५४-ब अन्वये अनुसूचित क्षेत्रातील पंचायतीचे अधिकार व कर्तव्य नमुद करण्यात आली असुन पंचायतीने ग्रामसभेच्या मान्यतेने हाती घेतलेल्या कामाची अंमलबजावणी करण्यास पंचायत सक्षम असेल.

२. पंचायत विस्तार अधिनियम १९९६ (पेसा) चे अंमलबजावणीसाठी आदिवासी उपयोजनेअंतर्गत प्राप्त होणा-या एकुण नियतव्ययापैकी ५% निधी अनुसूचित क्षेत्रातील ग्रामपंचायतींना त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात वितरीत करण्यात येणार आहे. अनुसूचित

क्षेत्रातील ग्रामपंचायतींना उपलब्ध होणा-या निधीमधुन अ) पायाभुत सुविधा ब) वनहक्क अधिनियम व पेसा अधिनियमाची अंमलबजावणी क) आरोग्य, स्वच्छता व शिक्षण ड) वन्यजीव संवर्धन, जलसंधारण, वन्यजीव पर्यटन व वन उपजिविका या व इतर संबंधित बाबींकरिता आदिवासी विकास विभागाकडुन निधी उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे.

या निधीच्या नियोजनासाठी पेसा नियमातील नियम १४ नुसार ग्रामसभाकोष समिती स्थापन करणे आवश्यक आहे. यासाठी तातडीने ग्रामसभेचे आयोजन करावे या ग्रामसभेत ग्रामसभाकोष समिती स्थापन करुन या समितीच्या नावे राष्ट्रीयकृत किंवा शेड्यूल बँकेत खाते उघडण्यात यावे. यासंदर्भात मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी तातडीने कार्यवाही करण्याचे निर्देश सर्व संबंधितांना दयावेत.

३. पंचायत विस्तार अधिनियमांतर्गत नियम ४ मध्ये नवीन गाव करण्याची मुभा आहे. प्रत्येक गावासाठी एक ग्रामसभा असेल व प्रत्येक ग्रामसभेसाठी एक ग्रामसभा कोष असेल. या ग्रामसभाकोषासाठी ग्रामसभाकोष समिती असेल, या समितीचा कार्यकाल तिच्या स्थापनेच्या दिनांकापासुन पाच वर्षाचा असेल.

४. ग्रामसभेच्या बैठकींबाबतची कार्यवाही महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमाच्या कलम ५४ -क व पेसा नियमांच्या नियम ९ नुसार करण्यात यावी.

५. या विभागाकडून प्राप्त झालेल्या ५% निधीची रक्कम सध्या अस्तित्वात असलेल्या ग्रामसभेच्या ग्रामसभा कोषात जमा करावी जेणेकरून ग्रामसभांना त्यांच्या प्राधान्य क्रमानुसार निर्णय घेता येतील व त्या कामाकरिता ग्रामकोषातील निधीचा त्यांना वापर करता येईल. निधी प्राप्त झाल्यानंतर ग्रामसभेने या विभागाच्या शासन निर्णय, दि. २१ एप्रिल २०१५ प्रमाणे लोकसंख्येच्या प्रमाणात विकास कामासाठी निधी उपलब्ध करून विकास कामे पूर्ण करावीत. नवीन पेसा गाव स्थापन झाल्यानंतर त्या गावाच्या ग्रामकोषामध्ये आदिवासी विकास विभागाकडून पुढील आर्थिक वर्षापासुन निधी जमा करण्यात येईल.

अ) ग्रामसभा कोषाचे खाते राष्ट्रीयकृत किंवा शेड्यूल बँकेत ग्रामसभाकोष समिती या नावाने उघडावे. हे खाते ग्रामसभा कोष समितीतील दोन सदस्य (पैकी एक महिला) (या दोन सदस्यांपैकी किमान एक सदस्य आदिवासी जमातीचा असेल) व ग्रामसेवक यांच्या संयुक्त नावे असेल. या तीन लोकांनी ग्रामकोषाचे आर्थिक व्यवहार ग्रामसभेच्या नियंत्रणाखाली करावेत.

ब) ग्रामस्तरावर ठेवावयाचे नमुने सुलभ असावेत व कमीत कमी असावेत ही बाब विचारात घेवुन तसेच प्रत्येक कृतीला किंवा कामाला ग्रामसभेची मान्यता घ्यावयाची असल्याने महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम व नियमातर्गत विहित करण्यात आलेले नमुने ग्रामसभास्तरावर ठेवण्यात यावेत. (परिशिष्ट -१ मध्ये नमुन्यांची यादी दिलेली आहे.)

क) ग्रामसभा कोषातील जमाखर्चाच्या नोंदी त्या त्या वेळीच पूर्ण कराव्यात.

ड) प्रत्येक व्यवहाराला ग्रामसभेची मंजुरी घेणे बंधनकारक आहे. कोणाकडून, किती व कोणत्या कारणासाठी रक्कम जमा केली तसेच कोणाला, किती व कोणत्या कारणासाठी रक्कम अदा केली याचे वाचन ग्रामसभेत करून प्रत्येक आर्थिक व्यवहाराची माहिती ग्रामसभेला देण्यात यावी.

६. जमा केलेल्या रकमेची त्वरित पोहोच द्यावी तसेच रक्कम अदा केल्याबरोबर त्याची पोच पावती तयार करून त्यावर रक्कम अदा केली असा शेरा मारून ग्रामसभा कोष समितीच्या सदस्यांनी व ग्रामसेवकाने त्याखाली स्वाक्षरी करावी.

७. प्रत्येक महिन्याच्या अखेरीस ग्रामसभा कोषातील रक्कम व बँकेतील नोंदी यांचा ताळमेळ घ्यावा व शेरा मारून ग्रामसभा कोष समिती सदस्यांनी ते स्वाक्षरीत करावे. व पुढील येणा-या ग्रामसभेत त्याला मंजुरी घेणेत यावी.

८. ग्रामसभेच्या सर्व आर्थिक व्यवहारांना प्रथम ग्रामसभा कोष समिती जबाबदार असेल. एखादा आर्थिक व्यवहार बेकायदेशीर,चुकीचा किंवा नुकसानीचा आहे असे एखाद्या सदस्यास वाटत असेल तर त्याने ती बाब समिती सदस्यांच्या व ग्रामसभेच्या निदर्शनास आणून देणे हे त्याचे कर्तव्य असेल.

९. ग्रामसभा कोषाच्या संदर्भातील नोंदवह्या शासनाने ग्रामपंचायतीच्या रेकॉर्ड संबंधाने जो कालावधी निर्धारित केला आहे त्या काळापर्यंत प्रचलित पध्दतीने ग्रामसेवकाने जपून ठेवाव्यात. व सदरचे रेकॉर्ड संबंधित अधिका-यांना तपासणीसाठी ग्रामसेवक उपलब्ध करुन देईल.

१०. ग्रामसभा कोषाचे सर्व आर्थिक व्यवहार पारदर्शीपणे केले जातील. सर्व आर्थिक व्यवहार ग्रामसभेची मान्यता घेवूनच केले जातील. वर्षाअखेरीस एकूण झालेला खर्च, त्यातून केलेले काम व कामाची गुणवत्ता व त्याची उपयोगिता ग्रामसभेसमोर मांडून सर्व कामांच्या अंमलबजावणीच्या कार्यवाहीला ग्रामसभेची मान्यता घेण्यात यावी. **पंचायतीने हाती घेतलेल्या कामांकरिता सर्व निधीच्या वापराचे उपयोगिता प्रमाणपत्र (Utilization Certificate) ग्रामसभेकडुन मिळविणे बंधनकारक राहील.**

११. ग्रामसभा कोषातून जी कामे केली जातील त्या कामाची माहिती देणारे फलक कामाच्या ठिकाणी लावले जातील. फलकावर कोणत्या महत्त्वाच्या बाबीवर किती खर्च झाला हे ठळक अक्षरात नमूद करावे. (उदा. एकूण सिमेंट, स्टील, विटा, मशनरी, मजुरी इत्यादीवर झालेला खर्च.)

१२. ग्रामपंचायत करत असलेल्या कामांच्याबाबत प्राधान्याने स्थानिक लोकांना/मजुरांना कामाची संधी उपलब्ध करुन दयावी. मजुरीची अदायगी मजुराच्या बँक खात्यावर करण्यात यावी.

१३. ग्रामसभा कोषांच्या नोंदवह्यांतील नोंदी ग्रामसेवक करेल. ग्रामसेवकाच्या अनुपस्थितीत ग्रामसभा ज्या कर्मचाऱ्यावर जबाबदारी सोपवेल तो किंवा ग्रामसभा कोष समितीचा सदस्य ग्रामसभा कोष नोंदवहीत नोंदी करेल व त्या नोंदी ग्रामसभा कोष समितीचे सदस्य साक्षांकित करतील.

१४. ग्रामसभेने हाती घेतलेल्या कामाचे किमान तीन फोटो (१.काम सुरु होण्यापूर्वी, २. काम सुरु असताना ३. काम पूर्ण झाल्यावर) घेण्यात येऊन ते जपून ठेवावेत तसेच आदिवासी विकास विभागाकडुन विकसित करण्यात येत असलेल्या संगणक प्रणालीवर उपलब्ध (अपलोड) करावेत. दुर्गम भागात यामध्ये अडचण निर्माण होवू नये यासाठी गट विकास अधिकारी यांनी ग्रामसभेला याकामी आवश्यक ते सहाय्य करावे, तसेच येणारा खर्च त्या कामावर दर्शविण्यात यावा.

१५. रु. ३ लाखांच्या वरील कामाचे अंदाजपत्रक त्या विषयाचा तालुका स्तरावरील खाते प्रमुख तयार करेल. या कामांना प्रशासकीय मान्यता ग्रामसभा देईल व तांत्रिक मान्यता गटविकास अधिकारी यांनी ठरवुन दिलेल्या तांत्रिक अधिका-यामार्फत देण्यात यावी. या कामी पंचायत समिती व जिल्हा परिषद ग्रामसभेला आवश्यक ती सहाय्यता व मनुष्यबळ उपलब्ध करुन देतील.

१६. रु. ३ लाखाच्या आतील कामाचे अंदाजपत्रक पंचायत समितीचा त्या विषयाशी निगडीत अधिकारी किंवा ग्रामसभा ठरवील ती व्यक्ती किंवा संस्था तयार करेल व या कामाला ग्रामसभेची मंजुरी म्हणजे ती ग्रामसभेची प्रशासकीय मान्यता समजण्यात येईल.

१७. पंचायतीने ग्रामसभेच्या मान्यतेने ग्रामसभाकोषातुन हाती घेतलेल्या सर्व कामांच्या खर्चाचे लेखा परिक्षण सनदी लेखापाल (सी. ए.) मार्फत दरवर्षी करून घेणे बंधनकारक असेल.

१८. ग्रामसभेची मंजुरी मिळाल्यानंतर साहित्य खरेदी करतेवेळी किंवा कामाचा ठेका देतेवेळी ग्रामसभा कोष समितीने सर्वसाधारण परिस्थितीत किमान ३ पुरवठादाराकडून दरपत्रक मागविणे आवश्यक आहे. ज्या पुरवठा दाराचे दर कमी आहेत व मालाचा किंवा सेवेचा दर्जा अपेक्षेप्रमाणे असेल त्याला ग्रामसभा मंजुरी देईल या कामी ग्रामसभेला पंचायत मदत करेल.

सदर शासन निर्णय ग्रामविकास विभागाकडून प्राप्त सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे.

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१५०८२११६३८३८३१२४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

Rajagopal Devara

Digitally signed by Rajagopal Devara
DN: c=IN, o=All India Service, ou=IAS, postalCode=110001, st=Maharashtra, cn=Rajagopal Devara
Date: 2015.08.21 16:46:49 +05'30'

(राजगोपाल देवरा)
सचिव, महाराष्ट्र शासन

सोबत : परिशिष्ट - १

प्रत:-

१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव
३. मा.मंत्री (आदिवासी विकास) यांचे खाजगी सचिव
४. मा.मंत्री (ग्राम विकास) यांचे खाजगी सचिव
५. मा.राज्यमंत्री (आदिवासी विकास) यांचे खाजगी सचिव
६. मा.राज्यमंत्री (ग्राम विकास) यांचे खाजगी सचिव
७. मा.मुख्य सचिव यांचे उप सचिव
८. प्रधान सचिव (ग्रामविकास विभाग), ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग, बांधकाम भवन, मर्झबान पथ, फोर्ट, मुंबई - ४०० ००१
९. सचिव (वने), मंत्रालय, मुंबई

१०. सर्व विभागीय आयुक्त
११. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय,मुंबई
१२. आयुक्त,आदिवासी विकास आयुक्तालय, नाशिक.
१३. जिल्हाधिकारी, ठाणे, पालघर, नाशिक, नंदुरबार, धुळे, अहमदनगर, जळगाव, अमरावती, यवतमाळ, चंद्रपुर, गडचिरोली, पुणे, नांदेड.
१४. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ठाणे, पालघर, नाशिक, नंदुरबार, धुळे, अहमदनगर, जळगाव, अमरावती, यवतमाळ, चंद्रपुर, गडचिरोली, पुणे, नांदेड.
१५. सर्व उप सचिव, आदिवासी विकास विभाग
१६. अप्पर आयुक्त, आदिवासी विकास, ठाणे, नाशिक, अमरावती, नागपूर.
१७. सर्व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प.
१८. उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रा.पं), ठाणे, पालघर, नाशिक, नंदुरबार, धुळे,अहमदनगर, जळगाव, अमरावती, यवतमाळ, चंद्रपुर, गडचिरोली, पुणे, नांदेड.
१९. गटविकास अधिकारी, पंचायत समिती, ठाणे, पालघर, नाशिक, नंदुरबार, धुळे, अहमदनगर, जळगाव, अमरावती, यवतमाळ, चंद्रपुर, गडचिरोली, पुणे, नांदेड. (जिल्हयातील सर्व पेसा तालुके)
२०. सर्व कार्यासने, आदिवासी विकास विभाग
२१. निवडनस्ती (का. १७)

शासन निर्णय क्रमांक पेसाअ-२०१५/ प्रक्र ९८/ का-१७, दिनांक २१ ऑगस्ट, २०१५ सोबतचे

परिशिष्ट-१

अनुसूचित क्षेत्रातील गावात (पेसा गावात) ग्रामसभेच्या कामकाजा संबधाने ठेवावयाच्या नोंदवहया.

१. ग्रामसभा हजेरीपत्रक
२. ग्रामसभा कार्यवृतांत नोंदवही
३. ग्रामसभा कोष रोकड नोंदवही
४. ग्रामसभा कोष सामान्य पावती
५. गाव मालमत्ता नोंदवही
६. कामाच्या मोजमापाची नोंदवही
७. कामावर लावण्यात आलेल्या मजुरांचा हजेरीपट
८. प्रमाणक (व्हाउचर) नोंदवही
९. वस्तु साठा नोंदवही
१०. आवक जावक नोंदवही

******

राज्यातील अनुसूचित क्षेत्रातील ग्रामपंचायतीना आदिवासी उपयोजनेंतर्गत ५% निधी थेट देण्याबाबत.

महाराष्ट्र शासन
आदिवासी विकास विभाग
शासन निर्णय क्रमांकः पेसा -२०१५ /प्र.क्र.१९/ का. १७
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड
मंत्रालय, विस्तार इमारत, मुंबई-४०० ०३२
दिनांक : **२१ एप्रिल, २०१५**

<u>वाचा</u> : १. शासन अधिसूचना, ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग, मंत्रालय, मुंबई, क्र. पीआरआय-२०१०/प्र.क्र.१३०/पं.रा.-२, दिनांक ४ मार्च, २०१४.

२. मा. राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य यांच्या कार्यालयाची अधिसूचना क्र. आरबी/टीसी/ई-११०१९ (८९) (२०१३)/नोटिफिकेशन-४/११२०/२०१४, दिनांक ३० ऑक्टोबर, २०१४.

<u>प्रस्तावना:</u>

पंचायत (अनुसूचित क्षेत्राचा विस्तार) अधिनियम, १९९६ केंद्र शासनाने दिनांक २४ डिसेंबर, १९९६ रोजी अधिसूचित केला आहे. राज्यामध्ये साधारणत: आदिवासी उपयोजना क्षेत्र, अतिरिक्त आदिवासी उपयोजना क्षेत्रामध्ये १५ जिल्हयातील ६० तालुक्यांमधील ७१७७ गावे व माडा व मिनी माडा क्षेत्रामध्ये १७ जिल्हयांमधील ६७ तालुक्यांतील १२५१ गावांचा समावेश आहे. महाराष्ट्र राज्यात १३ जिल्हयांतील ५९ तालुक्यांतील २८३५ ग्रामपंचायती व ५९०५ गावे पेसा (PESA) क्षेत्रामध्ये येतात. अनुसूचित क्षेत्रातील ग्रामपंचायतींना सक्षम व आर्थिकदृष्टया सबळ करण्याकरिता राज्य शासनाने अनेक योजना राबविलेल्या आहेत. त्यामुळे राज्यातील ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांना देशात एक वेगळे स्थान प्राप्त झाले आहे. मा. राज्यपाल महोदयांनी भारतीय राज्यघटनेच्या अनुसूची ५ मधील परिच्छेद ५, उपपरिच्छेद (१) नुसार प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन दि. ३० ऑक्टोबर, २०१४ अन्वये विविध कायद्यांच्या अनुषंगाने अधिसूचना निर्गमित केली आहे. त्यामध्ये महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम (III) १९५९ मध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे. त्यामधील कलम ५४ B नंतर "be competent to exercise control over local plans and resources for such plan including the Tribal sub-Plan; Provided that not less than ५ % of the total Tribal sub-Plan funds of the respective annual plan shall be devolved to the Gram Panchayat in Scheduled Areas in proportion to their population; Provided further that the Panchayat shall utilize these funds for the purpose and to the extent as recommended by the Gram Sabha. Provided also that in case a Panchayat has more than one Gram Sabha these funds shall be utilized in proportion to the population of the respective Gram Sabhas." कलम अंतर्भूत करण्यात आलेले आहे. त्यानुसार आदिवासी उपयोजनेंतर्गत प्राप्त होणा-या एकूण नियतव्ययाच्या ५ टक्के निधी अनुसूचित क्षेत्रातील ग्रामपंचायतींना त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात वितरित करण्याची तसेच याबाबत मार्गदर्शक तत्वे निश्चित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

शासन निर्णय:-

प्रस्तावनेत नमूद केल्यानुसार मा. राज्यपाल महोदयांच्या संदर्भ क्रमांक २ वरील दिनांक ३० ऑक्टोबर, २०१४ च्या अधिसूचनेनुसार कार्यवाही करण्यासाठी मंत्रिमंडळाच्या दिनांक ९ एप्रिल, २०१५ झालेल्या बैठकीमध्ये निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानुसार राज्यातील अनुसूचित क्षेत्रातील ग्रामपंचायतीना दरवर्षी आदिवासी उपयोजनेच्या नियतव्ययाच्या ५% निधी उपलब्ध करुन देण्याच्या योजनेस (पेसा ग्रामपंचायतींना ५ % थेट निधी योजना) मान्यता देण्यात येत आहे. सन २०१५-१६ या आर्थिक वर्षामध्ये या

योजनेसाठी सुमारे रु.२५० कोटी इतका निधी उपलब्ध होईल. सदरचा निधी खालीलप्रमाणे (अ) पायाभूत सुविधा, (ब) वन हक्क अधिनियम (FRA) व पेसा (PESA) कायद्याची अंमलबजावणी, (क) आरोग्य, स्वच्छता, शिक्षण व (ड) वनीकरण, वन्यजीव संवर्धन, जलसंधारण, वनतळी, वन्यजीव पर्यटन व वन उपजिविका या बाबींकरीता प्रत्येकी १/४ या प्रमाणात विनियोगात आणावा.

<u>(अ) पायाभूत सुविधा :</u>

१. संबंधित पेसा गावातील ग्रामपंचायत कार्यालये, आरोग्य केंद्रे, अंगणवाडया, शाळा, दफनभूमी, गोडाऊन, गावांचे अंतर्गत रस्ते व तत्सम पायाभूत सुविधा,

(ब) वन हक्क अधिनियम (FRA) व पेसा (PESA) कायद्याची अंमलबजावणी:

१. आदिवासींनी त्यांच्या उदरनिर्वाहाच्या व्यवसायाच्या संदर्भात प्रशिक्षण केंद्रांमार्फत प्रशिक्षण/मार्गदर्शन करणे.
२. गावतळी विकास किंवा मत्स्यपालन व्यवसाय / मत्स्यबीज खरेदी.
३. सामाईक जमिनी विकसित करुन देणे.
४. गौण पाणी साठयाचे व्यवस्थापन.
५. सामाईक नैसर्गिक साधनसंपदा व सामाईक मालमत्ता विकसित करणे

(क) आरोग्य, स्वच्छता, शिक्षण:

१. सार्वजनिक स्वच्छतागृहे बांधणे.
२. गावामध्ये स्वच्छता राखणे.
३. सांडपाणी व्यवस्थेकरीता गटारे बांधणे व त्याची देखभाल करणे.
४. शुध्द पिण्याचे पाणी पुरविणे.

(ड) वनीकरण, वन्यजीव संवर्धन, जलसंधारण, वनतळी, वन्यजीव पर्यटन व वन उपजिविका:

संबंधित ग्रामपंचायतीमधील गावांच्या ग्रामसभांनी वरील (अ) व (क) क्षेत्रांमधून त्या-त्या वर्षाकरिता कामाची निवड करावी. ग्रामसभांनी कामाची निवड करणे म्हणजेच त्या कामास ग्रामसभेची प्रशासकीय मान्यता समजावी. ग्रामसभेने निवड केलेल्या रुपये ३ लक्ष पेक्षा कमी मुल्याच्या कामास स्वतंत्र तांत्रिक मान्यता आवश्यक असणार नाही व रु. ३ लक्ष पेक्षा अधिक मूल्य असलेल्या कामासाठी तांत्रिक मान्यता घेण्याची पध्दती परिच्छेद -४(६) प्रमाणे राहील.

मात्र उपरोक्त (ब) व (ड) येथील क्षेत्रामधील त्या-त्या वर्षाकरिता कामाची निवड ग्रामसभेने केल्यानंतर त्याकरिता लागणारा निधी ग्रामसभेची अनुमती घेऊन संबंधित गावांच्या संयुक्त वन व्यवस्थापन समिती, ग्राम वन समिती किंवा सामुहिक वन हक्कांसाठी स्थापन केलेल्या समितीस देण्यात यावा.

सदर योजनेबाबत तपशीलवार मार्गदर्शक सूचना सोबतच्या “परिशिष्ट” मध्ये देण्यात आल्या आहेत.

२. सन २०१५-१६ या आर्थिक वर्षानंतर येणा-या प्रत्येक आर्थिक वर्षामध्ये आदिवासी उपयोजनेच्या एकूण मंजूर नियतव्ययाच्या ५% निधीपैकी ५० % इतका निधी ग्रामपंचायतींना लोकसंख्येच्या प्रमाणात वितरित करण्यात येईल व उर्वरित ५० % निधी ग्रामपंचायतींना त्यांच्या खालील क्षेत्रात केलेल्या कामगिरीच्या आधारे देय राहील :-

अ. अतिकुपोषित बालकांचे प्रमाण कमी करणे,
आ. बालविवाहावर बंदी आणणे,
इ. शिक्षणातील मुलींचे गळतीचे प्रमाण कमी करणे,
ई. वन जमिनीवर नव्याने अतिक्रमण थांबविणे इ.

वरील अ ते ई मध्ये नमूद केलेल्या क्षेत्रातील कामगिरी निश्चित करण्याकरीता खालीलप्रमाणे संबंधित सक्षम अधिका-याचे प्रमाणपत्र आवश्यक राहील :-

१) मध्यम व अतितीव्र कुपोषित बालकांची मागील वर्षातील सुरुवातीला असलेली संख्या व त्या वर्षाच्या ३१ मार्च अखेर असलेली संख्या याबाबतच्या तपशिलासह कुपोषित बालकांचे प्रमाण कमी झाले असल्याचे संबंधित बाल विकास प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक बाल विकास प्रकल्प यांचे प्रमाणपत्र.

२) गेल्या वर्षामध्ये गावात झालेल्या विवाहामध्ये एकही बालविवाह झाला नाही याबाबत संबंधित ग्राम सचिवाचे प्रमाणपत्र.

३) गावातील ५ ते १५ वयोगटातील मुलींची संख्या, त्यातील शाळेत जाणा-या मुलींची इयत्तानिहाय संख्या याबाबतच्या तपशिलासह शिक्षणातील मुलींचे गळतीचे प्रमाण कमी झाले असल्याबाबतचे संबंधित गट शिक्षण अधिका-याचे प्रमाणपत्र.

४) वन जमिनीवर नव्याने अतिक्रमण न झाल्याबाबत संबंधित वन विभागाच्या वन परिक्षेत्र अधिका-याचे प्रमाणपत्र.

वरील अधिका-यांना संबंधित ग्रामपंचायतीने मागणी केल्यानंतर १५ दिवसांत तपासणी करुन वस्तुस्थितीवर आधारीत प्रमाणपत्र देणे बंधनकारक राहील.

३. ग्रामपंचायतीला निधी वितरीत करण्याची पध्दती :

सर्व ग्रामपंचायतीचे बचत खाते क्रमांक व त्या ग्रामपंचायतीतील गावे/वस्ती यांची लोकसंख्या याबाबतची माहिती संबंधित जिल्हा परिषद आदिवासी विकास विभागाला उपलब्ध करुन देईल. सदर माहितीच्या आधारे आदिवासी उपयोजनेचा निधी आदिवासी विकास विभागामार्फत राज्य स्तरावरुन थेट ग्रामपंचायतींना RTGS व्दारे लोकसंख्येच्या प्रमाणात संबंधित ग्रामपंचायतीच्या बँक खात्यामध्ये थेट वितरित करण्यात येईल.

४. निधीच्या विनियोगासाठी वार्षिक आराखडा तसेच प्रशासकीय तांत्रिक मान्यतेची पध्दती :

१. प्रत्येक वर्षी दिनांक १ मे रोजीच्या ग्रामसभेमध्ये निधीच्या विनियोगाचा वार्षिक नियोजनाचा आराखडा निश्चित करण्यात येईल.
२. आराखडा तयार करताना मागील दोन वर्षातील कामांची स्थिती व पुढील वर्षातील गरजा विचारात घेण्यात येतील.
३. ग्राम पंचायतीच्या क्षेत्रातील प्रत्येक गाव व वाडी /पाडानिहाय आराखडा तयार करून त्यानंतर त्यांचे संकलन ग्रामपंचायत स्तरावर करण्यात येईल.
४. ग्रामसभेच्या ठरावानुसार निवड झालेल्या कामास स्वतंत्र प्रशासकीय मान्यता आवश्यक असणार नाही.

५. ग्रामसभेने मान्यता दिलेल्या रु. ३ लक्ष पेक्षा कमी मूल्याच्या कामास स्वतंत्र तांत्रिक मान्यता आवश्यक असणार नाही.
६. रु. ३ लक्ष पेक्षा अधिक मूल्याच्या कामांसाठी तांत्रिक मान्यता गटविकास अधिकारी यांनी ठरवून दिलेल्या तांत्रिक अधिका-यामार्फत देण्यात यावी. तसेच वन विभागाशी निगडित काम असल्यास उप वनसंरक्षक किंवा त्यांनी प्राधिकृत केलेल्या तांत्रिक अधिका-यामार्फत देण्यात यावी.
७. ग्रामस्तरावर घ्यावयाच्या सर्वसाधारण कामांची यादी करून तांत्रिक मान्यता आवश्यक असलेल्या कामांची **यादी-अ** व तांत्रिक मान्यता आवश्यक नसलेल्या कामांची **यादी-ब** सोबत जोडली आहे.

५. या योजनेंतर्गत निधी वितरणाबाबतचे आदेश स्वतंत्रपणे निर्गमित करण्यात येत आहेत.

६. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक:१७७/व्यय-१४, दिनांक १७ एप्रिल, २०१५, ग्राम विकास विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक:२०८/प्र.स.(ग्रा.वि.), दिनांक १२ मार्च, २०१५ व वन विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक: ५५५/प्र.स.(वने), दिनांक १६ मार्च, २०१५ नुसार प्राप्त सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे.

७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१५०४२०१७४३३५५९२४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.

Rajagopal Devara

Digitally signed by Rajagopal Devara
DN: c=IN, o=All India Service, ou=IAS, postalCode=110001, st=Maharashtra, cn=Rajagopal Devara
Date: 2015.04.21 14:58:42 +05'30'

(राजगोपाल देवरा)
सचिव, आदिवासी विकास

प्रत,

१. मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई-३२
२. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई -३२
३. मा. मंत्री/ राज्य मंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव
४. सर्व मा. मंत्री/राज्यमंत्री
५. सर्व विधानसभा / विधान परिषद सदस्य
६. मा. मुख्य सचिव यांचे उपसचिव
७. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र -१/२, मुंबई / नागपूर
८. महालेखापाल (लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र -१/२, मुंबई / नागपूर
९. प्रधान सचिव, ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग, बांधकाम भवन, फोर्ट, मुंबई
१०. प्रधान सचिव, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई - ३२
११. सचिव (वने), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई
१२. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, नागपूर

१३. आयुक्त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे
१४. आयुक्त, आदिवासी विकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक
१५. आयुक्त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे
१६. विभागीय आयुक्त, कोकण / नाशिक/ पुणे/ औरंगाबाद/अमरावती व नागपूर
१७. जिल्हाधिकारी, ठाणे/ पालघर/ नाशिक/धुळे/ नंदूरबार/ जळगांव/ अहमदनगर/ पुणे/ नांदेड/ यवतमाळ/ अमरावती /गडचिरोली व चंद्रपूर
१८. अप्पर आयुक्त, आदिवासी विकास, नागपूर /अमरावती/ नाशिक व ठाणे
१९. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, ठाणे/ पालघर/ नाशिक/धुळे/ नंदूरबार/ जळगांव/ अहमदनगर/ पुणे/ नांदेड/ यवतमाळ/ अमरावती /गडचिरोली व चंद्रपूर
२०. सर्व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालय
२१. सर्व संबंधित गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती
२२. सर्व संबंधित गट शिक्षण अधिकारी
२३. प्रधान सचिव, आदिवासी विकास विभाग यांचे वरीष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई
२४. सर्व उपसचिव, आदिवासी विकास विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई -३२
२५. सर्व संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी
२६. वित्त विभाग, (व्यय १४ / अर्थ १९)मंत्रालय, मुंबई -३२
२७. सर्व मंत्रालयीन विभाग
२८. सर्व कार्यासने, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई -३
२९. कक्ष अधिकारी, का-६, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई - ३२
३०. निवड नस्ती (का.१७)

शासन निर्णय, आदिवासी विकास विभाग क्र. पेसा २०१५/ प्रक्र.१९/ का-१७,

दिनांक २१ एप्रिल, २०१५ चे परिशिष्ट

आदिवासी उपयोजनेंतर्गत प्राप्त होणा-या एकूण नियतव्ययाच्या ५ % निधी अनुसुचित क्षेत्रातील ग्रामपंचायतीनां उपलब्ध करुन देणे, निधीचा विनियोग इत्यादी संदर्भात मार्गदर्शक सूचना.

१.ग्राम पंचायतींना निधी वितरीत करण्याची पद्धती:

१. आदिवासी उपयोजनेतील ५ %निधी ग्राम पंचायतींना अबांधित (Untied) स्वरुपात देण्यात येईल.

२. ग्राम पंचायतींना निधीचे वितरण २०११ च्या जनगणनेच्या लोकसंख्येनुसार करण्यात येईल.

३. ग्राम पंचायतीला निधी वितरीत करताना ग्राम पंचायत क्षेत्रातील प्रत्येक महसुली गाव तसेच वाडी /पाडा याकरिता वापरावयाच्या निधीचे प्रमाण २०११ च्या जनगणनेच्या लोकसंख्येनुसार निश्चित करून देण्यात येईल.

४. सर्व ग्रामपंचायतीचे बचत खाते क्रमांक व त्या ग्रामपंचायतीतील गावे/वस्ती यांची लोकसंख्या याबाबतची माहिती जिल्हा परिषद आदिवासी विकास विभागाला उपलब्ध करुन देईल. सदर माहितीच्या आधारे आदिवासी उपयोजनेचा निधी आदिवासी विकास विभागाकडून राज्य स्तरावरून थेट ग्राम पंचायतींना RTGS द्वारे लोकसंख्येच्या प्रमाणात संबंधित ग्रामपंचायतीच्या बॅक खात्यामध्ये RTGS व्दारे थेट वितरित करण्यात येईल.

५. प्रत्येक ग्राम पंचायतीस सदर निधीसाठी राष्ट्रीयकृत बँकेत स्वतंत्र खाते उघडणे बंधनकारक राहील.

६. रु .पाच लक्षच्या आतील निधी दोन हप्त्यात व त्यापेक्षा जास्त निधी तीन हप्त्यात अदा करण्यात येईल.

२. ग्राम पंचायत स्तरावर निधीचे नियंत्रण व व्यवस्थापन:

१. ग्राम पंचायतीच्या खात्यातून निधी ग्रामसभा कोषामध्ये वर्ग करण्यात येईल.

२. ग्रामसभा कोष समिती प्राप्त निधीचे व्यवस्थापन करेल.

३. निधीच्या विनियोगावर ग्रामसभेचे संपूर्ण नियंत्रण राहील व ग्रामसभेच्या ठरावाशिवाय सदर निधीतून कोणताही खर्च करता येणार नाही.

४. पेसा गावे घोषित होईपर्यंत सदर निधी ग्राम पंचायतीच्या एकत्रित ग्रामसभेच्या नियंत्रणाखाली राहील.

५. पेसा गावे घोषित झाल्यावर प्रत्येक गावासाठी निश्चित केलेल्या निधीचा विनियोग संबंधित गावाची ग्रामसभा ठरवेल.

६. ग्राम पंचायतीला प्राप्त झालेला निधी महसुली गावे, पाडे /वस्त्या यांना निश्चित केलेल्या प्रमाणानुसारच खर्च करणे बंधनकारक राहील.

७. सदर निधीबाबतचे सर्व लेखे हे महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रांवर विस्तारित करण्याबाबत), नियम,२०१४ प्रकरण तीन, ग्रामसभा लेखे मधील नियम क्रमांक १४,१५ व १६ नुसार ठेवावीत.

८. फक्त ज्या ग्रामपंचायती, स्थानिक वन व्यवस्थापन समिती यांचे मागील एक वर्षाचे लेखा परीक्षण, स्थानिक निधी लेखा परीक्षा पथकाकडून झाले नसल्यास त्रयस्थ लेखा परिक्षकाकडून लेखा परीक्षण करुन घेणे बंधनकारक आहे.

९. ज्या ग्रामपंचायतीचे किंवा संयुक्त वन व्यवस्थापन समिती, ग्राम वन समिती किंवा सामुहिक वन हक्कांसाठी स्थापन केलेल्या समितीचे गेल्या वर्षाचे लेखा परीक्षण झालेले नसेल किंवा लेखा परीक्षण अहवालामध्ये प्रतिकूल शेरे असतील तर ते पुढील वर्षाचा निधी मिळण्यास पात्र असणार नाहीत.

१०. कोणत्याही परिस्थितीत मागील एका आर्थिक वर्षाचे लेखा परीक्षण त्रयस्थ लेखा परिक्षकाकडून करण्यात आलेले आहे त्यांनाच हा निधी वितरित करण्यात यावा.

३.निधीच्या विनियोगाचे सूत्र, कालमर्यादा:

१. ग्राम पंचायतीला प्राप्त झालेल्या निधीचा विनियोग खालील सूत्रानुसार करणे बंधनकारक राहील:

अ. पायाभूत सुविधा	: १/४ निधी
ब. पेसा व वनहक्क अंमलबजावणी	: १/४ निधी
क. स्वच्छता, आरोग्य, शिक्षण व अनुषंगिक विषय	: १/४ निधी
ड. वनीकरण, वन्यजीव संवर्धन, जलसंधारण, वनतळी, वन्यजीव पर्यटन व वन उपजिविका	: १/४ निधी

२. उपरोक्त पैकी प्रत्येक वर्षी एका क्षेत्राची निवड करून त्यातील कामे राबविता येतील.

३. पुढील वर्षांमध्ये इतर तीन क्षेत्रातील कामे केल्यावरच पुन्हा पहिल्या क्षेत्रातील काम घेता येईल.

४. प्रत्येक वर्षी प्राप्त निधीचा खर्च पूर्ण करण्यासाठी ग्राम पंचायतीस दोन वर्षे कालावधी उपलब्ध राहील (चालू व पुढील वर्ष).

४. निधीच्या खर्चातील अननुज्ञेय बाबी :

सदर निधीतून खालील बाबींकरिता खर्च करता येणार नाही.

- सदर निधीतून वैयक्तिक लाभ (खालील अपवाद वगळता) देऊ नये:
  - अपंगाना उपकरणे /तत्सम सहाय्य.
  - अल्प व अत्यल्प भूधारकांना शेतजमीन विकास ,जलस्त्रोत विकासासाठी सहाय्य.
- सदर निधीचा वापर करताना आदिवासी उपयोजनेतील नियमित योजना, शासनाच्या विविध विभागांच्या नियमित योजना, जिल्हा वार्षिक योजना, वित्त आयोगाचे अनुदान इत्यादीतील तरतुदींची व कामांची पुनरावृत्ती (Duplication) होणार नाही याची काळजी घ्यावी. तसेच एकाच कामासाठी किंवा कामाच्या वावासाठी अन्य नियमित योजनेमधील निधीचा व या योजनेमधील निधीचा वापर होणार नाही, याची दक्षता घेण्यात यावी.
- ५ %निधीतून प्रत्येक आर्थिक वर्षात होणाऱ्या एकूण खर्चामध्ये बांधकामावरील खर्चाचे प्रमाण ४० %पेक्षा अधिक असू नये.
- रस्त्याची कामे केवळ खालील मर्यादेतच घ्यावीत:
  - ग्राम पंचायत कार्यालय, आरोग्य केंद्र, अंगणवाडी, शाळा, दहन-दफन भूमी व तत्सम पायाभूत सुविधा, गावाचे अंतर्गत रस्ते.
  - वैयक्तिक घरांना जोडणारे रस्ते सदर निधीतून घेऊ नयेत.
- ग्राम पंचायत प्रवेशद्वार अथवा तत्सम निव्वळ सुशोभीकरणाची कामे सदर निधीतून करू नयेत.
- ग्राम पंचायतीच्या कर संकलनाचे उद्दिष्ट)जसे पाणीपट्टी, मालमत्ता कर वसुली (अथवा स्वत:च्या महसुलातून करावयाचा खर्च) जसे वीज बिल अदायगी (यामध्ये कमी पडणारी रक्कम भरून काढण्यासाठी सदर निधीचा वापर करू नये.
- एखाद्या कामातील लाभार्थी हिस्स्याची (Beneficiary Contribution) रक्कम भरण्यासाठी सदर निधीचा विनियोग करू नये.
- कोणतेही सण /समारंभ /धार्मिक विधी यासाठी सदर निधीचा वापर करू नये.
- आदिवासी उप योजनेच्या मूळ तत्वांना अनुसरून, सदर निधीचा वापर सुस्पष्टपणे आदिवासी जनतेच्या कल्याणाकरिता होईल याची दक्षता घ्यावी व कोणत्याही परिस्थितीत इतर कारणासाठी त्याचा अपव्यय होणार नाही याची खबरदारी घ्यावी .

५. निधीच्या खर्चातील अनुज्ञेय बाबी:

- रोजगार विकासाकरीता नाविन्यपूर्ण उपक्रम.
- ग्राम पंचायतीच्या उत्पन्न वाढीसाठीचे उपक्रम.
- सार्वजनिक सुविधा केंद्र ,धान्य गिरणी ,अथवा सार्वजनिक उपयोगाच्या वस्तू /सुविधा.
- मध्यान्य भोजन उपक्रमाचे बळकटीकरण ,वैद्यकीय विशेषज्ञांकडून आरोग्य तपासणी (specialized health check-up), प्रसुतीपूर्व गर्भवती स्त्रियांची काळजी (ANC services), ई-शिक्षण (e-learning) , डिजिटल शाळा ,अशा स्वरूपाचे उपक्रम.
- परिसरातील ग्राम पंचायतींनी एकत्र येऊन स्थानिक परिस्थितीनुसार ठरविलेली कामे जसे सिंचन ,पडकाई , दूरसंचार ,दळण-वळण ,इत्यादी.
- नियमित योजनांतील तरतुदीस पूरक स्वरूपातील कामे जसे -रोजगार हमी ,पाणलोट विकास ,कृषी विकास ,लघु/सूक्ष्म सिंचन ,मत्स्य पालन ,पशु/दुग्ध व्यवसाय ,वनीकरण ,वन व्यवस्थापन ,घन व द्रव कचरा वर्गीकरण व व्यवस्थापन ,इत्यादी योजनांशी मेळ घालून सामुदायिक संसाधनांचे व्यवस्थापन व उपजीविका निर्मितीसाठी घ्यावयाची कामे.
- एका पेक्षा अधिक ग्राम पंचायतींच्या सामायिक प्रस्तावांमध्ये पंचायत समिती /जिल्हा परिषदेने समन्वयाची भूमिका बजावावी तसेच नियमित योजनांतील निधीची जोड देण्याचा प्रयत्न करावा.
- आदिवासी क्षेत्रातील प्रमुख कार्यक्रमांची (Flagship) देखभाल.
- ग्राम पंचायत स्तरावरील विविध पायाभूत सुविधा, अत्यावश्यक सेवा व कर्मचारी याबाबत आदिवासी क्षेत्रासाठी वेगळे निकष नसल्यास अथवा दुर्गम क्षेत्र /विरळ लोकवस्ती यामुळे निकषांपेक्षा अधिक सुविधा / कर्मचारी आवश्यक असल्यास त्यासाठीची तरतूद.
- जिल्हा दर पत्रकानुसार (DSR) जी कामे जिल्हा मुख्यालयापासून जवळ /सपाट प्रदेशात होऊ शकतात परंतु दुर्गम /डोंगराळ आदिवासी क्षेत्रात त्याच दराने होऊ शकत नाहीत (दळण-वळणाचा खर्च, अतिरिक्त मनुष्यबळाचा खर्च, इत्यादीमुळे) त्यासाठी अतिरिक्त खर्चाची तरतूद.
- आदिवासी उपयोजनेतील नियमित योजनांना एकमेकाशी जोडून त्यांना अधिक परिणामकारक बनविण्यासाठी Bridge Funding या स्वरुपातील उपक्रम (उदा.कौशल्य प्रशिक्षण व स्वयंरोजगार कर्ज)
- पेसा कायद्यातील तरतुदींनुसार १०० हेक्टरच्या आतील तलाव, गौण खनिजे व इतर नैसर्गिक /सांस्कृतिक साधन-संपत्तीचे व्यवस्थापन.
- वन हक्क कायद्यातील तरतुदींनुसार सार्वजनिक वन हक्काचे उपक्रम.
- गौण वन उपजावर प्रक्रिया व त्याची विक्री यासाठी पायाभूत सुविधा निर्माण करणे.
- आदिवासी क्षेत्रात ग्राम पंचायतीच्या पुढाकाराने पर्यटन विकासाचे (Ecotourism/ Heritage Tourism) उपक्रम हाती घेऊन त्यायोगे स्थानिक युवक /महिला बचत गट यांना उत्पन्न वाढीचे स्त्रोत निर्माण करणे.
- अशा पर्यटन विकासासाठी वन विभाग तसेच आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे, यांच्या सहाय्याने निसर्ग व संस्कृती माहिती केंद्र (Nature & Culture Interpretation Centres) उभारणे व चालविणे.
- देखभाली अभावी नादुरुस्त झालेल्या सुविधा पुन्हा कार्यान्वित करणे.
- ग्राम पंचायत व ग्राम सभा सक्षम करण्यासाठीचे उपक्रम.

६. ग्रामसभा व ग्राम पंचायातीस तांत्रिक सहाय्याची व्यवस्था:

१. प्रशासकीय व तांत्रिक सहाय्यासाठी व्यक्ती /संस्थांच्या सेवा घेण्याचे अधिकार ग्रामसभेस असतील.

२. ग्राम पंचायतीला प्राप्त होणाऱ्या निधीतील ५ %व्यवस्थापन निधीतून पायाभूत आराखडा, माहिती व्यवस्थापन, तांत्रिक सहाय्य, प्रशासकीय मनुष्यबळ, इत्यादीकरिता खर्च करता येईल.

३. प्रत्येक तालुक्यासाठी स्वयंसेवी संस्था निश्चित करण्यात येतील. स्वयंसेवी संस्थांना ग्रामसभांबरोबर तांत्रिक सहाय्य संस्था म्हणून संलग्न करण्यात येईल .पायाभूत आराखडा तयार करणे, ग्राम सभेस आराखडा सादर करणे, अंमलबजावणीतील तांत्रिक सहाय्य, इत्यादीमध्ये संस्था सहाय्य करतील .
४. ज्या ग्राम पंचायतीमध्ये पर्याप्त मनुष्यबळ उपलब्ध नसेल तेथे पेसा कायद्यातील तरतुदीनुसार गावातील सुयोग्य व्यक्तीस ग्रामसभेचे कामकाज बघण्यासाठी नेमता येईल.
५. पेसा व वनहक्क कायद्यान्वये निश्चित केलेल्या समित्या तसेच इतर गाव स्तरीय समित्या यांची भूमिका निश्चित करून ग्राम सभा त्यांचे सहाय्य घेईल.
६. ग्राम सभेने तांत्रिक सहाय्याची मागणी केल्यास संबंधित प्रशासकीय विभागांचे अभियंता, तांत्रिक व्यक्ती यांनी प्राधान्याने अशा सेवा पुरविणे बंधनकारक असेल.

७. जनजागृती, प्रशिक्षण व क्षमता बांधणी

१. सदर निधीच्या प्रभावी वापरासाठी ग्राम स्तरावरील संचेतन, जनजागृती, क्षमता बांधणी, ग्राम समित्यांचे गठन, तांत्रिक सहाय्य संस्थांची निवड, अभिलेख व्यवस्थापन, लेखा व्यवस्थापन, इत्यादी उपक्रमांसाठी पहिल्या वर्षी विशेष करून तरतूद करण्यात येईल.
२. सदर निधीबाबत सुलभ, बोली भाषेतील माहितीपर पुस्तिका तयार करून एप्रिल महिन्यातील ग्राम सभेत त्याचे वाचन करण्यात येईल.
३. पेसाचे ग्रामसभा स्तरीय प्रशिक्षण स्थानिक पातळीवर आयोजित करण्यात येईल.
४. पंचायत राज दिनाच्या निमित्ताने जनजागृती अभियान आयोजित करण्यात येईल.
५. राज्यातील तीन आदिवासी क्षेत्रांमध्ये आदिवासी पाडा परिषद आयोजित करण्यात येईल.

८. निधीची उपयोगिता, अहवाल, सनियंत्रण व सामाजिक अंकेक्षण :

१. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांचे या निधीवर/कार्यक्रमांवर सनियंत्रण राहील.
२. ग्राम पंचायतीने मागील प्राप्त निधीची उपयोगिता सादर केल्याशिवाय पुढील निधी देय होणार नाही.
३. प्रत्येक ग्राम पंचायतीसाठी एक सनियंत्रण अधिकारी व एक तांत्रिक अधिकारी नेमण्यात येईल जे शक्यतो इतर तालुक्यातील असतील.
४. सनियंत्रण अधिकारी निधीच्या खर्चाची व फलनिष्पत्तीची त्रयस्थ पाहणी करून त्याचा अहवाल संबंधित पंचायत समितीस सादर करतील.
५. ग्राम पंचायतीने केलेली कामे /खर्च यामध्ये गैरव्यवहार आढळून आल्यास पुढील निधी देय होणार नाही.
६. सनियंत्रण अधिकाऱ्याचा अहवाल मान्य नसल्यास ग्राम पंचायतीस उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्राम पंचायत) यांचेकडे अपिल करण्याची संधी असेल.
७. ग्राम पंचायतीने केलेल्या प्रत्येक कामाचे सामाजिक अंकेक्षण करण्यात येईल.
८. सामाजिक अंकेक्षणाचा तपशिल ग्राम पंचायतीच्या रजिस्टरमध्ये नमूद करण्यात येईल तसेच सदरचा तपशिल सुचना फलकावर जाहीर करण्यात येईल.
९. सनियंत्रण अधिकारी सदर रजिस्टरची देखील नियमित पाहणी करतील.
१०. ग्रामसभेमध्ये निधीच्या खर्चास वार्षिक मान्यता घेण्यात येईल.
११. सनियंत्रण अधिकारी सदर ग्रामसभेस उपस्थित राहतील.
१२. महाऑनलाईनच्या मदतीने सदर निधीचे सनियंत्रण करण्यासाठी अभिलेख व लेखा व्यवस्थापनाची ऑनलाईन प्रणाली विकसित करण्यात येईल.
१३. ग्राम सेवक व डेटा ऑपेराटर यांनी संग्राम प्रणाली, प्रियासॉफ्ट, इत्यादीमध्ये सर्व लेखे, अभिलेख, अद्ययावत ठेवणे आवश्यक राहील.

१४. ग्राम पंचायत स्तरावरील कामांच्या भौतिक व आर्थिक अहवालांचे संकलन पंचायत समिती व जिल्हा परिषदेमार्फत करून प्रत्येक जिल्ह्याचा एकत्रित अहवाल दरसाल ग्राम विकास विभागास सादर करण्यात येईल.

१५. ग्राम विकास विभागामार्फत जिल्ह्यांच्या अहवालांचे संकलन करून एकत्रित अहवाल दरवर्षी आदिवासी विकास विभागास सादर करण्यात येईल .

९.ग्राम पंचायतींच्या कामगिरीवर आधारित निधी:

१. प्रथम वर्षी १०० %निधी ग्राम पंचायतींना लोकसंख्येच्या प्रमाणात वितरीत करण्यात येईल.

२. दुसऱ्या वर्षापासून पुढील प्रत्येक वर्षी ५० %निधी ग्राम पंचायतींना त्यांच्या कामगिरीनुसार देय असेल.

३. या करिता खालील प्रकारचे निकष विचारात घेण्यात येतील:

अ. अतिकुपोषित बालकांचे प्रमाण कमी करणे (Reduction in SAM)

आ. बालविवाहावर बंदी आणणे (Reduction in child marriages)

इ. शिक्षणातील मुलींचे गळतीचे प्रमाण कमी करणे (Reduction in drop-out of girls from schools)

ई. वन जमीनीवर नव्याने अतिक्रमण थांबविणे इ. (No fresh encroachment on forest land, etc.)

४. प्रोत्साहन निधी (Incentive Fund) हा खेळत्या स्वरूपाचा राहील व एकाच ग्राम पंचायतीस तो वारंवार देय होणार नाही.

५. प्रोत्साहन निधी (Incentive Fund) करिता ग्राम पंचायतीची कर वसुली उद्दिष्टानुसार असणे आवश्यक राहील.

६. तसेच सदर निधीस ग्राम पंचायतीने काही स्वनिधीची जोड देणे आवश्यक राहील.

१०. सर्वसाधारण बाबी

१. सदर निधीबाबत प्रथम वर्षातील अनुभवाचा विचार करून पुढील वर्षी सुधारित मार्गदर्शक तत्वे तयार करण्यात येतील.

२. ग्राम पंचायतीस दिलेले अनुदान पूरक स्वरूपाचे असल्याने प्रशासकीय विभागांनी त्याकडे नियमित योजनांतील तरतुदीस पर्याय या दृष्टीने पाहू नये.

३. जिल्हाधिकारी यांना आवश्यकतेनुसार संबंधित विभागांच्या तांत्रिक कर्मचाऱ्यांच्या सेवा सदर निधीच्या विनियोगासाठी वर्ग करण्याचे अधिकार असतील.

४. महसुली गावे घोषित करण्याची प्रक्रिया जलद पूर्ण करण्यात यावी.

५. पेसा नियमावलीनुसार पेसा गावे व गाव ग्रामसभा घोषित करण्याची प्रक्रिया जलद पूर्ण करण्यात यावी.

शासन निर्णय, आदिवासी विकास विभाग क्र. पेसा २०१५/ प्रक्र.१९/ का-१७,
दिनांक २१ एप्रिल, २०१५ चे सहपत्र

यादी - अ

तांत्रिक मान्यतेची आवश्यक असलेल्या १० कामांची यादी.

१. सिंमेट नाला बंडीग
२. इमारतीचे बांधकाम, साठवणूकीकरीता खोली बांधणे, अंगणवाडी, समाजमंदिर इ. बांधकाम
३. मोठया गावांकरीता मलनिसा:रण, सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र उभारणे.
४. शेतीकरीता जलसिंचन प्रकल्प
५. सिंमेट कॉक्रिट चे अंतर्गत रस्ते, नाविन्यपूर्ण तंत्रज्ञानाचा वापर करुन रस्ते बांधणे
६. सौरउर्जा निर्मिती संयंत्र
७. शेतीयोग्य जमीन तयार करणे
८. पूरनियंत्रण भिंती बांधणे
९. हिंस्त्र श्वापदांपासून सरंक्षणकरीता भिंत बांधणे
१०.भूमिगत गटारे

****

शासन निर्णय, आदिवासी विकास विभाग क्र. पेसा २०१५/ प्रक्र.१९/ का-१७,
दिनांक २१ एप्रिल, २०१५ चे सहपत्र

यादी -ब

तांत्रिक मान्यतेची आवश्यकता नसलेल्या ३२ कामांची यादी

१. क्षमता बांधणी आणि स्थळ पाहणी
२. गरजू शेतक-यांकरीता शेतीविषयक औजारांचा सामुहिक वापर
३. ई-शिक्षण / डिजीटल शिक्षण प्रणाली
४. स्पर्धा परिक्षाबाबत पुस्तके असलेले सुसज्ज ग्रंथालय
५. सुधारीत बि-बियाणे प्रक्रिया, सेंद्रिय खताचे उत्पादन
६. भूमिहिन कुटुंबाना शेळीपालन
७. आरोग्य तपासणी शिबीर,पशुसंवर्धन तपासणी शिबीर आयोजित करणे
८. बचत गट, युवक व कुमारवयीन मुली यांना कौशल्य विकास प्रशिक्षण
९. सामुहिक विवाह सोहळा
१०. कंपोस्ट खताचे खड्डे, घन कचरा व्यवस्थापन, कचरा गोळा करणे, त्यांची विभागणी करुन खत निर्मिती करणे.
११. चारा निर्मिती
१२. दुधाळ जनावरांपासून दुध व दुग्धजन्य पदार्थाचे उत्पादन,
१३. वनराई बंधारा, शेत तळे
१४. सामाजिक वनीकरण
१५. प्राथमिक शाळेत विद्यार्थ्यांना बसण्यासाठी डेस्क बेंच,शैक्षणिक साहित्य व इतर
१६. अंगणवाडी व शाळेमध्ये प्रसाधनगृहे
१७. आठवडी बाजारामध्ये पुरविण्यात येणा-या सोई-सुविधा
१८. मत्स्यव्यवसाय
१९. अंगणवाडी,शाळा व ग्रामपंचायत कार्यालय आवारात भिंत बांधणे
२०. अंगणवाडीमध्ये किचन शेड उभारणे
२१. सौर ऊर्जेवर आधारीत संयंत्रे उभारणे
२२. जलशुध्दीकरण, जलप्रक्रिया प्रकल्प राबविणे
२३. पिण्याचे पाण्याकरीता कूपनलिका बांधणे
२४. जल मिटर बसविणे
२५. जनजागृती, दंवडी व इतर सूचना ग्रामस्थापर्यंत पोहचविण्याकरीता ध्वनी प्रक्षेपक बसविणे
२६. ग्राम पंचायत व शाळेमध्ये संगणक बसविणे
२७. अंगणवाडीमध्ये शालेय पूर्व साहित्य
२८. ग्रामसभाचे बळकटीकरण, अभिलेख जतन
२९. प्रौढ साक्षरता, निरंतर शिक्षण
३०. आदिवासी समाजाच्या रुढी, परंपरा व संस्कृतीचे जतन
३१. जल तलाव, तळी यांची दुरुस्ती व पाण्याचा अनुकूल वापर
३२. अपंगाकरीता वैयक्तिक लाभाच्या योजना

****

पंचायत विस्तार (अनुसुचित क्षेत्र) अधिनियम, १९९६ (पेसा) अंतर्गत येत असलेल्या अनुसुचित क्षेत्रातील ग्रामपंचायतींना मत्स्यव्यवसाय विभागांमार्फत राबविण्यात येणाऱ्या योजनांचा लाभ देण्याबाबत.

महाराष्ट्र शासन
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग
शासन निर्णय क्रमांकः मत्स्यवि २०१४/प्र.क्र.३५/पदुम १३
५ वा मजला विस्तार, मंत्रालय,
मुंबई- ४०० ०३२
दि.१२ सप्टेंबर, २०१४

<u>वाचा :-</u>

१) कृषि व पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभागाचे जा.क्र. मत्स्यवि २००९/११४५/प्र.क्र.१६१/०९/पदुम १३, दि.२४/०८/२००९
२) कृषि व पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभागाचे जा.क्र. मत्स्यवि २०१०/प्र.क्र.२४७/पदुम १३, दि.२८/०९/२०१०
३) कृषि व पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभागाचे जा.क्र. मत्स्यवि २४१०/५२६/प्र.क्र.१०५/१०/पदुम १३, दि.७/१०/२०१०
४) सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे क्र.ओीया/सी/मत्स्य/नियम पुनर्रचना, दि.१/०९/१९८९

<u>प्रस्तावना</u> :-

पंचायत विस्तार (अनुसुचित क्षेत्र) अधिनियम, १९९६ अंतर्गत येत असलेल्या अनुसुचित क्षेत्रामधील तलावांचे हक्क ग्रामपंचायतींना / जिल्हा परिषदांना हस्तांतरीत करण्यात आलेले आहे. त्यानुसार शासनाच्या दि.२६/०६/२०१४ च्या सुधारीत तलाव ठेका धोरणामध्ये १०० हेक्टर खालील तलावाचे मासेमारी हक्क ग्रामपंचायत / पंचायत समित्यांना हस्तांतरीत केलेले आहे. आदिवासी विकास विभाग पुरस्कृत मत्स्यव्यवसाय विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या अवरुद्ध पाण्यातील मत्स्यसंवर्धन, मासेमारी साधने पुरवठा, मच्छिमार संस्थांचा विकास, मत्स्यबीज केंद्राची स्थापना, मत्स्यसंवर्धन विकास यंत्रणा व केज कल्चर इ. योजना राबविण्यात येते. या योजनांचा लाभ अनुसुचित क्षेत्रातील ग्रामपंचायतींमार्फत राबवण्याची बाब मच्छिमारांना/ मच्छिमार संस्थांना देण्याबाबतची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुसार खालीलप्रमाणे धोरण निश्चित करण्यात येत आहे

शासन निर्णय:-

१) सदर योजना पंचायत विस्तार (अनुसुचित क्षेत्र) अधिनियम, १९९६ अंतर्गत येत असलेल्या अनुसुचित क्षेत्रातील ग्रामपंचायतीमार्फत राबविण्यात याव्या. सदर योजनेचे लाभार्थी संबंधित ग्रामपंचायत राहील.

२) सदर योजना अनुसुचित क्षेत्रामधील ग्रामपंचायतीमार्फत राबवितांना त्यामधील इतर तरतुदी कायम राहतील.

३) सदर योजना राबविण्याचे अधिकार ग्रामपंचायतींना राहतील. अशा योजना राबवितांना ग्रामसभेचा ठराव घेणे बंधनकारक राहील.

४) सदर योजना राबविण्याबाबत ग्रामसभेमध्ये घेतलेल्या निर्णयानुसार ठरावासह प्रस्तावास संबंधित ग्रामसचिव यांनी संबंधित, सहायक आयुक्त, मत्स्यव्यवसाय, यांची तांत्रिक मान्यता व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांची प्रशासकीय मान्यता घेण्यात यावी.

५) योजना निहाय मान्यता प्राप्त प्रस्तावाच्या अनुषंगाने सहायक आयुक्त, मत्स्यव्यवसाय यांचेमार्फत निधीची मागणी जिल्हा नियोजन समितीकडे करावी.

६) सदर योजनांसाठी निधी/ अनुदान सहायक आयुक्त, मत्स्यव्यवसाय यांनी संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांचे मार्फत संबंधित ग्रामपंचायतींकडे हस्तांतरीत करावे.

७) योजना निहाय निधीचे उपयोगिता प्रमाणपत्र संबंधित ग्रामपंचायत यांनी सहायक आयुक्त, मत्स्यव्यवसाय यांना सादर करावे. त्याची एक प्रत मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांचेमार्फत शासनास सादर करणे बंधनकारक राहील. ग्रामपंचायत यांनी उपयोगीता प्रमाणपत्र ग्रामसभेची मान्यता घेऊन सादर करावे.

८) योजना निहाय प्राप्त मागील निधी उपयोगिता प्रमाणपत्र दिल्याशिवाय सहायक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय यांना पुढील निधी/ अनुदान वितरीत करता येणार नाही.

९) सदर योजना राबवितांना तांत्रिक अडचणी उद्‌भवल्यास संबंधितांनी जिल्हयाचे सहायक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय यांचे तांत्रिक सहाय प्राप्त करुन घेता येईल.

१०) सदर योजनांच्या माध्यमातून होणाऱ्या आर्थिक फायद्याची विभागणी संबंधित ग्रामपंचायतीने ग्रामसभेमध्ये ठरवावी.

११) ग्रामपंचायतीने आर्थिक फायद्याचा वापर ग्रामपंचायतीच्या क्षेत्रातील तलावाच्या विकासासाठी तसेच ग्रामपंचायतीच्या विकासासाठी करावा.

१२) सदर योजनेची अंमलबजावणी करातांना केंद्र शासनाच्या मूळ तत्वाचे उल्लंघन होणार नाही, याची दक्षता संबंधित प्राधिकारी यांनी घ्यावी.

१३) सदर योजनांपैकी काही योजना राबविण्यापूर्वी आयुक्त, मत्स्यव्यवसाय / शासनाच्या सहमतीची आवश्यकता असल्यास त्याप्रमाणे संबंधित ग्रामपंचायतीने मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या मार्फत सहमती घ्यावी.

१४) सदर योजनांचे पुरस्कर्ता प्राधिकारी आदिवासी विकास विभाग राहील, नियंत्रण प्राधिकारी मत्स्यव्यवसाय विभाग राहील व अंमलबजावणी प्राधिकारी ग्रामविकास विभाग राहील.

सदर शासन निर्णय आदिवासी विकास विभाग, ग्रामविकास विभाग यांच्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे.

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१४०९१६१६३१०४६१०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.

Sathe Shashank M

Digitally signed by Sathe Shashank M
DN: c=IN, o=Government of Maharashtra, ou=Agri & ADF, postalCode=400032, st=Maharashtra, cn=Sathe Shashank M
Date: 2014.09.16 16:26:42 +05'30'

(श.मा. साठे)

उप सचिव, महाराष्ट्र शासन

प्रत,

१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव

२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव

३. मा.उपमुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव

४. सर्व मा.मंत्री / राज्यमंत्री यांच खाजगी सचिव

५. मा.मुख्यसचिव, महाराष्ट्र राज्य

६. अप्पर मुख्य सचिव (महसूल), मंत्रालय, मुंबई-३२

७. प्रधान सचिव (वित्त), मंत्रालय, मुंबई-३२

८. प्रधान सचिव (वने), मंत्रालय, मुंबई-३२

९. प्रधान सचिव (ग्रामविकास), मंत्रालय, मुंबई-३२

१०.प्रधान सचिव (आदिवासी विकास), मंत्रालय, मुंबई-३२

११.प्रधान सचिव (सामाजिक न्याय), मंत्रालय, मुंबई-३२

१२.सचिव (सहकार), मंत्रालय, मुंबई-३२

१३.सचिव (जलसंपदा), मंत्रालय, मुंबई-३२

१४.सचिव (लाक्षेवि), मंत्रालय, मुंबई-३२

१५.आयुक्त मत्स्यव्यवसाय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई

१६.आयुक्त सहकार, पुणे

१७.सर्व विभागीय आयुक्त

१८. सर्व जिल्हाधिकारी

१९.सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद

२०.व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र मत्स्योद्योग विकास महामंडळ, मुंबई

२१.सर्व आयुक्त, महानगरपालिका

२२.सर्व गटविकास अधिकारी

२३.सर्व सहायक आयुक्त, मत्स्यव्यवसाय

२४.सर्व उपायुक्त, मत्स्यव्यवसाय

२५.महालेखापाल (लेखापरिक्षा / लेखाअनुज्ञेयता), मुंबई/ नागपूर

२६.वित्त विभाग (व्यय-२), मंत्रालय, मुंबई-३२

२७.कृषि व पदुम विभागातील सर्व कार्यासने

२८. निवडनस्ती

पंचायत विस्तार (अनुसूचित क्षेत्र) अधिनियम, १९९६ (पेसा) अंतर्गत येत असलेल्या अनुसुचित क्षेत्रातील ग्रामपंचायतींना मत्स्यव्यवसाय विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या योजनांचा लाभ देण्याबाबत.

महाराष्ट्र शासन
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग,
शासन शुद्धीपत्रक क्र.मत्स्यवि २०१४/प्र.क्र.३५/पदुम १३
मंत्रालय विस्तार, मुंबई - ४०००३२
दि.२० ऑक्टोबर, २०१४

वाचा :- कृषि व पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभागाचा शासन निर्णय क्र.मत्स्यवि २०१४/प्र.क्र.३५/पदुम १३, दि.१२/०९/२०१४

शासन शुद्धीपत्रक :-

उपरोक्त शासन निर्णयामधील मुद्दा क्र. १२ हा "सदर योजनेची अंमलबजावणी करतांना केंद्र शासनाच्या मूळ तत्त्वाचे उल्लंघन होणार नाही याची दक्षता संबंधित प्राधिकारी यांनी घ्यावी" असा असून यापुढे त्याऐवजी "सदर योजनेची अंमलबजावणी करतांना केंद्र शासनाच्या मूळ तत्त्वाचे उल्लंघन होणार नाही. तसेच, सदर योजनेचा लाभ आदिवासी क्षेत्रातील आदिवासी मच्छिमारांना/ मच्छिमार संस्थांना प्राधान्य देण्याबाबतची दक्षता संबंधित प्राधिकारी यांनी घ्यावी," असे वाचावे.

९५९०

जिल्हाधिकारी
अहमदनगर
६६४१/१४
ग्रा.प.
10 DEC 2014
शाखा
नि.स.प्र./नि.उ.जि./उ.जि.(मह.)
अपर जिल्हाधिकारी/जिल्हाधिकारी

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने,

(प.श.अहमद)
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन

१. प्रति,
२. मा.राज्यपाल यांचे सचिव
३. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव
४. मा.उपमुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव
५. सर्व मा.मंत्री / राज्यमंत्री यांच खाजगी सचिव
६. मा.मुख्यसचिव, महाराष्ट्र राज्य
७. अप्पर मुख्य सचिव (महसूल), मंत्रालय, मुंबई-३२
८. प्रधान सचिव (वित्त), मंत्रालय, मुंबई-३२
९. प्रधान सचिव (वने), मंत्रालय, मुंबई-३२

जिल्हाधिकारी यांची ग्रामपंचायत शाखा
दिनांक 16/12/2014

C:\Users\ashwini.mhatre\Desktop\Smita-ADF13\GR.docx

अनुसुचित उपक्षेत्रातील लहान तलावांमधील मासेमारीचे अधिकार ग्रामपंचायतीला सुपूर्द करणेबाबत.

महाराष्ट्र शासन
ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग,
शासन निर्णय, क्रमांक:संकिर्ण-२०१४/प्र.क्र.१९४ /पंरा-२
बांधकाम भवन, २५, मर्झबान पथ,
फोर्ट, मुंबई - ४०० ००१
दिनांक:-२-८ ,२०१४

प्रस्तावना:-

राज्यातील ग्रामपंचायती सक्षम करण्यासाठी महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमात सुधारणा करुन ग्रामपंचायतींना /ग्रामसभांना विशेष अधिकार देण्यात आलेले आहेत. त्यास अनुसरुनच ग्रामपंचायतींना कोणताही महत्वाचा निर्णय घेण्यापूर्वी ग्रामसभेची मान्यता घेणे आवश्यक करण्यात आलेले आहे.

आदिवासी भागातील अनुसुचित उपक्षेत्रातील तलावांचा विकास होण्याच्या दृष्टीने १०० हेक्टर खाली तलावांचे मासेमारीचे हक्क ग्रामपंचायतीकडे सोपविण्याची बाब विचाराधीन होती.ही बाब विचारात घेऊन शासनाने आता पुढील प्रमाणे निर्णय घेतला आहे.

शासन निर्णय —

१. पंचायत विस्तार अधिनियम, १९९६अंतर्गत समाविष्ट अनुसुचित क्षेत्रातील १०० हेक्टर खालील लहान तलावांनमध्ये मासेमारी करण्यासाठी संबंधित ग्रामपंचायतींना हस्तांतरीत करण्यात यावेत.

२. ग्रामपंचायतींने ग्रामसभेच्या मान्यतेनुसार सदर तलावांचे हक्क मासेमारी करिता स्वत:कडे ठेवावेत किंवा जाहीर लिलाव पध्दतीने देण्यात यावेत.

३. ग्रामपंचायतींच्या हद्दीतील स्थानिक पारंपारिक मच्छीमार यांचे हक्क ग्रामसभेमध्ये ठराव घेऊन अबाधीत ठेवण्यात यावेत व त्यांना मासिक परवाना देऊन मासेमारी करण्यास मुभा देण्यात यावी.त्यांनी पकडलेली मासळी तलाव ठेकेदारांना विक्री करण्यात यावी.

४. तलाव ठेका किंमत ठरवितांना शासन निर्णय क्र.मत्सवि १२१३/प्र.क्र.४८/पदुम-१३/ दि.२२.१०.२०१३ व शुध्दीपत्रक ५.१२.२०१३ परिच्छेद क्र १२ अन्वये न्युनतम तलाव ठेका रक्कम ठरविण्यात यावी.अधिकतम तलाव ठेका रक्कम ठरविण्याबाबत ग्रामसभेत निर्णय घेण्यात यावा.

५. मत्स्यव्यवसाय विभाग शासन शुध्दीपत्रक दि.५.१२.२०१२ अनुक्रमांक १२ नुसार तलावांमध्ये इष्टतम मत्स्यबीज साठवणुक करणे आवश्यक आहे.

६. मासेविक्रीतुन / तलाव ठेकयातुन मिळणारी रक्कम / मासेमारी परवाना देण्यातुन मिळणारी रक्कम इत्यादी ग्रामपंचायतीने याबाबतचा लेखाजोखा ठेऊन ग्रामनिधीमध्ये ठेवण्यात यावा.

७. शासकिय योजनेतुन मत्स्यव्यवसाया करिता आलेले अनुदान ग्रामनिधीमध्ये ठेवुन त्याचे लेखेजोखे स्वतंत्र ठेवण्यात यावेत.वरिल सर्व व्यवहार ग्रामसभेची मान्यता घेऊन करणे आवश्यक राहील.

८. तलाव ठेका देणे व मास संवर्धन करण्या संदर्भात तांत्रिक सहाय्य मिळण्यासाठी ग्रामपंचायतींना मत्स्यव्यवसाय विभागाकडे मागणी करण्याचे अधिकार राहतील.सर्व

मत्स्यसंवर्धनाचे निकष पाळण्यात यावेत.व त्याची जबाबदारी ग्रामपंचायत व ग्रामसभा यांची राहील.

९. जेव्हा एकापेक्षा जास्त ग्रामपंचायत हद्दीमध्ये तलाव येत असेल अशा वेळी सर्व तलाव ठेक्याने देण्याची कार्यवाही पंचायत समितीने करावी.तथापी संबंधित तलाव ठेक्यात निव्वळ उत्पन्नाच्या ५०% वाटा हा संबंधित ग्रामपंचायतीमध्ये समप्रमाणात वाटप करण्यात यावा.व उर्वरीत ५०% वाटा पंचायत समितीस त्यांचा मोबदला देण्यात यावा.यामोबदल्यात पंचायत समितीने भारांकित तलावांचे देखभाल व दुरुस्तीची कामे करून घ्यावी.

१०. तलाव ठेका कालावधी वर्ष १ जुलै ते ३० जून असे राहील.तलाव ठेका देण्याची मुदत ५ वर्ष राहील.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

(डॉ.नरेश गीते)
उपसचिव,महाराष्ट्र शासन

प्रत:-
१. मा.राज्यपाल महोदयांचे सचिव
२. मा.मंत्री (ग्रा.वि. व पं.रा) यांचे खाजगी सचिव
३. मा.मंत्री (आदिवासी विकास) यांचे खाजगी सचिव
४. मा.राज्यमंत्री (ग्रा.वि. व पं.रा) यांचे खाजगी सचिव
५. मा.सर्व विधानसभा / विधान परिषद सदस्य
६. मा.मुख्य सचिव यांचे वरिष्ठ सहाय्यक, मंत्रालय , मुंबई -३२
७. प्रधान सचिव ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग (जलसंधारण), मंत्रालय, मुंबई -३२
८. प्रधान सचिव आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय , मुंबई -३२
९. सचिव ,कृषी व पदुम (मत्स्यव्यवसाय), मंत्रालय , मुंबई -३२
१०. मा.विभागीय आयुक्त सर्व
११. मा.संचालक,यशदा,पुणे.
१२. सर्व संबंधित जिल्हाधिकारी
ठाणे, नाशिक, धुळे,नंदुरबार, जळगाव, अहमदनगर, पुणे, चंद्रपूर, अमरावती, यवतमाळ, नांदेड, गडचिरोली
१३. सर्व संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी
ठाणे, नाशिक, धुळे,नंदुरबार, जळगाव, अहमदनगर, पुणे, चंद्रपूर, अमरावती, यवतमाळ, नांदेड, गडचिरोली
१४. सर्व संबंधित उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रामपंचायत)
ठाणे, नाशिक, धुळे,नंदुरबार, जळगाव, अहमदनगर, पुणे, चंद्रपूर, अमरावती, यवतमाळ, नांदेड, गडचिरोली
१५. सर्व संबंधित गटविकास अधिकारी
ठाणे, नाशिक, धुळे,नंदुरबार, जळगाव, अहमदनगर, पुणे, चंद्रपूर, अमरावती, यवतमाळ, नांदेड, गडचिरोली

महाराष्ट्र शासन

सहाय्यक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय (तांत्रिक),अहमदनगर यांचे कार्यालय,
पहीला मजला, पराग बिल्डींग, जिल्हाधिकारी कार्यालयाजवळ, अहमदनगर-४१४००१.
दुरध्वनी क्रमांक-(का)-०२४१-२३२३३८३ (ई-मेल) acfnagar@gmail.com

जा.क्र.सआमअ/तां./ ११९३ /२०१४ दिनांक :- २७/११/२०१४

प्रति,
मा.प्रादेशिक उपआयुक्त मत्स्यव्यवसाय,
नाशिक विभाग, नाशिक.

विषयः- पेसा कायदा १९९६ अंतर्गत आदिवासी अनुसुचित क्षेत्रातील तलावांसाठी प्रस्ताव सादर करणेबाबत.

संदर्भ :- १) या कार्यालयाचे जा.क्र. सआम/ अनगर /आस्था/१०२२/२०१४ दि. १३/१०/२०१४
२) आपले पत्र जा. क्र.प्राउआमना/तां/२२९९/२०१४ दि.५/११/२०१४

महोदय,

उपरोक्त विषयी अहमदनगर जिल्हयातील पेसा कायदा १९९६ अंतर्गत आदिवासी अनुसुचित क्षेत्रातील ८ पाटबंधारे तलावाचे मासेमारी हक्क संबंधित ग्रमापंचायतींना हस्तांरीत करण्यात आलेले आहेत. या कार्यालयाचे वरील संदर्भ पत्र क्र.१ नुसार अ.नगर जिल्हयातील आदिवासी अनुसुचित क्षेत्रातील तलावांसाठी गांवनिहाय प्रस्ताव सादर करण्यात आलेला होता. तथापि, आपले संदर्भ-२ चे पत्रान्वये निर्देशित केल्यानुसार नाशिक जिल्हयाने सादर केल्याच्या धर्तीवर पेसा कायदा शा.नि. दिनांक १२.०९.२०१४ च्या तरतुदीस आधिन राहुन योजना प्रस्तावित करण्यात येत आहे.

अनुसुचित क्षेत्रांतर्गत येणा-या तलावांमधील मत्स्यसंवर्धन ग्रामसभेच्या माध्यमातुन घेण्यात येत असलेल्या पाटबंधारे तलावातुन मत्स्योत्पादन वाढीसाठी व ग्रामसभेस उत्पन्न वाढ घेण्यासाठी बीज भांडवल म्हणुन ग्रामसभांना एकवेळचे अर्थसहाय उपलब्ध करुन देणेसंबंधी योजना प्रस्तावित करण्यात येत आहे. सविस्तर प्रस्ताव सोबत पुढील आवश्यक त्या कार्यवाहीस्तव सादर करण्यात येत आहे.
सहपत्रे-३

आपला,

सहाय्यक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय, (तां)
% अहमदनगर

D:\Technical\PESA Act.docx/२/ २६/११/२०१४

" ग्रामसभांना मत्स्योत्पादन वाढीसाठी बीजभांडवल म्हणुन एकवेळचे अर्थसहाय्य"

प्रस्तावना:-

जिल्हयातील पंचायत क्षेत्र विस्तार कायदा -१९९६ (पेसा) आणि अनुसुचित जमाती असलेल्या ग्रामसभेचे सक्षमीकरण करणेसाठी उपलब्ध पाटबंधारे तलावातुन मत्स्यसंवर्धन करुन त्यापासुन मत्स्योत्पादन व उत्पन्न वाढ घेण्यासाठी या योजनाअंतर्गत बीजभांडवल म्हणुन ग्रामसभांना एक वेळचे अर्थसहाय्य उपलब्ध करुन देण्याची योजना प्रस्तावित करण्यात येत आहे.

सदर योजेनेचे सविस्तर निकष खालीलप्रमाणे देण्यात येत आहे.

१) योजनेची व्याप्ती :-

पेसा अंतर्गत अनुसुचित जमाती असलेल्या ग्रामसभांना मासेमारी हक्क हस्तांतरीत करण्यात आलेल्या तलावांचा वापर मत्स्यसंवर्धनासाठी करण्यात येत आहे. किंवा वापरले जाणार आहेत, अशा गावांच्या ग्रामसभेला या योजनेअंतर्गत अनुदान उपलब्ध करुन देण्यात येईल.

२) बीज भांडवालाची गरज :-

ग्रामसभा क्षेत्रात असलेल्या नैसर्गिक साधन संपत्तीच्या सुयोग्य वापर करणेसाठी व नैसर्गिक साधन संपत्तीच्या सुयोग्य वापर करणेसाठी व उंत्पन्न वाढीसाठी ग्रामसभेला खेळत्या भांडवलाची गरज असते . खेळत्या भांडवलाच्या अभावी ग्रामसभांना / अनुसुचित समुहाला उपलब्ध स्त्रोत विकसीत करणे शक्य होत नाही म्हणुन मत्स्योत्पादन / उत्पन्न वाढीसाठी बीज भांडवलाची गरज आहे.

३) योजनेची कार्यपध्दती:-

१) या योजनेअंतर्गत ज्या गावांना लाभ दयावयाचा आहे अशा गावांतील ग्रामसभांनी या लघु पाणीसाठयातील मत्स्यसंवर्धन / प्रकल्प आराखडा तयार करुन सविस्तर प्रस्ताव सादर करावा.

२) ग्रामसभेच्या माध्यमातुन तलावात मत्स्यव्यवसाय विकसित करण्यात येणा-या ग्रामसभांना अर्थसहाय्य अनुज्ञेय असेल.

३) प्रस्तावासोबत ग्रामसभेच्या निव्वळ नफ्याच्या भाग शासनाकडुन मिळणा-या अर्थसहाय्यातुन उभारलेल्या बीज भांडवलात जमा करण्याची तयारी असल्याचा ग्रामसभेचा ठराव जोडणे आवश्यक आहे.

४) या कार्यालयास प्राप्त प्रस्ताव निधी उपलब्धतेनुसार व्यवहार्यता तपासुन कोणत्या ग्रामसभांना अर्थसहाय्य मंजुर करावे याबाबत निर्णय घेतील.

५)ज्या ग्रामसभांना लाभ देण्याचे निश्चित केले आहे. त्या ग्रामसभेच्या पातळीवर एक बचत खाते उघडावे . त्यात ग्रामसभेने नामनिर्देशित केलेला एक मत्स्यव्यवसायिक सदस्य हे सह-स्वाक्षरीकर्ते असतील.

६)बीजभांडवलाची रक्कम ग्रामसभेच्या कोषामध्ये जमा करण्यात यावी.

७) मत्स्योत्पादन वाढीसाठी बीजभांडवल हे एकदाच देय अर्थसहाय्य ग्रामसभेला देण्यात येणार असल्याने मत्स्यबीज साठवणुक , होडी खरेदी जाळे खरेदी, तलाव व्यवस्थापन इ. विविध बाबीसाठी खर्चा करता आलेल्या रक्कमेतुन. मिळालेले उत्पन्न हे दरवर्षी पुनश्च : त्या खात्यात जमा करणे बंधनकारक राहील .तसेच मासेमारीच्या व्यवसायातुन मिळालेल्या निव्वळ नफ्यातील ५०% रक्कम बचत खाते किंवा ग्रमकोसामध्ये जमा कारणे आवश्यक राहील. जेणेकरुन ग्रामसभेच्या कोषात भर पडेल याबाबतच्या त्रैमासिक अहवाल संबंधित ग्रामपंचायतीने गट विकास अधिकारी, यांचेमार्फत जिल्हाधिकारी , मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि.प., प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक

आदिवासी विकास प्रकल्प व सहाय्यक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय,(तां) अहमदनगर या कार्यालयाना सादर करावा लागेल.

४) योजनेअंतर्गत देण्यात येणा-या अर्थसहाय्याचा वापर कसा करावा:-

योजनेअंतर्गत मत्स्यसंवर्धनासाठी देण्यात येणा-या अर्थसहाय्याचा वापर खालील बाबीसाठी अनुज्ञेय असेल.

१) मत्स्यबीज खरेदी करण्यासाठी येणारा खर्च

२) मासेमारीसाठी बिगर यांत्रिकी पत्र्याची लाकडी नौका

३) ओढप जाळयाची खरेदी,

४) नायलॉन केज हाप्पा.

५) मासेवाढीसाठी निविष्ठा खर्च

६) तलाव व्यवस्थापन खर्च (वेतनासह)

७) निविदा खर्च/ आकस्मिक खर्च

५) गावांची निवड:-

अहमदनगर जिल्हयातील पेसा अंतर्गत अनुसुचित क्षेत्रातील गावांनाच ही योजना लागु राहील तसेच निधी उपलब्धता विचारात घेऊन या योजनेअंतर्गत गावांची निवड करण्यात येईल. या योजनेअंतर्गत गावांना लाभ देत असताना प्रथम प्रस्तावास प्रथम प्राधान्य या पध्दतीने एक वेळचे अर्थसहाय्य मंजुर करण्यात येईल.

६) योजनेअंर्गत अनुज्ञेय अर्थसहाय्य :-

मत्स्यसंवर्धनासाठी देण्यात येणारे अर्थसहाय्य प्रति ग्रामसभा प्रकल्प आराखडयानुसार रु.३.५० लक्ष अनुज्ञेय राहील.

योजनेची फलनिश्चिती:-

पेसा अंतर्गत आदिवासी बहुल लोकसंख्या असल्याने ,या भागाचा विकास करतांना साधन संपत्तीचा पुरेपुर वापर करणे गरजेचे आहे. गावातील नैसर्गिक साधन संपत्तीचा स्त्रोत असलेला लघु पाणीसाठयातील मत्स्यसंवर्धनासाठी बीजभांडवल उपलब्ध करुन दिल्यास त्यापासुन मिळणारे उत्पन्न वाढीमुळे गावातील जनतेचे राहणीमान उंचावण्यास मदत होणार असुन, ग्रामसभेस महसुल / उत्पन्नवाढ होवुन जिल्हयाच्या उत्पादकतेत भर पाडण्यास मदत होईल. उपलब्ध नैसर्गिक तलाव क्षेत्र मत्स्यसंवर्धनाखाली येवुन ते विकसित होतील.

७) योजनेचे मुल्यमापन:-

लघु पाणीसाठयातील मत्स्यसंवर्धनाकरिता बीजभांडवल अर्थसहाय्य दिल्यानंतर. संबंधित ग्रामसभेने अर्थसहाय्याचा उपयोग /विनियोग कशाप्रकारे केला, तसेच योजना कार्यान्वयन पध्दतीचे एक वर्षाने मुल्यमापन करण्यात येईल. हे मुल्यमापन संबंधित गट विकास अधिकारी, यांचे मार्फत संयुक्तपणे करण्यात येईल.

सहाय्यक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय, (तां)
अहमदनगर

D:\Technical\PESA Act.docx/२ २६/११/२०१४
पवार

योजनेचा प्रकल्प आराखडा

(रुपये लाखात)

अ.क्र.	योजना	परिमाण	संख्या	दर (रु. प्रतिनग	एकुण किंमत
१)	जिल्हयात ग्रामपंचायतकडे ८ तलावांचे पेसा अंतर्गत मासेमारी हक्क हस्तांतरीत करण्यात आलेले एकुण तलाव-८ प्रति तलाव मत्स्य बोटुकली संचयन १.०० लक्ष	मत्स्यबोटुकली लाखात	८	१/-	८.००
२)	बिगर यांत्रिक पत्र्याची लाकडी नौका- १७X६.२५X२.५० फुट	नौका	८	०.५०	४.००
३)	ओढप जाळ- १०० किलो वजनाचे	किलो	१००	५००	०.५०
	२० मि. मी. ४ किलोची पट्टी (१० पट्टी X४)	किलो	४०	५००	०.२०
	मध्यभागी खोळ	किलो	१०	५००	०.०५
	फ्लोट १ पट्टी X १२ फ्लोट = १० X १२=१२०	नग	१२०	१००	०.१२
	दोरखंड (१६ ते १८ मि. मी.)	किलो	१०	२००	०.०२
	शिलाई १ पट्टीकरीता २ किलो दोरा	किलो	२०	३००	०.०६
	मजुरी १ पट्टी X५००	नग	१०	५००	०.०५
	एकुण १ ओढप जाळे किंमत	--	--	--	१.००
	एकुण ८ तलावा करीता खर्च	नग	८	१०००००/-	८.००
४)	नायलॉन केज हाप्या ६ मी. X५ मी. X५मी (२ नग X८ तलाव)	नग	१६	१००००/-	१.६०
५)	निविष्ठा खर्च प्रति तलाव ५००० किलो X ८ तलाव	किलो	४००००	१०	४.००
६)	व्यवस्थापन खर्च ,प्रति तलाव प्रकल्प खर्चाच्या १० %	तलाव संख्या	८	३००००	२.४०
	एकुण १+२+३+४+५+६	--	--	--	२८ .००

सहाय्यक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय, (तां)
अहमदनगर

D:\Technical\PESA Act.docx/२ २६/११/२०१४
पवार